Follow us on: @TheDailyPioneer facebook.com/dailypioneer instagram.com/dailypioneer/

RNI NO.UPHIN/2010/36547
वर्ष 15 अंक 55
लखनऊ, बृहस्पतिवार, 12 दिसम्बर 2024
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
लखनऊ, नगर संस्करण

Established 1865

पायनियर

लखनऊ, नई दिल्ली और रायपुर से प्रकाशित

www.dailypioneer.com

आभ्यन्तर

राष्ट्रीय-10

मोदी सरकार ने सरकारी बैंकों को निजी फाइनेंसर में तब्दील कर दिया

नोकझोंक के चलते नहीं चली संसद

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

संसद बुधवार को लगातार ग्यारहवें दिन भी राजनीतिक दलों के लिए युद्ध का मैदान बनी रही, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए और आरोप लगाया कि दोनों में से कोई भी शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलने नहीं दे रहा है। लोकसभा में रेलवे कानून में संशोधन के लिए विधेयक पारित होने के बाद सत्ता पक्ष के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की पार्टियां कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी इंडिया ब्लॉक के मुकाबले में बराबरी से लोकसभा और राज्यसभा में नारेबाजी की जिससे दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित हुई और इसके चलते दिन भर के कार्यवाही स्थगित कर दी गई। स्थगन के तुरंत बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया ब्लॉक और भाजपा ने शीतकालीन सत्र के ठीक से न चलने पर चिंता जताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

25 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह में विपक्षी सदस्यों द्वारा उद्योगपति गौतम अडाणी के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की अदालत में अभियोग और संभल हिंसा जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग के कारण संसद की कार्यवाही नहीं हो सकी और पिछले सप्ताह से सत्तारूढ़ भाजपा के सांसद सोरोस और कांग्रेस के बीच कथित सांठगांठ का मुद्दा उठा रहे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।

कई विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के 'पक्षपातपूर्ण' आचरण का आरोप लगाया, उन्हें उपाध्यक्ष के पद से हटाने के लिए नोटिस दिया और उन पर सदन में 'सबसे बड़ा व्यवधान' डालने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके आचरण ने देश की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस धनखड़ को 'बदनाम' करने और जाट समुदाय का 'अपमान' करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि संसद के ऊपरी सदन में नियमों पर राजनीति हावी हो गई है और उन्होंने कहा कि सभापति का आचरण उनके उच्च पद की गरिमा के विपरीत है। संसद परिसर में विपक्ष के कई सांसदों ने एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में लाल गुलाब लेकर भाजपा सांसदों का स्वागत किया। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी से सदन की कार्यवाही सुनिश्चित करने और अडाणी मामले सहित सभी मुद्दों पर चर्चा करने का आग्रह किया। अडाणी मुद्दे पर कांग्रेस के नेतृत्व में हो रहे असामान्य दैनिक प्रदर्शनों की श्रृंखला में यह नवीनतम है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी कार्ड के रूप में तिरंगा भेंट किया, जब वे मुख्य संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे। राहुल ने स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात की और उनसे भाजपा सांसदों द्वारा उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने और सदन को सुचारू रूप से चलाने का आग्रह किया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक के नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खड़गे ने आरोप लगाया कि धनखड़ सरकार के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं और स्कूल के हेडमास्टर की तरह काम कर रहे हैं, अक्सर अनुभवी विपक्षी नेताओं को उपदेश देते हैं और उन्हें सदन में बोलने से रोकते हैं। खड़गे ने कहा, 'राज्यसभा के चेयरमैन का आचरण उनके पद की गरिमा के विपरीत है। वह विपक्षी नेताओं को निशाना बनाते हैं और अक्सर सरकार की तारीफ करते हैं।' खड़गे ने कहा, 'सदन में राज्यसभा के चेयरमैन के आचरण ने देश की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि राज्यसभा में सबसे बड़ा व्यवधान खुद चेयरमैन ही हैं।' कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि 1952 से संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति के खिलाफ कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया है क्योंकि इससे पहले (शेष पृष्ठ 9)

नई दिल्ली में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य के साथ लोकसभा में।

रेलवे कानूनों में संशोधन करने वाला विधेयक पारित

लोकसभा ने बुधवार को रेलवे कानूनों में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया, जिसमें सरकार ने जोर देकर कहा कि इससे राष्ट्रीय वाहक का निजीकरण नहीं होगा। रेलवे संशोधन विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निचले सदन में कहा कि एक झूठी कहानी फैलाई गई थी कि संशोधन से रेलवे का निजीकरण होगा। उन्होंने कहा, 'संविधान पर उनका (विपक्ष का) झूठा आख्यान विफल हो गया है... अब यह भी विफल हो जाएगा।' पिछले सप्ताह सदन की कार्यवाही में बार-बार व्यवधान के कारण बहस नहीं हो सकी थी, जिसके बाद विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। वैष्णव ने कहा, 'कुछ सदस्यों ने कहा है कि विधेयक से रेलवे का निजीकरण होगा, एक झूठी कहानी बनाने की कोशिश की गई है। मैं उनसे पूरी ईमानदारी से अपील करना चाहता हूं कि वे ऐसा न करें, संविधान के बारे में उनका एक झूठा आख्यान पहले ही विफल हो चुका है।' रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024, जिसका उद्देश्य रेलवे बोर्ड के कामकाज और स्वतंत्रता को बढ़ाना है, पिछले संसद सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था।

मैनुअल तरीके से सीवर सफाई को खत्म करने की जरूरत :सुप्रीम कोर्ट

पीटीआई। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह मैनुअल तरीके से सीवर सफाई को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह समाप्त करने के लिए दिए गए निर्देशों के अनुपालन पर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करे।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वह दो सप्ताह के भीतर सभी हितधारकों के साथ केंद्रीय निगरानी समिति की बैठक बुलाएं।समिति मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएस अधिनियम, 2013) के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। पीठ ने कहा, अदालत द्वारा (2023 में) पारित आदेश में कहा गया था कि प्रौद्योगिकी के विकास को देखते हुए, सीवर की सफाई के लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग और श्रमिकों के रोजगार को खत्म करना पूरी तरह से संभव है। ऐसा नहीं किया गया है। रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। न्याय मित्र के रूप में न्यायालय की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने दलील दी कि 2024 में सीवर सफाई और सेप्टिक टैंक की सफाई के कारण 40 लोगों की मौत हुई, लेकिन कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत अनिर्वाय ज्यादातर समितियां अस्तित्व में नहीं हैं तथा कानूनों का अनुपालन नहीं होने की ओर ध्यान दिलाया। इस मामले पर जनवरी, 2025 में सुनवाई होगी। उच्चतम न्यायालय ने 2023 में केंद्र और राज्यों को उचित उपाय करने और नीतियां बनाने का निर्देश दिया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मैनुअल तरीके से सीवर सफाई को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। इससे पहले न्यायालय ने कई निर्देश जारी करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से सीवर सफाई के दौरान मरने वालों के परिजनों को 30 लाख रुपए का मुआवजा देने को कहा था।

उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि किसी भी दिव्यांगता से ग्रस्त सीवर पीड़ितों के मामले में न्यूनतम मुआवजा 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। इसने कहा था कि यदि दिव्यांगता स्थाई है और पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर है तो मुआवजा 20 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए।

4.9 डिग्री सेल्सियस पर ठिठुरी दिल्ली

राजेश कुमार। नई दिल्ली

मौसम में बदलाव के बाद पहली बार दिल्लीवासियों ने सर्दी का अनुभव किया, बुधवार को न्यूनतम तापमान सफदरजंग स्टेशन पर 4.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो इस सर्दी में सामान्य से पांच डिग्री कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 20 से 23 डिग्री सेल्सियस और 4 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच है।

यह पिछले साल के महीने के सबसे कम न्यूनतम तापमान के समान है, जो 15 दिसंबर, 2023 को दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने वाहन चलाते समय या किसी भी परिवहन से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने और ढीले-ढाले, हल्के वजन वाले गर्म ऊनी कपड़ों की कई परतें पहनने की सलाह दी। उन्होंने लोगों को अपने सिर, गर्दन, हाथ और पैर की उंगलियों को पर्याप्त रूप से ढकने की भी सलाह दी क्योंकि शरीर के इन अंगों को अधिकांश नुकसान होता है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, पालम में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री रहा, जो (शेष पृष्ठ 9)

महाराष्ट्र के परभणी में भारतीय संविधान की प्रतिकृति को कथित तौर पर क्षतिग्रस्त किए जाने के विरोध में दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा।

महाराष्ट्र के परभणी में हिंसक हुआ प्रदर्शन

टी एन रघुनाथ। मुंबई

स्थानीय रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित डॉ. बीआर अंबेडकर की प्रतिमा के पास कुछ उपद्रवियों द्वारा भारतीय संविधान की कांच से बनी प्रतिकृति को क्षतिग्रस्त किए जाने के एक दिन बाद, मराठवाड़ा के परभणी शहर में बुधवार को एक बार फिर हिंसा भड़क उठी, जब अंबेडकरवादी कार्यकर्ताओं द्वारा आहूत बंद के बीच प्रदर्शनकारियों ने बड़े पैमाने पर हिंसा, आगजनी और पथराव किया।

प्रदर्शन हिंसक हो गया, जब गुस्साई भीड़ ने जिला कलेक्टर के कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की, फर्नीचर और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, जबकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने पड़ोस में आगजनी और पथराव किया। उग्र भीड़ ने जिला कलेक्टर के कार्यालय के पास भी पथराव किया, जबकि उन्होंने कुछ वाहनों में आग लगा दी, सड़कों पर टायर और कचरा जला दिया। कुछ हिंसक प्रदर्शनकारियों को लाठी, रॉड और पत्थर लेकर घूमते देखा गया।

पुलिस ने उग्र प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय के पास आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारियों ने एक दुकान के सामने रखे पीवीसी पाइपों के ढेर में आग लगा (शेष पृष्ठ 9)

दिल्ली में शराब पीनी है तो दिखाओ सरकारी आईडी प्रूफ!

राजेश कुमार। नई दिल्ली

दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने शराब परोसने वाले होटलों, क्लबों और रेस्तराओं को निर्देश दिया है कि वे शराब पीने की कानूनी उम्र के नियमों का उल्लंघन पाए जाने के बाद सरकार द्वारा जारी पहचान प्रमाणों की हार्ड कॉपी के ज़रिए अपने ग्राहकों की उम्र सत्यापित करें। दिल्ली में शराब सिर्फ़ 25 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को ही परोसी जाती है। दिल्ली अब एकमात्र ऐसा महानगर है जहाँ शराब पीने की उम्र सीमा ज़्यादा है, यहाँ तक कि मुंबई में भी 25 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सिर्फ़ हार्ड शराब पर पाबंदी है, जबकि वाइन और बीयर 21 साल की उम्र में पीने की अनुमति है। न्यूयॉर्क और लंदन जैसे प्रमुख वैश्विक शहरों में शराब पीने की उम्र क्रमश: 21 और 18 साल है। दिलचस्प बात यह है कि भारत में मतदान की उम्र 18 साल है, जबकि महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल और पुरुषों के लिए 21 साल है।

दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने हाल के दिनों में अपनी टीमों द्वारा नियमित निरीक्षण के दौरान पाया कि 25 साल से कम उम्र के ग्राहक बार, क्लब और रेस्तराँ में शराब पीते हैं। निरीक्षण में यह भी पता चला कि कुछ ग्राहक 25 साल की उम्र पूरी करने का दिखावा करके शराब पी रहे थे। आबकारी विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, विभाग को यह भी शिकायतें मिली थीं कि कुछ आबकारी लाइसेंसधारी कम उम्र के व्यक्तियों को शराब परोस रहे थे। आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार, शहर में करीब 1,100 एचसीआर (होटल, क्लब, रेस्टोरेंट) श्रेणी के परिसर हैं, जिनमें करीब 700 रेस्ट्रोबार शामिल हैं। आबकारी लाइसेंस संख्या वाले

होटलों और क्लबों की संख्या करीब 165 और 50 है। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर एचसीआर शराब परोसते समय पीने की उम्र के मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत, कोई भी व्यक्ति या लाइसेंसधारी विक्रेता या उसका कर्मचारी या एजेंट 25 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत या दूसरों के उपभोग के लिए शराब नहीं बेचेगा या वितरित नहीं करेगा। आयु प्रतिबंध मानदंडों के उल्लंघन की विभाग द्वारा समीक्षा की गई।

विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है, सभी होटल, क्लब, रेस्तरां (एचसीआर) के लाइसेंस धारकों को अधिक सावधान रहने और सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र के माध्यम से आयु की पुष्टि किए बिना 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब न परोसने का निर्देश दिया जाता है। इस संबंध में उपायुक्त (आबकारी) तनवीर अहमद ने होटल, क्लब और रेस्तरां को जारी परिपत्र में कहा, दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 की धारा 23 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें लिखा है, कुछ व्यक्तियों को बिक्री का निषेध - कोई भी व्यक्ति या लाइसेंस प्राप्त विक्रेता या उसका कर्मचारी या एजेंट किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं बेचेगा या वितरित नहीं करेगा, चाहे वह स्वयं या दूसरों के उपभोग के लिए हो।

परिपत्र में कहा गया है, 'सभी लाइसेंस धारकों को सलाह दी जाती है कि वे ग्राहकों की आयु का सत्यापन केवल भौतिक पहचान पत्र से करें, न कि मोबाइल फोन पर दिखाए गए वर्चुअल पहचान पत्र (सरकारी पोर्टल जैसे डिजिलॉकर को छोड़कर) से, ताकि फर्जी/संपादित डिजिटल पहचान पत्र के माध्यम से आयु के सत्यापन की संभावना कम से कम हो।' दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र एक लंबित मुद्दा था, क्योंकि यह एनसीआर के शहरों नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में कम थी। आबकारी नीति 2021-22 के तहत, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है, शराब पीने की कानूनी उम्र को घटाकर 21 वर्ष करने की योजना थी, लेकिन यह अमल में नहीं आ सकी, क्योंकि नीति स्वयं भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन के आरोपों के घेरे में आ गई। इसके अलावा, अगले तीन वर्षों में शहर को नशा मुक्त बनाने के लिए हाल ही में दिल्ली द्वारा शुरू किए गए अभियान के अनुसरण में, आबकारी विभाग ने लाइसेंसधारियों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ई-शपथ लेने और होटलों, क्लबों और रेस्तरां में प्रमाण पत्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। विभाग ने लाइसेंसधारियों को सलाह दी है कि वे अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने में सहयोग करने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए इसके उपयोग से दूर रहने के लिए जागरूकता पैदा करें। एक (शेष पृष्ठ 9)

एफआरएस के जरिये फर्जीवाड़ा कर 75 लाख का लोन लिया

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उन्नत फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस) का उपयोग करते हुए, दिल्ली पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक संपत्ति को गिरवी रखकर और जाली दस्तावेज़ तैयार करके 75 लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया था। पुलिस ने पंकज सचदेवा उर्फ ??रोशन मनचंदा (61) को गिरफ्तार किया, जिसने ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्ति के दस्तावेज़ और पहचान प्रमाण-पत्रों को गढ़ा था। गिरफ्तारी से दो साथियों, सुहैल चौहान और नितिन वर्मा की संलिप्तता का भी पता चला, जो फ्रीलांस लोन एजेंट के रूप में काम करते थे।

पुलिस के अनुसार, यह मामला 2019 में बेंगलुरु की रहने वाली हरमिंदर कौर आनंद की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि 2011 में उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के राणा प्रताप बाग में उन्होंने जो संपत्ति खरीदी थी, उसे 75 लाख रुपये के ऋण के लिए एक निजी बैंक को धोखाधड़ी से गिरवी रख दिया गया था। पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पश्चिम) अभिषेक धनिया ने कहा, 'महिला 2018 में संपत्ति का दौरा करने के दौरान धोखाधड़ी के बारे में

जानकर चौंक गई थी, जब पड़ोसियों ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दी और उसके दामाद ने संपत्ति पर एक ऋण नोटिस चिपका हुआ पाया।' अधिकारी ने आगे कहा कि धोखेबाजों ने संपत्ति को गिरवी रखने के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए थे और बाद में फर्जी पहचान के तहत कई खातों में धन हस्तांतरित करके ऋण प्राप्त किया। गिरोह ने विशेष रूप से लंबे समय से खाली संपत्तियों को निशाना बनाया, स्वामित्व स्थापित करने के लिए नकली दस्तावेजों की एक श्रृंखला बनाई। फिर उन्होंने इन जाली कागजों का इस्तेमाल वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए किया। उन्होंने कहा कि धन को पता लगाने से बचने के लिए तेजी से विभिन्न खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिससे धन के निशान का पता लगाना मुश्किल (शेष पृष्ठ 9)

'जुगाड़' और अन्य शब्द नई डिक्शनरी में शामिल

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

देश के युवा तेजी से बदलते डिजिटल युग में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में 'ब्लू कार्बन', 'कल्चरनॉमिक्स', 'डिजिटल नोमैड', '15 मिनट सिटी' और 'लॉक्स' जैसे 47 शब्दों को भारत की ताकत को मान्यता देते हुए नई डिक्शनरी में शामिल किया गया है। डिक्शनरी का शीर्षक है 'इंडिया इन फ्यूचर टेंस- 47 वर्ड्स फॉर 2047।'

'जुगाड़' और 'गेमिफिकेशन' जैसे अन्य शब्द, जो किसी देश में रोजमर्रा की बोलचाल या भाषा का हिस्सा हैं, ने एक तरह से अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कर ली है। यह घटना पिछले कुछ वर्षों में यूरोप और संयुक्त

राज्य अमेरिका में कुलीन संस्थानों और उद्योगों में अध्ययन करने या काम करने वाले प्रतिभाशाली भारतीय युवा पुरुषों और महिलाओं के बाद आई। उन देशों के साथियों के साथ बातचीत ने स्पष्ट रूप से इन शब्दों को संवाद करते समय दैनिक उपयोग में ला दिया है और व्यापक स्वीकृति प्राप्त की है। यह शब्दकोष उन प्रमुख प्रवृत्तियों की पहचान करता है जो 2047 में भारत के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रमुख होंगी, इसका उद्देश्य उन मूल्यों को प्रतिबिंबित करना है जो राष्ट्र की यात्रा को परिभाषित करेंगे- 'समावेशीपन, स्थिरता और तकनीकी उन्नति'। इसे संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन और ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) द्वारा लाया गया है। यह शब्दकोष नेक्स्ट जेनरेशन इंडिया फेलोज की पहल का हिस्सा है और इसके विवरण में कहा गया है, इसका उद्देश्य युवाओं को 2047 तक एक स्थाई और समृद्ध भारत को आकार देने के लिए आवश्यक ज्ञान और भाषा से सशक्त बनाना है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारे जीवंत वातावरण और उभरते शब्दों का वर्णन करने के लिए नए संज्ञा, क्रिया और वाक्यांश आवश्यक होंगे। ब्लू कार्बन वह कार्बन है जो वायुमंडल से अवशोषित होकर समुद्र में जमा होता है, कल्चरनॉमिक्स संस्कृति और अर्थशास्त्र का मिश्रण है जो मनोरंजन, भोजन, खेल आदि के माध्यम से संस्कृति के दुनिया भर में प्रसार का वर्णन करता है।इसी प्रकार, डिजिटल नोमैड वह व्यक्ति है जो खानाबदोश जीवन शैली को अपनाते हुए दूर से काम करने के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग करता है। जबकि 15-मिनट सिटी से अभिप्राय: शहर में कहीं भी रहने वाले लोगों के लिए सभी आवश्यक सेवाओं को 15 मिनट के दायरे में रखने से है। शब्दकोश में शामिल अन्य प्रमुख शब्दों में गेमिफिकेशन , जेंडर बॉन्ड , हेरिटेज हब , जुगाड़ , न्यूरोक्रीर , ओस्मोटिक ऊर्जा , प्लास्टिवोर और रोबोकेयर शामिल हैं।

फिर भी रहेंगी निशानियां...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में महान अभिनेता स्वर्गीय राजकपूर के परिवार के सदस्यों के साथ। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, नीतू सिंह, करीना कपूर खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर और अन्य सहित पूरे कपूर परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें महान अभिनेता-फिल्म निर्माता की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले राज कपूर फिल्म महोत्सव में आमंत्रित किया।

दुनिया की 100 प्रतिष्ठित कंपनियों में से 20 के सीईओ भारत के युवाः मुख्यमंत्री

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ बस्ती

सीएम योगी ने बस्ती में कर्मा देवी समूह के 15वें स्थापना दिवस समारोह में की शिरकत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह भूमि भगवान राम के जन्म के हेतु का कारण है। प्रभु श्रीराम ने प्रेरणा दी कि व्यक्ति कितना भी बड़ा और यश-धनधान्य से परिपूर्ण न हो जाए, वह तब तक अधूरा है, जब तक मां और मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित न कर ले। मां की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखते और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य निभाते हुए गरीब छात्र भी अच्छी व आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए दोनों भाइयों ने मां के नाम पर कर्मा देवी समूह और पिता के नाम पर फॉर्मेसी कॉलेज स्थापित किया। उनका उद्देश्य था कि इसके जरिए हजारों बच्चे कर्मपथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करते हुए सम्मान के साथ स्वावलंबन का जीवनयापन करें। एक व्यक्ति का स्वावलंबन समाज व राष्ट्र का स्वावलंबन होता है।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को कर्मा देवी समूह के 15वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। सीएम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों व शिक्षकों को सम्मानित किया। सीएम ने ओमनी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर का बटन दबाकर शिलान्यास किया। सीएम ने सरोज सिंह व देवमंगल सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सरोज सिंह जब मंदिर आती थी, तब कहती थीं कि एक दिन आप मुख्यमंत्री बनेंगे। योगी ने कहा कि व्यक्ति पर पांच ऋण होते हैं। मां, पिता, गुरु, मातृभूमि व देवगणों के लिए जो कुछ भी कर पाएंगे, उनकी स्मृतियों व आदर्शों को जीवन में जिस हद तक अंगीकार करने का प्रयास कर पाएंगे, यही उद्धरण होने का माध्यम होता है। ओएन सिंह व देवमंगल सिंह का प्रारंभिक जीवन संघर्षों से भरा था। जब पूर्वी उप्र संसाधन के अभाव में जूझ रहा था, सड़क, बिजली, शुद्ध पेयजल, शिक्षण संस्थान, रोजगार के साधन नहीं थे, उन स्थितियों में अपनी शिक्षा को अनवरत बनाए रखना मां की साधना के बिना संभव नहीं था। 1981 में देवमंगल सिंह (अब स्मृतिशेष) आईएफएस बने व 1983 में ओएन सिंह उप्र पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अधिकारी बने। योगी ने कहा कि विकसित देशों ने योग्यता, तकनीक व परिश्रम की पराकाष्ठा को महत्व व प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाकर स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर किया। पीएम ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प रखा है। दुनिया भारत के महत्व को समझ रही है। भारत की प्रतिभा को जहां भी मौका मिला, उसने खुद को सााबित किया। दुनिया की 100 प्रतिष्ठित कंपनियों में से 20 के सीईओ भारत के युवा हैं। तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है, हम भी इससे पीछे नहीं भाग सकते। लेकिन हमें नैतिक निहितार्थ व सुरक्षात्मक उपायों को अपनाना पड़ेगा। यदि दृष्टि नकारात्मक बनी तो नीचे होंगे और सकारात्मक दृष्टि बनाई तो छाने में समय नहीं मिलेगा। योगी ने कहा कि सरकार व समाज मिलकर कार्य करेंगे तो अवश्य परिणाम आएगा। लगभग दो दशक पूर्व मुंडेरवा चीनी मिल के किसानों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। सकारात्मक सोच की सरकार आई तो आज मुंडेरवा में चीनी मिल आज कार्य कर रही है। एक सरकार ने इसे बेच दिया, दूसरी ने इसे खोल दिया। कार्य करने की इच्छाशक्ति होनी चाहिए, संसाधन आड़े नहीं आता। हमें दिग्भ्रमित नहीं होना है, बल्कि सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ना है। बस्ती अब मॉडल नगर बन चुका है। उन्होंने कहा कि यहां का तपसी धाम एकमात्र धर्मस्थल है, जहां क्रांतिकारियों की स्मृति में भंडारा होता है। इजराइल के साथ बस्ती के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हुई है। यहां होर्टिकल्चर का बेहतरीन सेंटर बनकर उभरा है। सीएम ने यहां के प्रोडक्ट, क्लाईमेट चेंज, आर्गेनिक प्रोडक्ट, प्राकृतिक खेती, क्वालिटी, निराश्रित गोआश्रय स्थल पर भी चर्चा करते हुए किसानों को सफलता का मंत्र दिया।

गरीबों की जमीन कराएं कब्जामुक्त भूमाफिया को सिखाएं कानूनी सबक

मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में सुनीं 200 लोगों की समस्याएं

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ गोरखपुर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गरीबों की जमीन कब्जामुक्त कराएं और अवैध कब्जा करने वाले दबंगों को करारा कानूनी सबक सिखाएं। उन्होंने कहा कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफिया और कमजोरों को उजाड़ने वाले दबंग किसी भी दशा में बख्शे न जाएं। उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुसरण करते हुए कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सरकार का संकल्प है कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जमीन कब्जा करने के मामलों में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

सीएम योगी बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक वह खुद पहुंचे और एक-एक करके, इत्मीनान से सबकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सबको न्याय मिलेगा और सबकी पीड़ा दूर की जाएगी। जनता दर्शन में दूसरे जिलों के भी लोग आए थे।

जनता दर्शन में कुछ महिलाओं ने भूमाफिया और दबंगों द्वारा जमीन कब्जा करने की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमाफिया को करारा सबक सिखाया जाएगा। उनके रहते कोई भी किसी कमजोर या गरीब को उजाड़ नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद प्रशासन व पुलिस के अफसरों को निर्देशित किया कि जबरन जमीन कब्जा करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई करें। सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी दबंग, माफिया, अपराधी किसी की जमीन पर कब्जा न करने पाए।

मुख्यमंत्री के समक्ष जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इलाज से जुड़ी इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करा कर शासन में उपलब्ध कराया जाए। सीएम ने अफसरों से कहा कि वे हर जरूरतमंद का आयुष्मान कार्ड बनवाएं ताकि इलाज के लिए उन्हें परेशान न होना पड़े। जनता दर्शन में कुछ महिलाएं अपने बच्चों के साथ आई थीं। मुख्यमंत्री ने उन्हें चॉकलेट गिफ्ट करते हुए स्नेहिल भाव से आशीर्वाद दिया।

मनरेगा से गांवों में बन रहे अन्नपूर्णा भवनः केशव मौर्य

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में मनरेगा से गांवों में बन रहे अन्नपूर्णा भवन बनाये जा रहे हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत खाद्यान भण्डारण संरचनाओं का निर्माण, जिनका उपयोग उचित दर की दुकानों के लिए भी किया जा सकता है, ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत सरकारी जमीन पर खाद्यान भण्डारण संरचना (अन्नपूर्णा भवन) का निर्माण कार्य निरंतर जारी है। इसमें एक हॉल, एक प्रतीक्षालय के साथ साथ जनसेवा केंद्र संचालन की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना के अंतर्गत राशन मॉडल शॉप (अन्नपूर्णा भवन) का निर्माण कार्य जारी है। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 2800 से ज्यादा कार्य प्रारंभ कराये जा चुके हैं, जबकि इनमें से बड़ी संख्या अन्नपूर्णा भवन बनकर तैयार भी हो चुके हैं, जबकि करीब 2763 कार्य प्रगतिशील हैं। उचित दर विक्रेताओं की दुकानें संकरी गलियों में होने के कारण खाद्यान वाहन और आम जनमानस को दुकान तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। ग्राम सभाओं में अब अन्नपूर्णा भवन के विकसित होने से खाद्यान वाहन और आम जनमानस की पहुंच आसान हुई है। उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए यहां से विद्युत देयकों का भुगतान, सी.एस.सी सेवाएं, पी.एम वाणी के अंतर्गत ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने के साथ-साथ आम जनमानस की रोजमर्रा की आवश्यकता की वस्तुओं की बिक्री की भी अनुमति प्रदान की गई है। एक भाग में उचित दर की दुकान होगी।

सरकार रसायनमुक्त खेती को दे रही बढ़ावाः शाही

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

कृषि मंत्री की अध्यक्षता में कृषि स्थायी समिति की बैठक सम्पन्न

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में कृषि स्थायी समिति की बैठक बुधवार को विधानसभा के सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान समिति के लिए नामित जनप्रतिनिधि सदस्यों द्वारा विविध विषयों पर अपने सुझाव रखे गए। कृषि स्थायी समिति की बैठक के दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा समिति के सदस्यों को वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के अन्तर्गत कृषि कार्यक्रमों की प्रगति, फसलोत्पादन योजनाओं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वेदर इन्फारमेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम (विंड्स), एग्रीस्टैक योजनान्तर्गत फार्मर रजिस्ट्री अभियान सहित अन्य विभागीय योजनाओं की अद्यतन प्रगति की जानकारी दी।

शाही ने कहा कि विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में समय पर उचित मात्रा में खाद उपलब्ध कराने का कार्य किया गया। बीजों के लिए दी जा रही सब्सिडी को एट सोर्स कर दिया गया। अर्थात् किसानों को बीज खरीदते समय ही सब्सिडी उपलब्ध करा दी जाती है, उन्हें इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। किसानों की ऊर्जा मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम किसान) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में नवंबर 2024 तक 53250 के सापेक्ष 19478 सोलर पंप स्थापित किया जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही खेत तालाब योजना के अंतर्गत गत वर्ष 3370 तालाब तैयार कराए गए थे, जबकि इस वित्तीय वर्ष में 8499 की सापेक्ष अभी तक 1428 खेत तालाब तैयार किये जा चुके हैं। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 54 जनपदों में परंपरागत कृषि विकास योजना संचालित की जा रही है। गंगा के तटवर्ती 27 जनपदों में नमामि गंगे योजना चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत रसायनमुक्त खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दौरान स्थाई समिति के सदस्य गणों द्वारा मंडी परिषद की सड़कों की गुणवत्ता सुधारने, निराश्रित गोवंश के आश्रय स्थलों की व्यवस्था को बेहतर किए जाने, पराली प्रबंधन को किसानों के लिए लाभदायक बनाए जाने तथा जिला स्तर पर कृषि विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम और योजनाओं में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित किए जाने सहित अन्य विषयों पर अपने सुझाव रखें। इन सुझावों पर कृषि मंत्री ने कहा कि सदस्यों के स्वागत योग्य सुझावों को आगामी योजनाओं में शामिल किए जाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर स्थाई समिति के सदस्यों में बाबूलाल आगरा, जवाहर लाल राजपूत झांसी, राजेन्द्र सिंह पटेल फतेहपुर, मूलचन्द्र सिंह जालौन, राजीव सिंह ऊर्फ बब्लू भइया बदायूं, विनोद शंकर अवस्थी खीरी, प्रभात कुमार वर्मा गोण्डा, सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा कुशीनगर, प्रदीप यादव औरैया, अखिलेश आजमगढ़, डॉ. संग्राम यादव आजमगढ़ तथा प्रमुख सचिव कृषि रविंद्र, कृषि निदेशक एवं कृषि विभाग के उच्चाधिकारी शामिल रहे।

पीआरडी जवान पूरी कर्मठता के साथ निभा रहे सुरक्षा व्यवस्था की अहम जिम्मेदारीः गिरीश चंद्र

लखनऊ। युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग द्वारा जेल रोड, आनन्द नगर स्थित महानिदेशालय पर 76वें प्रान्तीय रक्षक दल (पीआरडी) का स्थापना दिवस समारोह का आयोजन परेड ग्राउण्ड में किया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), युवा कल्याण एवं खेल गिरीश चन्द्र यादव द्वारा पीआरडी जवानों की रैतिक परेड का निरीक्षण करने के उपरान्त मान-प्रणाम स्वीकार किया गया। इस अवसर पर गिरीश चन्द्र यादव द्वारा अपने उद्बोधन में पी.आर.डी. जवानों द्वारा थाना, यातायात एवं अन्य शासकीय विभागों तथा अर्ध-शासकीय संस्थानों में की जा रही ड्यूटी की सराहना की गयी। उन्होंने कहा कि पीआरडी जवानों द्वारा पुलिस बल के सहयोगी यूनिट के रूप में कार्य करने के साथ ही महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालयों की सुरक्षा का भी दायित्व कुशलतापूर्वक निर्वहन किया जा रहा है।

यूपी को पर्यटकों के मामले में अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार कटिबद्धः जयवीर सिंह

● उत्तर प्रदेश में विगत नौ महीने में आए 47.61 करोड़ पर्यटक

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में आये बदलाव और बेहतर कानून व्यवस्था एवं सराहनीय कनेक्टिविटी के चलते उत्तर प्रदेश में विगत 09 माह में 47.61 करोड़ पर्यटकों ने भ्रमण किया। इसमें घरेलू पर्यटकों की संख्या 47.47 करोड़ और विदेशी पर्यटकों की संख्या 14 लाख अधिक रही, जिसके फलस्वरूप पर्यटन सेक्टर से जुड़े व्यावसायियों तथा कारोबारियों में गजब का उत्साह देखा गया। साथ ही निवेश एवं रोजगार तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को गतिशीलता प्राप्त हुई। राज्य सरकार पर्यटन सेक्टर को प्राथमिकता देने के लिए प्रयासरत है कि देश में आने वाला हर विदेशी पर्यटक एक बार उत्तर प्रदेश अवश्य पधारे। इसके लिए पर्यटक फ्रेण्डली वातावरण तैयार किया गया है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने बताया कि राज्य पर्यटन में बढ़ोतरी के मुख्य केंद्र में धार्मिक और आध्यात्मिकता हैं। मर्यादापुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। इस पावन भूमि पर नौ माह में 135590523 पर्यटक आए, जिसमें 135587370 घरेलू पर्यटक और 3153 विदेशी श्रद्धालु हैं। इसी तरह, भगवान कृष्ण की स्थली मथुरा में कुल 68155926 श्रद्धालु पहुंचे, जिसमें 68068697 घरेलू और 87229 विदेशी पर्यटक आए। प्राचीनतम नगरी के रूप में विश्वविख्यात काशी जो कि भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है। यहां कुल 62718417 श्रद्धालु आए, जिसमें 62534381 घरेलू और 184036 विदेशी पर्यटक हैं। प्रयागराज जिसे तीर्थराज भी कहा जाता है, यहां कुल 48010970 पर्यटक आए, जिसमें 48006180 घरेलू और 4790 विदेशी पर्यटक आए। मीरजापुर में कुल 11818401 पर्यटक पहुंचे।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि वाराणसी और मथुरा के अलावा आगरा व कुशीनगर आदि स्थलों पर बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंचे। कुशीनगर में 1620920 पर्यटक आए, जिसमें 153165 विदेशी और 1467755 घरेलू पर्यटक हैं। आगरा में कुल 12518887 सैलानी आए, जिसमें 11594626 घरेलू और 924261 विदेशी पर्यटक हैं। सिद्धार्थनगर में कुल 86215 पर्यटक आए जिसमें 75343 घरेलू और 10872 विदेशी श्रद्धालु हैं। कुशीनगर और सिद्धार्थनगर बुद्धिस्ट सर्किट का महत्वपूर्ण गंतव्यस्थल हैं।

भाजपा सरकार ने सभी संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दियाः अखिलेश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने सभी संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया है। भाजपा ने संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिकरण कर दिया है, जिसके कारण उन पर से लोगों का भरोसा खत्म हो रहा है। सरकार के दबाव में संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि संवैधानिक संस्थाएं देश की जनता के बजाय भाजपा के लिए काम कर रही हैं, देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा है, भाजपा की सत्ता की भूख ने पूरे देश को तबाह कर दिया है। भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली और रवैया तानाशाही पूर्ण है। उन्होंने कहा कि विपक्ष, आमजन, नौजवान, किसान, व्यापारी, कर्मचारी किसी को भी अब भाजपा सरकार पर कोई भरोसा नहीं रहा है। भाजपा सरकार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसान की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है। भाजपा सरकार को आम जनता की कोई परवाह नहीं है क्योंकि वह वोट से नहीं खोट से चुनाव जीत कर सरकार बनती है। उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि भाजपा ने झूठ के सहारे ही अपनी सरकार चलाई है। किसानों को दुगनी आय का भरोसा दिया गया, मिला कुछ नहीं। एमएसपी की अनिवार्यता के लिए आंदोलन चला, सात सौ से ज्यादा किसान शहीद हो गए। आज तक भाजपा ने एमएसपी पर कोई निर्णय नहीं लिया। किसानों की समस्याओं पर कमेटी बनाने का प्रस्ताव फाइलों में कैद हो गया। प्रदेश में बिजली के निजीकरण के बहाने आरक्षण समाप्त करने और आउट सोर्स से भर्ती की साजिशें चल रही हैं। अखिलेश ने कहा कि नौजवानों को बड़े-बड़े सपने दिखाए गए। दो करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का वादा किया गया था। 10 साल में 10 लाख भी नौकरियां नहीं दी गई।

TATA
TATA POWER
(Corporate Contracts Department)
Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela, Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, India
(Board Line: 022-67173188) CIN: L28920MH1919PLC000567

CORRIGENDUM

The Tata Power Company Limited has invited expression of interest from eligible vendors for the **"Security Services at Jojobera Plant, Jamshedpur, Jharkhand for a period of three years - Ref No.: CC25FK060"** vide advertisement on 20th September 2024. Notice is hereby given to interested parties of an amendment to our Notice inviting Expression of Interest for the above mentioned Package. Interested parties may visit Tender section of our website **(URL: https://www.tatapower.com/tender)** for downloading the same. Eligible parties willing to participate may submit their expression of interest along with the tender fee for issue of bid document latest by **18th December 2024.** Parties who have already submitted their expression of interest need not re-apply.

HDFC BANK
We understand your world
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, द्वितीय तल, एक्सपीरियो बिल्डिंग, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010

कब्जा सूचना परिशिष्ट IV [नियम 8(1).

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित 01-01-2024 जारी की थी, जिसमें कर्जदार(रों) **(1) मैसर्स तनीषा एंटरप्राइजेज अपने प्रोपराइटर श्रीमती रुपाश्री राय (उधारकर्ता) के माध्यम से (2) श्रीमती रुपाश्री राय पति श्री आशिष शर्मा (सह-उधारकर्ता) (3) श्रीमती उषा शर्मा पत्नी श्री शिवाश्रय राय शर्मा (सह-उधारकर्ता) (4) श्री शिवाश्रय राय शर्मा पुत्र श्री विश्वनाथ राय शर्मा (सह-उधारकर्ता और बंधककर्ता),से उक्त सूचना में वर्णित अनुसार बकाया राशि रू. 48,56,457.00/- (अक्षरों में: अड़तालीस लाख छप्पन हजार चार सौ सत्तावन मात्र)** का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार(रों) तथा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने, उक्त नियमावली, के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **09-12-2024 को ले लिया है।** . कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। . कर्जदार को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की सूचना में वर्णित बकाया राशि **रू 48,56,457.00/- (अक्षरों में: अड़तालीस लाख छप्पन हजार चार सौ सत्तावन मात्र)** उस पर ब्याज और खर्चे तथा प्रभार इत्यादि (-) भुगतान की गई राशि, यदि कोई, चुकाने के बाद ही किया जा सकता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

नगर निगम भवन संख्या बी-04/0132, माप 361.37 वर्ग मीटर, विशाल खंड, गोमती नगर योजना, वार्ड- रफी अहमद किदवई, तहसील और जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 , जो श्री शिवाश्रय राय शर्मा के नाम पर है। सीमाएं इस प्रकार है , उत्तरः 12 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिणः प्लॉट संख्या 4/132ए, पूर्वः प्लॉट संख्या 4/131, पश्चिमः 09 मीटर चौड़ी सड़क।

प्राधिकृत अधिकारी
तिथि : 09-12-2024, स्थान : लखनऊ
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

पायनियर वर्गीकृत

सूचना

महत्वपूर्ण सूचना

उप निबन्धक सीतापुर के कार्यालय में दिनांक 05.08.1993 को बही संख्या 1 जिल्द संख्या 260 के पृष्ठ संख्या 347 से 362 पर क्रमांक 1799 पर रजिस्ट्रीकृत मूल विक्रय-विलेख दिनांकित 04.08.1993 व उप निबन्धक सीतापुर के कार्यालय में दिनांक 18.12.2003 को बही संख्या 1 जिल्द संख्या 1491 के पृष्ठ संख्या 299 से 326 पर क्रमांक 6476 पर रजिस्ट्रीकृत मूल विक्रय-विलेख दिनांकित 18.12.2003 एवं उप निबन्धक सीतापुर के कार्यालय में दिनांक 20.03.2004 को बही संख्या 1 जिल्द संख्या 1562 के पृष्ठ संख्या 239 से 250 पर क्रमांक 1025 पर रजिस्ट्रीकृत मूल विक्रय-विलेख दिनांकित 20.03.2004 दिनांक 22.11.2024 को समय लगभग 11.30 बजे प्रातः मोहल्ला रोटी गोदाम सीतापुर से बलराज फोटोस्टेट लालबाग सीतापुर के बीच कही गिर गये है। उक्त मूल विक्रय-विलेख संख्या 1799 दिनांकित 05.08.1993 व मूल विक्रय- विलेख संख्या 6476 दिनांकित 18.12.2003 एवं मूल विक्रय-विलेख संख्या 1025 दिनांकित 20.03.2004 के गिरने की सूचना थाना कोतवाली नगर सीतापुर में जी० डी०/एस० डी० डी० डी० संख्या 0035 पर दिनांक 23.11.2024 को खोयी सम्पत्ति का पंजीकृत की श्रेणी में दर्ज की गयी है। उक्त विक्रय-विलेख में वर्णित सम्बंधित सम्पत्ति के पूर्ण स्वामी संजय सिंह पुत्र स्व० रघुनाथ सिंह है।
संजय सिंह पुत्र स्व. रघुनाथ सिंह निवासी - 265, रोटी- गोदाम, तहसील व-जिला- सीतापुर

सीएम सामूहिक विवाह योजना

दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्ग ने उठाया सबसे अधिक लाभ

● योजना के शुरुआत से अब तक चार लाख से अधिक गरीब कन्याओं की शादी करा चुकी है प्रदेश सरकार

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

योगी की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर तबके, खासकर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। 2017 में शुरू हुई यह योजना आज न केवल इन वर्गों की बेटियों के लिए वरदान साबित हो रही है, बल्कि सामाजिक समरसता और समावेशिता को भी मजबूत कर रही है। अब तक इस योजना के तहत 4 लाख से अधिक गरीब कन्याओं की शादी योगी सरकार द्वारा पूरे रीति-रिवाज और सम्मान के साथ कराई जा चुकी है।

इस योजना ने उन राजनीतिक दलों को कठघरे में खड़ा कर दिया है, जो लंबे समय तक पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की राजनीति के सहारे सत्ता का आनंद लेते रहे, लेकिन उनके लिए ठोस विकास कार्य करने में विफल रहे। विपक्ष की राजनीति को आइना दिखाते हुए, इस योजना ने यह साबित कर दिया है कि केवल वादों से नहीं, बल्कि ठोस कदमों से ही समाज का सशक्तिकरण संभव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कदम न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास और समावेशिता को प्राथमिकता देकर यह साबित कर दिया है कि उनकी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के सिद्धांत पर अडिग है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के आंकड़े यह स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए यह योजना कितनी प्रभावशाली साबित हुई है। अब तक इस योजना का सबसे अधिक लाभ दलित वर्ग ने उठाया है, जिसमें 2.20 लाख से अधिक गरीब परिवारों की बेटियों की शादी कराई गई है। वहीं, पिछड़े वर्ग के 1.30 लाख परिवार और अल्पसंख्यक वर्ग के 40,000 से अधिक परिवार इस योजना के लाभार्थी बने हैं। वहीं सामान्य वर्ग के करीब 16,000 गरीब परिवारों ने अब तक सामूहिक विवाह योजना का लाभ लिया है। यह योजना न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बेटियों की शादी का सपना पूरा कर रही है, बल्कि यह उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान कर रही है। विवाह समारोह में हर जोड़े को 51,000 रुपये की मदद दी जाती है, जिसमें विवाह से जुड़ी आवश्यक सामग्री, वधू के खाते में नकद धनराशि और आयोजन की व्यवस्था शामिल होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने साढ़े सात वर्षों के कार्यकाल में बार-बार यह दिखाया है कि उनकी प्राथमिकता वंचित वर्गों को सशक्त बनाना है। इस योजना के माध्यम से वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रदेश के सभी वर्ग, विशेषकर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, मुख्यधारा से जुड़े और उनके विकास के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। यही वजह है कि इस योजना के लिए योगी सरकार ने अब तक करीब 2,200 लाख रुपये से अधिक की धनराशि खर्च कर चुकी है।

इंडियन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) इलाहाबाद
Indian Bank (A Govt. of India Undertaking) ALLAHABAD

कब्जा नोटिस (अचल सम्पत्ति हेतु)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)अधिनियम 2002 के नियम-8(1) के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **इंडियन बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002, (धारा 54, 2002) की धारा 13 (12) प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (प्रवर्तन) की सपठित नियम 3, 8 व 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋणी को मांग सूचना पत्र से यहाँ विस्तृत रूप से नीचे दी गयी राशि 60 दिनों के भीतर लौटाने के लिए निर्गमित किया।

ऋण-ग्रहिता / जमानतकर्ता के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋण-ग्रहिता / जमानतकर्ता और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है की अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 व 9 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में निम्नलिखित सम्पत्तियों का आधिपत्य ग्रहण कर लिया गया है। ऋण-ग्रहिता / जमानतकर्ता को विशिष्ट रूप से और सर्व-साधारण को सामान्य रूप से एतद्द्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार (क्रय-विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त संपत्ति का किसी भी प्रकार से क्रय-विक्रय **इंडियन बैंक** के अधीन रहेगा।

उधारकर्ता / जमानतकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

यह सूचना इस अधिग्रहण के आयोजन के सम्बन्ध में कर्जदारों, जमानतकर्ताओं और बंधककर्ताओं को बकाया जमा करने के लिए कहा जा रहा है।

विवरण निम्नुसार हैं:-

क्र. सं.	ऋणी / प्रोपराइटर / जमानतकर्ता / बंधककर्ता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि / कब्जा की तिथि / बकाया धनराशि
	शाखाः आयुर्वेदिक कॉलेज शाखा		
1.	1. सुश्री पूजा राठौड़ पत्नी श्री संजय राठौड़ (ऋणी एवं बंधककर्ता), मकान सं. 543/84 शेखपुर हबीबपुर वार्ड सआदतगंज लखनऊ 226003 2. श्री संजय राठौड़ (ऋणी) मकान सं. 543/84 शेखपुर हबीबपुर वार्ड सआदतगंज लखनऊ 226003	मकान सं. 543/01 ए, प्लॉट सं. 14 एवं 15 भाग खसरा संख्या 11,12 एवं 13 के सभी भाग व खण्ड, क्षेत्रफल 116.17 वर्ग मीटर, स्थित शेखपुर हबीबपुर, वार्ड सआदतगंज, तहसील एवं जिला-लखनऊ, **मालिकः** श्रीमती पूजा राठौड़ पत्नी श्री संजय राठौड़, **चौहद्दीः पूर्वः** वकील अहमद का मकान, **पश्चिमः** संजय राठौड़ का मकान, **उत्तरः** 25 फीट चौड़ी सड़क, **दक्षिणः** मेराज की संपत्ति	26.09.2024 06.12.2024 रु. 16,26,584.00 एवं उसपर ब्याज

दिनांकः 12.12.2024 स्थानः लखनऊ
प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

राजस्व वृद्धि पर दें ध्यान, अवैध खनन बर्दाश्त नहीं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को की भूतत्व व खनिकर्म विभाग के कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2407.20 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति हुई है। इसमें और वृद्धि की अपेक्षा है। इसकी बेहतरी के लिए विभागीय व जनपद स्तर के अधिकारी तेजी से प्रयास करें। राजस्व प्राप्ति के लिए जिलाधिकारी व जिला खनन अधिकारी की जवाबदेही तय की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनभद्र, बांदा, कौशांबी तथा महोबा में खनन के दृष्टिगत राजस्व वृद्धि की असीम संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कम राजस्व प्राप्त करने वाले जनपदों की समीक्षा करते हुए इनमें भी राजस्व बढ़ोतरी के उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन, विभाग व जनपद स्तर पर लंबित आवेदन पत्रों पर शीघ्रता से निर्णय लेकर कार्रवाई बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व बढ़ाने के अन्य उपायों पर भी विचार करें। उन्होंने कहा कि नदी के कैचमेंट एरिया में किसी भी प्रकार के अवैध खनन की गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तकनीक का उपयोग करते हुए इसे सख्ती से रोका जाए। स्वीकृत खनन क्षेत्र के अंदर खनन कर रहे वाहनों पर व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) लगाया जाए, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि खनन स्वीकृत क्षेत्र में ही हो रहा है या नहीं। इससे परिवहनकर्ता को भी सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों से प्रदेश में उपखनिज का परिवहन करने वाले वाहनों की वैधता की जांच के लिए उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान व मध्य प्रदेश से एपीआई इंटीग्रेशन किए गए हैं। जनपदों में टास्क फोर्स अवैध खनन को रोकने के लिए समय-समय पर छापेमारी करते रहें। छापेमारी के दौरान विभागीय अधिकारी, प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित हो। इसकी वीडियोग्राफी भी नियमित कराई जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि विभागीय स्तर पर पेंडिंग मामलों का समय से निस्तारण किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जून से अगस्त के मध्य ही वर्ष भर की कार्ययोजना तैयार की जाए। समय से कार्ययोजना तैयार करने से सरलतापूर्वक कार्य संपन्न होंगे। बैठक में उपस्थित परिवहन विभाग के अफसरों को निर्देश दिया कि मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तेजी से प्रयास करें। सड़कों के किनारे ओवरलोड वाहन कतई न खड़े किए जाएं। कर अपवंचन तथा ओवरलोडिंग रोकने के लिए जनपदों में 55 चेक गेट्स स्थापित किए गए हैं। इन पर शीघ्र ही वे इन मोशन संयंत्र लगाए जाएं। ओवरलोडिंग हर हाल में जीरो पॉइंट पर ही रोका जाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के खनन मंत्रालय द्वारा स्टेट माइनिंग रेडिनेश इंडेक्स तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में विभिन्न विभागों के समन्वय से आवश्यक सूचनाओं की समय से उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों के किनारे मिट्टी-बालू तथा सिल्ट का प्रयोग ईंट बनाने में किया जाए। यह पर्यावरण को बचाने में कारगर होगा। उपजाऊ जमीन की मिट्टी का प्रयोग ईंट भट्ठों में न किया जाए।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हुए सख्त, श्रावस्ती के सीएमओ सस्पेंड

सुल्तानपुर के सीएमओ, पूर्व अधीक्षक पर आरोपों की होगी जांच

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सख्त कार्रवाई करते हुए लगातार मिल रहीं शिकायतों के चलते श्रावस्ती के सीएमओ को निलंबित कर दिया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। वहीं, फतेहपुर में तैनात चिकित्सक को भी निलंबित कर सीएमओ सिद्धार्थनगर के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। वहीं, सुल्तानपुर के सीएमओ तथा पूर्व अधीक्षक द्वारा अनियमितताओं के आरोपों की जांच कराई जा रही है। पीलीभीत व अमेठी के दो चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि श्रावस्ती के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अजय प्रताप सिंह द्वारा अवैध निजी अस्पतालों पर प्रभारी अंकुश न लगा पाने, टेंडरों में कतिपय अनियमितता किए जाने तथा बायो मेडिकल वेस्ट का उचित निस्तारण न करने व उच्च आदेशों की अव्हेलना किए जाने के आरोपों के चलते उन्हें सस्पेंड करते हुए चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय से संबद्ध किया गया है। इस संबंध में शासन द्वारा डीएम व सीडीओ श्रावस्ती को पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए गए थे। दोनों अधिकारियों द्वारा शासन को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

वहीं, फतेहपुर के जिला महिला चिकित्सालय में तैनात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. पुण्ड्रीक कुमार गुप्ता को निलंबित करते हुए सिद्धार्थ नगर के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से संबद्ध किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि चिकित्सक का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे सरकार, शासन व प्रशासन के आला अफसरों के प्रति अभद्र टिप्पणी व अमर्यादित भाषा का प्रयाग कर रहे थे। समय से शासन को इस प्रकरण की जानकारी न देने पर डिप्टी सीएम द्वारा फतेहपुर के सीएमओ का स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। डॉ. गुप्ता द्वारा फतेहपुर के जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को प्रतिमाह पैसे दिए जाने के आरोप के संबंद्ध में भी उक्त चिकित्सा अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि सुल्तानपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. ओपी चौधरी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लम्भुआ (सुल्तानपुर) के पूर्व अधीक्षक के विरुद्ध विभिन्न अनियमितताओं एवं भष्टाचार की शिकायतों की जांच मंडलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को दिए गए हैं। वहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमानाबाद (पीलीभीत) में तैनात दन्त शल्यक डॉ. प्रतिष्ठा सिंह एवं गौरीगंज (अमेठी) के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात रेडियोलॉजिस्ट डॉ. संदीप कुमार द्वारा लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

30 नियमित, 12 आउटसोर्स पद सृजित

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंगेल में निर्मित 50 शैय्या मैटर्निटी विंग की स्थापना एवं क्रियांवयन के लिए चिकित्सकों के नौ एवं पैरामेडिकल व अन्य श्रेणी के 21 पदों सहित 30 नियमित पदों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा आउटसोर्स के आधार पर 12 पद सृजित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। इस विंग से स्थानीय व आसपास के मरीजों को लाभ मिल सकेगा।

बहू की हत्या करने वाली सास को आजीवन कारावास

विधि संवाददाता। लखनऊ

27 वर्ष पूर्व अपने बेटे की दूसरी शादी करने के लिए अपनी बहू की हत्या कर लाश को जला देने के मामले में आरोपी सास कृष्णा देवी को सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे मोहम्मद कमरुज्जमा खान ने इस पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका है।

घटना की एफआईआर मृतका के ससुर राजेंद्र सिंह ने थाना माल में दर्ज कराई थी। लेकिन उसने इस मामले में अपने विरोधियों को नामजद कर दिया था। आरोप लगाया था कि उधारी वापस मांगने पर गांव के अरुण, रतिभान व आनंद सिंह आदि मेरे घर आए। दरवाजे पर बैठी मेरी मां को गाली देने लगे। मां ने विरोध किया तो उन्हें लाठी से मारने लगे। उनके चिल्लाने पर मैं व मेरी पत्नी कृष्णा दौड़कर छुड़ाने आए तो हमदोनों को भी मारने लगे। चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग बचाने दौड़े तो अरुण और आनंद ने मेरे ही घर में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर मेरी बहू विमलेश को छत पर ले गए और उस पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि से हुआ असली आरोपियों का खुलासा

सरकारी वकील शशि पाठक के मुताबिक विवेचना के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि से पता चला कि इस घटना को खुद राजेंद्र सिंह, उसकी पत्नी कृष्णा देवी व पड़ोसी मनोज ने अंजाम दिया था। क्योंकि कृष्णा देवी अपनी बहू विमलेश सिंह को पागल समझती थी। इसलिए वह अपने बेटे संजय सिंह की दूसरी शादी मनोज की चचेरी साली से करना चाहती थी। इसके लिए विमलेश को प्रताड़ित भी किया जाता था। विवेचना के पश्चात पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ हत्या आदि की धारा में आरोप पत्र दाखिल किया। 20 अप्रैल 2001 को अभियुक्तों पर आरोप तय हुआ। अदालत ने दौरान विचारण राजेंद्र सिंह को विक्षिप्त करार देते हुए उसके विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही स्थगित कर दी। जबकि मनोज को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

रक्षा सम्पदा संगठन का स्थापना दिवस सम्पन्न

सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी हुए सम्मानित

प्रधान निदेशक भावना सिंह ने राष्ट्र के विकास में रक्षा सम्पदा संगठन के योगदान पर प्रकाश डाला

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा, मध्य कमान, लखनऊ छावनी में बुधवार को रक्षा सम्पदा स्थापना दिवस, 2024 का आयोजन किया गया। प्रधान निदेशक भावना सिंह इस समारोह की मुख्य अतिथि थी। निदेशालय के अधिकारियों ने सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया और साथ ही उनके सेवाकाल में किए गए योगदान की सराहना की। इस अवसर पर छावनी परिषद्, लखनऊ के छात्र-छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें गणेश-वन्दना, राधा-कृष्ण नृत्य एवं सूफी नृत्य, इत्यादि कार्यक्रम शामिल थे।

भावना सिंह, प्रधान निदेशक द्वारा सभी वर्तमान एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी गई एवं राष्ट्र के विकास में रक्षा संपदा संगठन के योगदान पर प्रकाश डाला गया। एन.वी. सत्यनारायण, निदेशक, डा. डी.एन. यादन, निदेशक, श्री पुष्पेन्द्र सिंह, निदेशक एवं श्री अजय कुमार, संयुक्त निदेशक भी इस मौके पर उपस्थित थे। प्रधान निदेशिका ने बताया कि 16 दिसम्बर, 1926 के दिन कैंटोनमेंट्स डिपार्टमेंट के संविधान का गठन हुआ था। इसीलिए रक्षा सम्पदा संगठन ने छावनी विभाग की गठन की स्मृति में 16 दिसम्बर को रक्षा सम्पदा दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारम्भ किया। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व छावनी अधिनियम 1924 का सृजन हो चुका था परन्तु छावनी की कार्यप्रणाली की लम्बी श्रृंखला में 'सेना भूमि एवं छावनी' सेवा कहलाने के उपरान्त वर्ष 1983 में भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा का गठन हो सका है। वर्तमान में 62 छावनियों के अधीन स्थित रक्षा भूमि का प्रबन्धन और नियंत्रण उत्कृष्ट रूप में किया जा रहा है। छावनी के बाहर सैन्य स्टेशनों, एअर फील्ड्, फायरिंग रेन्ज के रूप में लगभग 20 लाख एकड़ भूमि विद्यमान है जिसका प्रबन्धन रक्षा सम्पदा अधिकारियों एवं मुख्य अधिशासी अधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है। इसके भूमि का अधिग्रहण एवं रक्षा भूमि का पट्टाकरण, ओल्ड ग्राण्ट शर्तों के अधीन रक्षा भूमि का आबंटन रक्षा भूमि से अतिक्रमण का हटाया जाना एवं छावनी परिषद की कार्यप्रणाली के अधीन छावनी एवं सिविल क्षेत्र में साफ-सफाई के साथ बड़े स्तर पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लाट की स्थापना द्वारा छावनी एवं सम्बद्ध नागरिक क्षेत्रों बृहत स्तर पर जल-आपूर्ति एवं असैन्य नागरिकों को शुद्ध एवं निर्मल वातावरण उपलब्ध कराने में असाधारण उपलब्धि प्राप्त हुई है।

जोनल लेवल स्पीच कंपटीशन आज

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद-2025 जोनल लेवल स्पीच कंपटीशन का आयोजन गुरुवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय एवं समाज कार्य विभाग में ऑनलाइन मोड में आयोजित होगा। क्षेत्रीय स्तर आयोजित प्रतियोगिता में 16 विश्वविद्यालय के 200 प्रतिभागी इस जोनल लेवल कंपटीशन में शामिल होंगे।

निर्णायक मंडल में 16 सदस्य हैं और 16 उनके सहयोगी सदस्य द्वारा सर्वश्रेष्ठ विजेता प्रतिभागी का चयन किया जाना है। इस जोनल लेवल कंपटीशन को जोनल कोऑर्डिनेटर (पीएसजी) डॉक्टर हेमेंद्र कुमार सिंह तथा फैकेल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (पीडीपी) के संयोजक श्री रमाकांत जी तथा संकायाध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश कुमार के कुशल मार्गदर्शन में क्षेत्रीय स्तर प्रतियोगिता आयोजित की गई है। बता दें कि पिछले दिनों शिक्षा संकाय में जल, जंगल, जमीन, जानवर, और जन विषय पर दो दिवसीय डिबेट कंपटीशन का आयोजन किया गया था। जिसमें लविवि के विभिन्न विभागों से लगभग 35 प्रतियोगियों ने प्रतिभाग किया था।

निर्णायक मंडल ने कुल 10 विजेता प्रतिनिधियों का चयन किया जो जोनल लेवल कंपटीशन में प्रतिभाग करेंगे अर्थात यह 10 विजेता प्रतिभागी लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि (पीएसजी) तथा फैकेल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) तथा शिक्षा संकाय द्वारा इस कार्यक्रम को संपादित कराए जाने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी का दायित्व दिया गया है। जो लखनऊ विश्वविद्यालय के एनवायरमेंटल नोडल ऑफिसर (इएनओ) को अब जोनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है। क्षेत्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता का विषय नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है। प्रतियोगिता में जो विवि शामिल होंगे, उनमें लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, छात्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा, रज्जू भैया राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय इलाहाबाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ, ज्योतिबा फूले रोहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, हीगिम्बटॉम यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंस प्रयागराज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध कॉलेज वाराणसी, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ शामिल है।

नौ वर्षीया अर्यमा शुक्ला ने बगैर देखे किया संपूर्ण श्रीमद्भगवत गीता का पाठ

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

गीता जयंती के अवसर पर बुधवार को रामकृष्ण मठ में अर्यमा शुक्ला (उम्र 9 वर्ष) ने संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता का पाठ बैगर देखे किया। अर्यमा शुक्ला ने 2 घंटे 10 मिनट के समयान्तराल बिना किसी विराम के अखण्ड गीता पाठ पूर्ण किया। पाठ पूर्ण होने के उपरांत उपस्थित लोगों को श्रीमद् भगवत गीता की प्रतियां भी भेंट की। रामकृष्ण मिशन के अधक्ष्य स्वामी मुक्तिनाथानंद ने अर्यमा को अपना आशिर्वाद दिया और कहा कि अर्यमा असाधारण प्रतिभा है। ऐसी बाल प्रतिभा नई पीढ़ी के लिए अनुकरणीय है। भारतीय संस्कृति की परंपरा के प्रति गौरवबोध जगाने के लिए प्रेरक भी है। उल्लेखनीय है कि अर्यमा शुक्ला कक्षा 4 की छात्रा हैं और लगातार नए- नए कीर्तिमान स्थापित करती रहती हैं। अर्यमा को संस्कृत में संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता के साथ साथ संपूर्ण श्रीदुर्गा सप्तशती और भी अनेक महामंत्र कंठस्थ हैं। अर्यमा को देश की अनेक विभूतियों समेत उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जगद्गुरु श्री रामभद्राचार्य ने भी आशीर्वाद और अपना स्नेह प्रदान किया है।

गैंगस्टर को तीन वर्ष की कैद

विधि संवाददाता। लखनऊ

गैंगेस्टर के एक मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त गोविंद पासी को विशेष अदालत ने तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे उप्र गिरोहबंद और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 2/3 में दोषी करार दिया है। गैंगस्टर एक्ट के विशेष जज पुष्कर उपाध्याय ने इस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वर्ष 1997 में गैंगेस्टर का यह मुकदमा प्रभारी निरीक्षक विष्णु दयाल यादव ने थाना इटौंजा में दर्ज कराई थी। विशेष लोक अभियोजक लक्ष्मण प्रसाद दीक्षित के मुताबिक इसका सुसंगठित गिरोह है। यह अपने व अपने गिरोह के साथियों के दुनियावी लाभ के लिए समाज में आतंक व भय का माहौल बनाकर अपराधिक कृत्य करता है। यह अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी, लूट, नकबजनी व आर्म्स सप्लाई जैसे आपराधिक कृत्य करता था। यह आदतन अपराधी है। इसके गिरोह की डर की वजह से किसी की हिम्मत इसके बारे में बोलने की नहीं होती है। इसके विरुद्ध आम लोग मुकदमा लिखाने व गवाही देने से डरते हैं।

गाय के दूध के उत्पादन में भी नंबर वन बनेगा यूपी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

रंग ला रही है राज्य सरकार की गोसंरक्षण और गोसंवर्धन की पहल

गोवंश का गोरक्षपीठ की परंपरा रही है। गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर की गोशाला इसका प्रमाण है। गोवंश की देशी प्रजातियों के लिहाज से ये गोशाला बेहद समृद्ध है। पीठ की परंपरा के अनुसार गोवंश का संरक्षण मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर के रूप में योगी आदित्यनाथ की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निराश्रित गो वंश का संरक्षण, गो पालकों कई तरह की रियायत और देना इसी की कड़ी है। इसी तरह गोवंश निरोग रहें इसलिए उनका नियमित टीकाकरण, नस्ल सुधार, इसके जरिए उनकी उत्पादकता बढ़ाने काम भी योगी सरकार लगातार कर रही है।

गोवंश के संरक्षण और संवर्धन का ये सिलसिला जारी रहा तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश गाय के दूध के मामले में भी देश नंबर वन होगा। अभी यह उपलब्धि राजस्थान के नाम पर दर्ज है। उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में दुधारू गायों की संख्या करीब 0.66 करोड़ है। इनसे कुल 5.29 मिलियन टन दूध प्राप्त होता है। प्राप्त दूध में विदेशी नस्ल की गायों का दूध 1.7 मिलियन टन और मिश्रित एवं देशी नस्ल के दूध की मात्रा 4.2 मिलियन टन है।

चूंकि देशी नस्ल की गाय का दूध विदेशी नस्ल की गायों से गुणवत्ता में बेहतर होता है। इनका विकास भारतीय जलवायु में हजारों वर्ष के अनुकूलन (कंडीशनिंग) के बाद हुआ है। लिहाजा भारतीय परिस्थितियों में इनको पालना आसान है। यही वजह है कि योगी सरकार का फोकस देशी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन पर ही है। आने वाले समय में गोरखपुर और भदोही के पशु चिकित्सक महाविद्यालय के बन जाने पर देशी गोवंश के संरक्षण और संवर्द्धन को और बढ़ावा मिलेगा। यहां होने वाले शोध का लाभ उत्तर प्रदेश खासकर पूर्वांचल के दो दर्जन जिलों के पशुपालकों को मिलेगा। इसका लाभ देशी गोवंश की बढ़ी उत्पादकता के रूप में मिलेगा। ऐसे में 16 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूध के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखने वाला उत्तर प्रदेश गायों के दूध के उत्पादन के मामले में भी देश में पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। इसी मंशा से मुख्यमंत्री योगी ने पिछले दिनों गोरखपुर में बनने वाले पशु चिकित्सा महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि गोरखपुर पशु चिकित्सा महाविद्यालय को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाय। महाविद्यालय में पशुओं के रखने, चारागाह के लिए हो पर्याप्त रिजर्व लैंड हो। और गौ सरोवर भी बनाएं। गोरखपुर के ताल नदोर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी वर्ष 3 मार्च को किया था। 80 एकड़ में क्रमवार तीन चरणों मे बन रहे इस महाविद्यालय के निर्माण पर 350 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। पहले चरण के निर्माण पर 277 करोड़ 31 लाख रुपये खर्च होंगे। 2026 तक पहले चरण का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।

नवाचार के जरिए लविवि ने बनाई खास

सभी राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों में 41वें स्थान पर एलयू

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

लखनऊ विश्वविद्यालय ने शैक्षिक क्षेत्र में डिजिटल सहभागिता के नए मानक तय किये हैं। यह बात यूनिरैंक 2024 में उसकी शानदार प्रदर्शन से साफ झलकती है। आज के दौर में जहाँ पारदर्शिता, सटीक जानकारी और समय पर अपडेट मिलना जरूरी है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन सभी मामलों में अपनी खास पहचान बनाई है वहीं,विश्वविद्यालय की सोशल मीडिया उपस्थिति और सामाजिक सहभागिता इसकी मजबूत रैंकिंग के प्रदर्शन से साफ देखी जा सकती है।

रैंकिंग के अनुसार लखनऊ विश्वविद्यालय ने सभी राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों में 41वां स्थान प्राप्त किया है और देश के नियमित विश्वविद्यालयों में 16वां स्थान प्राप्त किया है। यूनि-रैंक द्वारा प्रकाशित विभिन्न सोशल प्लेटफ़ॉर्मों पर उपस्थिति के आधार पर, विश्वविद्यालय ने ट्विटर पर शैक्षिक संस्थानों में 17वां स्थान और नियमित विश्वविद्यालयों में 5वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं, यूट्यूब पर यह संस्थानों में 34वें और नियमित विश्वविद्यालयों में 18वें स्थान पर है। विश्वविद्यालय रियल-टाइम इंटरैक्शन और पारदर्शी संवाद से जरिये यह सुनिश्चित करता है कि छात्र, पूर्व छात्र और आम जनता इसकी शैक्षणिक पहलों, शोध उपलब्धियों और सामाजिक योगदानों से जुड़ी जानकारी से हमेशा अपडेट रहें। शिमागो इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग भी विश्वविद्यालय के इस प्रदर्शन की पुष्टि करती है। जिसमें विश्वविद्यालय ने सभी शैक्षणिक संस्थानों में 91वां और सामाजिक प्रभाव के मामले में देश के नियमित विश्वविद्यालयों में 21 वां स्थान प्राप्त किया था। यह इस बात की तस्दीक करता है कि विश्वविद्यालय एक जिम्मेदार संस्थान के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। और अपने संसाधनों का इस्तेमाल सही जानकारी और पारदर्शिता के साथ वैश्विक चुनौतियों से निपटने में करता है।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने कहा, यह रैंकिंग हमारे लगातार किए गए प्रयासों का नतीजा है। हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पारदर्शिता और नवाचार के जरिए नेतृत्व करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रों की जरूरतों को समझते हुए और समाज में अपना योगदान देते हुए, ऑनलाइन और ऑफलाइन, हर जगह अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि विश्वविद्यालय की 24×7 सोशल मीडिया उपस्थिति बनी रहे, ताकि हर सवाल का जवाब समय पर दिया जा सके और हर जानकारी तुरंत पहुंचाई जा सके।

पायनियर
लखनऊ, बृहस्पतिवार, 12 दिसंबर , 2024

स्कूल-कॉलेजों में सिगरेट व तंबाकू के खिलाफ मुहिम

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद विनियमन अधिनियम के उल्लंघनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे : एलजी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान शुरू करने के बाद, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली में विशेष रूप से छात्रों और युवाओं के बीच, तंबाकू-मुक्त, स्वस्थ और सुरक्षित शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है।

हाल ही में हुई राज्य स्तरीय समिति नारको कोऑर्डिनेशन सेंटर की 9वीं समीक्षा बैठक के बाद, सक्सेना ने शिक्षा निदेशालय और उच्च शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए तंबाकू-मुक्त दिशा निर्देशों के सख्त कार्यान्वयन के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव को इन दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने और प्रत्येक संस्थान में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। इन नोडल अधिकारियों के नाम और संपर्क सूत्र हर संस्थान में प्रमुख रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे। एनसीओआरडी बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन पर प्रतिबंध और व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के नियमन) अधिनियम, 2003 के अनुपालन की निगरानी करने और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए नोडल अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया था। सक्सेना के निर्देश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में हैं, जो शैक्षिक संस्थानों के लिए अनिवार्य हैं।

प्रमुख स्थानों पर जागरूकता संकेतों का प्रदर्शन करना

अपने स्टाफ से तंबाकू मॉनिटर्स की नियुक्ति करना, जो एक अधिकारी, शिक्षक या छात्र प्रतिनिधि हो सकता है। तंबाकू-मुक्त क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए 100 गज के क्षेत्र को चिह्नित करना। शैक्षिक संस्थानों के 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर जुर्माना वसूलने के लिए सभी विभाग प्रमुखों संस्थान प्रमुखों को अधिकृत किया गया है। शैक्षिक संस्थानों के प्रमुखों को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा 4 के तहत जुर्माना लगाने और वसूलने का भी अधिकार होगा। उपराज्यपाल सचिवालय द्वारा मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने, तंबाकू सेवन निवारण कार्यक्रमों का आयोजन करने, और छात्रों तथा कर्मचारियों को काउंसलिंग और समर्थन सेवाएं प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया गया है।

सूची में मतदाताओं नाम हटाने का मुद्दा

आप का प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग पहुंचा

निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर वापस लौटते मुख्यमंत्री आतिशी, आप प्रमुख केजरीवाल व अन्य। फोटो: रंजन डिमरी

● किया दावा, 3000 पन्ने के दिए सबूत

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (आप) के एक प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोपों को लेकर बुधवार को निर्वाचन आयोग से मुलाकात की।

बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा मतदाताओं, ज्यादातर दलित, अनुसूचित जाति और पूर्वांचल से संबंधित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश रच रही है। केजरीवाल ने दावा किया, हमने 3,000 पन्नों के सबूत सौंपे हैं, जिनसे पता चलता है कि कैसे भाजपा बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश रच रही है। निर्वाचन आयोग ने कई आश्वासन दिए जिनमें यह भी शामिल है कि उचित सत्यापन के बिना बड़े पैमाने पर नाम नहीं हटाए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मामलों में बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जांच की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति पांच से अधिक मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन करता है तो इसकी जांच संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने आप को संदिग्ध रूप से नाम हटाने का अनुरोध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। प्रतिनिधिमंडल में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और राघव चड्ढा तथा पार्टी नेता जैस्मीन शाह शामिल थे। केजरीवाल ने बैठक को सफल बताया और निर्वाचन आयोग का आभार व्यक्त किया। लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही आप ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर चुनाव को प्रभावित करने के लिए मतदाता सूची में हेरफेर के प्रयास का आरोप लगाया है।

अवैध वोट आप की शक्ति थे : भाजपा

नई दिल्ली। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी आप की घबराहट साफ दिखा रही है। आप संयोजक चाहें जितना शोर मचा लें भाजपा अवैध घुसपैठियों के मृतकों और नकली पतों पर बने वोटों के विरूद्ध अभियान चलाती रहेगी। पूर्व मुख्य मंत्री की स्थिती एक ऐसे हताश सेनापति जैसी है जिसे मालूम है की वह लड़ाई हार रहा है बस अब वह हार को ढंकने के बहाने ढूंढ रहे हैं। केजरीवाल का बुधवार को मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलने जाना उनकी घबराहट बौखलाहट का प्रमाण है। जनता हो या भाजपा कार्यकर्ता सब अपने घरों के आसपास के नकली वोट कटवाने में लगे हैं। दिल्ली वालों को जहां भी रोहिंगयों, बंग्लादेशियों या अन्य घुसपैठियों के वोट बनने की जानकारी मिल रही है वह उन्हें कटवाने के लिए खुद आपत्ति कर रहे हैं।

सुविधा: नरेला सब सिटी का होगा विकास

● खाली डीडीए फ्लैटों में पुलिस बीट स्थापित की जाएगी : उपराज्यपाल

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नरेला सब-सिटी में सुरक्षा और नागरिक बुनियादी ढांचे, सेवाओं की समीक्षा की और अपराधों की रोकथाम, सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे को रोकने और आवासीय सोसायटियों तथा क्षेत्र में संचालित उद्योगों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने एवं सुविधाओं को बढ़ाने के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए।

उपराज्यपाल ने न केवल दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवासीय सोसायटियों की सुरक्षा के लिए लगभग 500 पूर्व सैनिकों की तैनाती और पीसीआर वैन के माध्यम से नियमित गश्त काने को भी कहा। उन्होंने दिल्ली पुलिस को क्षेत्र में बदमाशों और अराजक तत्वों की पहचान के लिए एक विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। बैठक में डीडीए के उपाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ डीडीए अधिकारी, क्षेत्र के डीसीपी, डीएम और एमसीडी के जोनल डीसी उपस्थित थे। यह कदम उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की नरेला सब-सिटी के पुनर्विकास और इसे शैक्षणिक एवं खेल गतिविधियों का केंद्र बनाने की महत्वाकांक्षी योजनाओं का हिस्सा है। कार्यभार संभालने के बाद से ही उपराज्यपाल नरेला के विभिन्न आवासीय इलाकों में डीडीए के खाली फ्लैटों को रियायती और किफायती दरों पर लोगों को उपलब्ध कराने पर जोर दे रहे हैं। साथ ही, उन्होंने नरेला औद्योगिक क्षेत्र और बवाना तथा भोरगढ़ जैसे आस-पास के औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए व्यक्तिगत तौर पर पहल की है।

इस साल आईजीआई के पास 540 दलाल हुए गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दलाली के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। खास तौर पर विदेशी नागरिकों के साथ। दिल्ली पुलिस ने इस साल आईजीआई के पास से 540 दलालों को गिरफ्तार कर 254 वाहनों को जब्त किया है।

यह पिछले साल के 264 गिरफ्तारियों और 96 वाहनों की जब्ती के आंकड़ों से काफी अधिक है। दिल्ली पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली पर्यटन रोकथाम अधिनियम और पर्यटकों के खिलाफ कदाचार रोकथाम अधिनियम के तहत की गई गिरफ्तारियों में पिछले साल की तुलना में 48 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। दलाल अक्सर बिना सोचे-समझे यात्रियों को शिकार बनाते हैं, खासकर रात में, खुद को प्री-पेड टैक्सी ड्राइवर बताकर और सस्ती सेवाओं का झूठा वादा करते हैं। पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी ने कहा, ये भ्रामक प्रथाएं यात्रियों को उत्पीड़न, वित्तीय शोषण और सुरक्षा जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 373 दिल्ली से, 107 उत्तर प्रदेश, हरियाणा से 32 और बिहार से ग्यारह लोग गिरफ्तार किए गए तथा राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और सिक्किम से अन्य शामिल हैं

आप सरकार यमुना साफ करने में नाकाम : विजेंद्र

● बोले, केंद्र सरकार के 1,244 करोड़ रुपये का भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाई दिल्ली सरकार

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने यमुना में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी की सरकार यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने में नाकाम रही है। साथ ही नदी की साफ-सफाई के उसके दस सालों के पुराने वादों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार से मिली रकम और यमुना सफाई परियोजनाओं पर वर्ष 2013 से लेकर 2024 तक 11 सालों में 1,508 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में यमुना की स्थिति बद से बदतर हो गई है ।

गुप्ता ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि नवंबर 2024 में यमुना में फीकल कॉलिफॉर्म (मलमूत्र से होने वाला प्रदूषण) का लेवल चौंकाने वाले 79,00,000 एमपीएन/100 एमएल तक पहुंच गया, जो दिसंबर 2020 के बाद सबसे ज्यादा है । यह लेवल निर्धारित मात्रा 2,500 एमपीएन/100 एमएल की सीमा से 31,600 गुना अधिक है । ये आंकड़े केजरीवाल और उनकी सरकार की विफलता की कहानी बयां करते हैं। जिन्होंने बार-बार यमुना को स्वच्छ और पुनर्जीवित करने के झूठे वादे जनता के साथ हर साल किए हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नवंबर में एनजीटी में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, शहर में प्रतिदिन 792 मिलियन गैलन (एमजीडी) सीवेज उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 650 एमजीडी को ही ट्रीट किया जा रहा है। इसका मतलब है कि बड़ी तादाद में ट्रीट किये बिना ही सीवेज सीधे यमुना में छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार कॉलोनियों के सीवरों से निकलने वाले गंदे पानी को ट्रीट करने के लिये पर्याप्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने में नाकाम रही है ।

स्कूलों में एआई लैब लगाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने चुनिंदा स्कूलों में एआई लैब स्थापित करने की योजना बनाई है। सरकार ने इन लैब की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के वास्ते एजेंसियों को आमंत्रित किया है।

एक अधिसूचना में कहा गया है, "दिल्ली सरकार छात्रों के बीच उन्नत तकनीकी शिक्षाएवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए चयनित स्कूलों में एआई लैब स्थापित करने की योजना बना रही है। एआई लैब को तकनीकों को समझने और सिखाने के लिए तैयार किया गया है। योग्य एजेंसियों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने और प्राधिकरण के समक्ष अपनी एआई लैब की स्थापना करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

विस चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी आप : केजरीवाल

● आप प्रमुख ने पहले भी गठबंधन की बात नकारी थी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को अरविंद केजरीवाल ने नाकार दिया है।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। पहले भी तीन चुनाव अकेले लड़े थे और प्रचंड बहुमत के साथ जीते थे। आप प्रमुख ने कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना से इनकार किया है। आप प्रमुख ने पहले भी कांग्रेस से गठबंधन की बात नकारी थी। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठजोड़ की संभावना से बुधवार को एक बार फिर इनकार कर दिया। पहले चर्चा थी कि दोनों दल मिलकर यह चुनाव लड़ सकते हैं। सोशल मीडिया एक्स पर केजरीवाल ने कहा कि आप दिल्ली में अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ेगी। उनकी प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि दोनों पार्टियां फरवरी में होने जा रहे 70 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए हाथ मिला सकती हैं। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना से इनकार किया था। हाल में विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस के इन दो घटकों के बीच गठजोड़ को लेकर चर्चा तब शुरू हुई।

आप, कांग्रेस गठबंधन करें या अलग चुनाव लड़े हर निश्चित है : सचदेवा

नई दिल्ली। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा केजरीवाल और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर नूरा कुश्ती चल रही है। आप और कांग्रेस भलीभांति जानती हैं कि गठबंधन करें या अलग अलग लड़ें हार निश्चित है। 2013 में बच्चों की कसम खाकर गठबंधन सरकार बनाने वाले और फिर सभी ड्रामों के बाद भी लोकसभा चुनाव कांग्रेस से गठबंधन में लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल की किसी घोषणा पर अब लोगों को विश्वास नहीं है।

कांग्रेस इतनी मजबूत है कि अकेले जीत सकती है विस चुनाव : देवेंद्र यादव

नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि उन्होंने दिल्ली न्याय यात्रा के दौरान स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस विस चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करने की लोगों ने ठान लिया है, जबकि भाजपा को सत्ता से दूर रखने का फैसला दिल्ली वाले पहले से ही कर चुके हैं। देवेन्द्र ने कहा, कि उन्होंने केजरीवालऔर संजय सिंह के सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जेल में जाने के बाद पार्टी लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है।

डीएमआरसी-4 फेज: 40 किमी सुरंग का कर रहा है निर्माण

● दिल्ली मेट्रो रेल निगम 27 भूमिगत स्टेशन भी बना रहा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली मेट्रो रेल निगम चौथे चरण के विस्तार के तहत 40 किलोमीटर से अधिक के भूमिगत गलियारों का निर्माण कर रहा है जो पांच विभिन्न गलियारों में विकसित की जा रही कुल लाइनों का करीब आधा हिस्सा है। चौथे चरण में कुल 27 भूमिगत स्टेशनों का निर्माण कर रहा है।

डीएमआरसी के अधिकारी ने कहा कि डीएमआरसी पहले ही जनकपुरी पश्चिम से कृष्णापार्क तक दो करीब दो किलोमीटर के भूमिगत खंड के निर्माण का कार्य पूरा कर चुका है जो मैजेंटा लाइन का विस्तार है। दिल्ली मेट्रो अपने चौथे चरण के तहत 40.109 किलोमीटर नए भूमिगत गलियारे का निर्माण कर रही है। इस चरण में पांच अलग-अलग गलियारों में लगभग 86 किलोमीटर नई लाइनें बिछाई जा रही हैं।

अधिकारी ने कहा कि यह एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है क्योंकि भूमिगत गलियारे विभिन्न भू-स्तरों से होकर गुजर रहे हैं जैसे कि सदर बाजार, नबी करीम, महरौली बदरपुर रोड, अजमल खान पार्क, नई दिल्ली आदि में भीड़भाड़ वाले आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र। आम तौर पर डीएमआरसी पारंपरिक कट-एंड-कवर तकनीक का उपयोग करके भूमिगत मेट्रो स्टेशनों का निर्माण करता है, जबकि सुरंगों का निर्माण टनल बोरिंग मशीनों (टीबीएम) की मदद से किया जाता है।उन्होंने बताया कि टीबीएम एक ऐसी मशीन है जिसका इस्तेमाल मिट्टी और चट्टानों की विभिन्न परतों में गोल क्रॉस-सेक्शन वाली सुरंगें खोदने के लिए किया जाता है। उन्होंने बताया कि इन्हें कठोर चट्टान से लेकर रेत तक किसी भी चीज़ को भेदने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि तुगलकाबाद के पास एरोसिटी-तुगलकाबाद गलियारे पर एक छोटा सा हिस्सा भी एनएटीएम तकनीक (न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड) का उपयोग करके बनाया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि सुरंग बनाने की इस पद्धति का इस्तेमाल पहले भी निगम द्वारा बड़ी सफलता के साथ किया गया है।

संक्षिप्त समाचार

आईआईएसएसएम का वार्षिक ग्लोबल कॉन्क्लेव आज से

नई दिल्ली। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट (आईआईएसएसएम) का दो दिवसीय (12 और 13 दिसम्बर) 34वें वार्षिक वैश्विक कॉन्क्लेव 2024 बृहस्पतिवार से द्वारका स्थित होटल ताज विवांता में आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी आईआईएसएसएम के कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व सांसद डॉ आर के सिन्हा ने यहाँ कान्स्टीट्यूशन क्लब में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में दी। डॉ सिन्हा ने बताया कि सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ करेंगे। इसके अलावा सम्मेलन में केंद्रीय कोयला और खनन राज्यमंत्री सतीश चंद्र दूबे, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी भाग लेंगे। इस अवसर पर असम सरकार के पूर्व पुलिस महानिदेशक जी एम श्रीवास्तव, डॉ संतोष कुमार, डॉ शकीला मर्चेंट, दिलीप कोटिया और जीबी सिंह भी मौजूद थे।

डीडीए को परियोजनाओं के लिए परामर्श देगा हुडको

नई दिल्ली। आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) आवासीय, वाणिज्यिक तथा संस्थागत परियोजनाओं के विकास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को परामर्श सेवाएं प्रदान करेगा। हुडको ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि उसने दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। हुडको डीडीए के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करेगा। साथ ही डीडीए द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के लिए अपनी परामर्श सेवाएं प्रदान करेगा।

मेट्रो में केबल चोरी करने वाले चार गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो में तार चोरी करने वाले 11 सदस्यीय गिरोह के कथित चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (परिवहन) विजय सिंह ने बताया, हमें दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) से पांच दिसंबर को तार चोरी होने के बारे में शिकायत मिली थी। चोरी के कारण मोती नगर और कीर्ति नगर स्टेशन के बीच ब्लू लाइन पर मेट्रो सेवाएं बाधित हो गईं थीं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की और दो वाहनों पर जांच केंद्रित किया।

यमुना में मल मूत्र संबंधी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर

● नदी मे प्रदूषण का स्तर वर्ष 2020 की तुलना मे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया : डीपीसीपी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर 2020 की तुलना में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है तथा असगरपुर में इसमें मल मूत्र से होने वाले प्रदूषण की सांद्रता प्रति 100 मिलीलीटर पर 79,00,000 ईकाई (एमपीएन) तक पहुंच गई है। असगपुर में ही यमुना दिल्ली से बाहर निकलती है। नवंबर के लिए जारी नवीनतम जल गुणवत्ता रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के आंकड़ों से पता चला है कि यह आंकड़ा अक्टूबर में दर्ज किए गए शीर्ष स्तर से मेल खाता है, जो दिसंबर 2020 के बाद से सबसे अधिक सांद्रता थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार मल मूत्र संबंधी प्रदूषण के प्रतीक फीकल कोलीफॉर्म की मान्य सीमा प्रति 100 मिलीलीटर पर 2500 इकाई है। मल मूत्र संबंधी प्रदूषण के उच्चतम स्तर का अंतिम दर्ज उदाहरण दिसंबर 2020 है जब सांद्रता प्रति 100 मिलीलीटर पर 120 करोड़ इकाई तक पहुंच गई थी। डीपीसीसी की मासिक गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार यमुना पल्ला में दिल्ली में प्रवेश करती है और वहां फीकल कोलीफॉर्म 1100 इकाई प्रति 100 मिलीलीटर है और जब नदी आगे बढ़ती है जो उसमें मल संबंधी सांद्रता जलमल वाली नालियों के यमुना में गिरने के कारण बढ़ती चली जाती है। डीपीसीसी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश पर यह रिपोर्ट जारी करती है।

नदी के पानी में घुली ऑक्सीजन (डीओ) का स्तर पल्ला (6.1 मिलीग्रामालीटर) और वजीराबाद (5.2 मिलीग्रामालीटर) में स्वीकार्य सीमा के भीतर बताया गया, जो जलीय जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हालांकि, आईएसबीटी पुल पर ऑक्सीजन स्तर घटकर शून्य हो गया है और दिल्ली से बाहर निकलने तक वह शून्य ही रहा। शून्य डीओ स्तर आमतौर पर मृत नदी पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है।

सिसोदिया की जमानत शर्तों में कोर्ट ने दी ढील

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार एवं धन शोधन मामलों में सप्ताह में दो बार जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। उच्चतम न्यायालय ने सिसोदिया की जमानत शर्तों में बुधवार को ढील दे दी।

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने इन शर्तों को अनावश्यक बताते हुए इनमें ढील दे दी। पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता को सुनवाई में नियमित रूप से उपस्थित होना होगा। उच्चतम न्यायालय ने 22 नवंबर को सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा था।

भारत का संविधान सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित:ओझा

अधिवक्ता परिषद काशी प्रांत की उच्च न्यायालय इकाई प्रयागराज की ओर से संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित

प्रयागराज। अधिवक्ता परिषद काशी प्रांत की उच्च न्यायालय इकाई प्रयागराज की ओर से बुधवार को संविधान दिवस का आयोजन बार एसोसिएशन के लाइब्रेरी हॉल में किया गया। मुख्य अतिथि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा एवं विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश राय रहे। कार्यक्रम का आरंभ अतिथियों के मंच पर आगमन एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। मुख्य अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा ने संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए कहा कि भारत का संविधान सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है। भारत के संविधान का कोई भी उपबंध कहीं से आयात नहीं किया गया है। वरन भारत के प्राचीन संस्कृति सभ्यता के आधार पर संविधान का निर्माण हुआ है। अनुच्छेद 14 की विस्तृत व्याख्या करते हुए उन्होंने समानता और समरसता के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने संविधान सभा की चर्चाओं का अध्ययन करने का सुझाव भी दिया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश राय ने संविधान निर्माताओं के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा करते हुए संविधान सभा के प्रथम प्रस्ताव पर डॉ भीमराव अम्बेडकर विचार को उदधृत किया। उन्होंने समाज में अधिवक्ता परिषद की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि अधिवक्ता परिषद अधिवक्ताओं का संगठन होते हुए समाज के लिए कार्य करता है। उन्होंने अधिवक्ता परिषद की राष्ट्र निर्माण में भूमिका को उदधृत करते हुए बताया कि अपने स्थापना काल से ही अधिवक्ता परिषद ने सदैव समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाने हेतु कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भारत में समाज कभी जाति व्यवस्था आधारित नहीं रहा। संविधान के विभिन्न उपबंधों पर विस्तृत परिचर्चा करते हुए उन्होंने समानता बंधुत्व और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। मुख्य स्थाई अधिवक्ता द्वितीय उत्तर प्रदेश सरकार डॉ राजेश्वर त्रिपाठी ने भी अपने विचार व्यक्त किए।कार्यक्रम की अध्यक्षता इकाई की अध्यक्ष राजकुमारी ने की। कार्यक्रम का संचालन विनायक पाण्डेय ने किया। अतिथि परिचय एवं स्वागत वत्सला उपाध्याय तथा धन्यवाद ज्ञापन एवं कार्यक्रम के समापन की घोषणा मुख्य स्थाई अधिवक्ता द्वितीय उत्तर प्रदेश सरकार डॉ राजेश्वर त्रिपाठी ने की। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस मौके पर मुख्य स्थाई अधिवक्ता चतुर्थ शीतला प्रसाद गौड़ अधिवक्ता परिषद काशी प्रांत के महामंत्री नीरज कुमार सिंह सौमित्र द्विवेदी विजय प्रकाश मिश्रा सुरेंद्र नाथ शुक्ला सृष्टि शशि वाला महामंत्री उच्च न्यायालय इकाई वरुण सिंह सात्विक त्रिपाठी प्रतीक राय संदीप सिंह आदि उपस्थित रहे।

पीडियाट्रिक टीवी को रोकने के लिए आयोजित की गई प्रशिक्षण कार्यशाला

मीरजापुर। पीडियाट्रिक टीवी को लेकर जिला क्षय रोग कार्यालय के नेतृत्व में वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स संस्था के सहयोग से एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में किया गया। जिसमे समस्त सामुदायिक स्वास्थय केन्द्रो की मेडिकल ऑफिसर और निजी बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों को बच्चो में होने वाली टीवी की जांच और उपचार हेतु प्रशिक्षण दिया गया।राज्य स्तर पर प्रशिक्षित जिला चिकित्सालय के डॉक्टर पंकज पांडेय एवं मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर अक्षय दयाल यादव ने विस्तृत रूप से पीडियाट्रिक टीवी के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अनील कुमार ओझा ने की। डॉक्टर ओझा ने कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कहा की बच्चो में टीवी के लक्षण दिखने पर तत्काल डॉक्टर से परामर्श लें। समय पर टीवी रोग की पहचान होने से न सिर्फ इसे फैलने से रोक सकते है बल्कि रोगी बच्चों के जीवन को भी सुरक्षित कर सकते है। टीबी का पूर्ण इलाज हर स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। इस दौरान डब्लू एच ओ कंसल्टेंट डॉक्टर गायत्री ने कहा की बच्चो में टीबी संभधित लक्षण दिखते ही जांच कराए।

गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही में उपबंध के पालन के आदेश के अनुपालन के उठाए गए कदमों की जानकारी तलब

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों का पालन किए बगैर गैंग चार्ट तैयार करने के मामले में 17 अक्टूबर 24 को दिए आदेश के अनुपालन में उठाए गए कदमों की रिपोर्ट मांगी है और जिलाधिकारी और एस पी कौशांबी के अनुमोदन से नोडल अधिकारी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही पुलिस को याची के विरूद्ध विवेचना पूरी करने का भी आदेश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने विनय कुमार गुप्ता की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अरविंद कुमार मिश्र व देवेंद्र मिश्र ने बहस की। अपर महाधिवक्ता पी के गिरी ने 2 दिसंबर 24 का कार्यालय ज्ञाप दिया और कोर्ट को बताया कि सरकार गैंगस्टर एक्ट के तहत दो चेक लिस्ट तैयार करती है। एक गृह विभाग तो दूसरी अभियोजन निदेशालय। केस तय होने पर अंतिम चेक लिस्ट तैयार की जाती है।

3दिसंबर को कोर्ट ने संयुक्त सचिव गृह को जांच अधिकारी नियुक्त किया था और जांच के प्रारंभिक निष्कर्ष के आधार पर 17 अक्टूबर के आदेश के पालन के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी। पुलिस को भी विवेचना पूरी करने को कहा था। किंतु विवेचना पूरी नहीं की गई है। जिस पर कोर्ट ने नोडल अधिकारी से उठाये गये कदमों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने 17 अक्टूबर के आदेश से गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करते समय उपबंध का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है।

यज्ञ कराता है शाश्वत सनातन ब्रह्म की प्राप्ति-डॉ. वी. सिंह

सोनभद्र। राबर्ट्सगंज नगर स्थित साईं अस्पताल के प्रांगण में बुधवार को गीता जयंती समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें गीता में वर्णित यज्ञ विषय पर आयोजित गोष्ठी में विद्वतजनों ने अपना विचार व्यक्त किया। इसके अलावा पांच विभूतियों को गीता प्रचार प्रसार सम्मान से सम्मानित किया गया। आयोजक मंडल की ओर से स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्य वक्ता गीता जयंती समारोह के संयोजक डॉक्टर वी. सिंह ने कहा कि गीता के अनुसार यज्ञ यौगिक क्रिया है। यह यज्ञ किसी तत्वदर्शी महापुरुष के सानिध्य में साधक के हृदय देश में मन और इंद्रियों के संयम द्वारा संपन्न होता है। यह शुद्ध साधना परक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि गीता के अनुसार 卐यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्卐 यज्ञ जिसे अवशेष छोड़ता है वह है अमृत। उसकी प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है। उस ज्ञानामृत को भोगने अर्थात प्राप्त करने वाले योगीजन शास्वत, सनातन परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अर्थात यज्ञ कोई ऐसी वस्तु है जो पूर्ण होते ही सनातन परब्रह्म में प्रवेश दिला देती है। संयोजक डॉ0 कुसुमाकर ने कहा कि गीता के अनुसार यज्ञार्थात्कर्मणो अन्यत्र लोकोअयं कर्मबंधन:। अर्थात यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। पूर्व में जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी ने इसी प्रकार यज्ञ कर्म को करके परम नैष्कर्म की स्थिति को प्राप्त किया है। पारस नाथ मिश्र ने कहा कि यज्ञ आध्यात्मिक प्रक्रिया है। बालेश्वर यादव ने यथार्थ गीता के आलोक में यज्ञ की विशद व्याख्या किया। आगन्तुकों का स्वागत अरुण चौबे ने किया। गोष्ठी का संचालन जगदीश पंथी ने किया। इस मौके पर उमाकांत मिश्रा आशुतोष कुमार रमेश प्रताप सिंह राणाप्रताप सिंह नरेन्द्र पांडे विमल कुमार चौबे दीपक कुमार केसरवानी गणेश पाठक चंद्रकांत तिवारी आदि मौजूद रहे।

सोनभद्र। गीता जयंती के अवसर पर गीता के अविनाशी योग के प्रचार-प्रसार में लगे पाँच महानुभावों को गीता जयंती समारोह समिति द्वारा सम्मानित किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता आत्म प्रकाश त्रिपाठी, प्रधानाध्यापक प्रदीप सिंह पटेल अध्यापक नरेन्द्र प्रताप सिंह रमेश थरड और मनीष कुमार श्रीवास्तव को समिति द्वारा सम्मानित किया गया।

क्विक न्यूज

संजय श्रीवास्तव केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन प्रयागराज के नए महाप्रबन्धक

प्रयागराज। संजय कुमार श्रीवास्तव केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन प्रयागराज के नए महाप्रबन्धक बनाए गए हैं। वर्ष 1988 बैच के आईआरएसई अधिकारी संजय कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को महाप्रबंधक केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन कोर प्रयागराज का पदभार ग्रहण कर लिया। संजय कुमार श्रीवास्तव महाप्रबंधक कोर का पदभार ग्रहण करने के पूर्व आर डी एस ओ लखनऊ में प्रधान कार्यकारी निदेशक इन्फ्रा वन ईडी ट्रैक के पद पर अक्टूबर 2021 से कार्य कर रहे थे। संजय कुमार श्रीवास्तव भारतीय रेल में कई अहम पदों पर अपनी सेवा दे चुके हैं। वह अप्रैल 2019 से अगस्त 2021 तक मंडल रेल प्रबंधक बीकानेर के पद पर तथा अप्रैल 2015 से अप्रैल 2019 तक कार्यकारी निदेशक गतिशीलता रेलवे बोर्ड के पद पर भी कार्यरत थे। यह जानकारी कल्याण सिंह मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी कोर प्रयागराज की ओर से दी गई।

गुरुकुलम स्कूल के पहले वार्षिक कार्यक्रम में विद्यार्थियों के सांस्कृतिक प्रदर्शन को सराहा गया

वाराणसी। गुरुकुलम स्कूल ने हाल ही में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया।जिसमें प्री.नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में पारंपरिक और आधुनिक प्रस्तुतियों का खूबसूरत संगम देखने को मिलाए जिसमें रचनात्मक कहानी.कथनए भूमिका.निर्वहनए और मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों के जरिए भारतीय शिक्षा के विकास को उजागर किया गया। विद्यार्थियों ने प्राचीन गुरुकुल प्रणाली से लेकर आधुनिक शिक्षा की यात्रा को दर्शायाए जिसमें समग्र शिक्षा और शिक्षक.छात्र के मजबूत संबंधों पर जोर दिया गया।गुरुकुलम स्कूल की प्रिंसिपलए प्रियंका मुखर्जी ने कहाए ष्हमारे वार्षिक कार्यक्रम ने हमारे विद्यार्थियों की रचनात्मकता और प्रतिभा को खूबसूरती से प्रस्तुत किया। यह उनके एक महीने की मेहनत का परिणाम है। हमें गर्व है कि अलख सर ने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। जहां शैक्षणिक उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैंए वहीं ऐसे कार्यक्रम भी विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और टीम वर्क को बढ़ाने में मदद करते हैं। गुरुकुलम स्कूल मेंए हम विद्यार्थियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैंए ताकि वे व्यक्तिगत और शैक्षणिक सफलता के लिए तैयार हो सकें।ष्अलख सर ने इस कार्क्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और विद्यार्थियों ने उनका स्वागत किया।

ओवर लोड कोल व ऐश परिवहन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई-जिलाधिकारी

सोनभद्र। जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह के अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में नॉन-अटेन्मेन्ट शहर अनपरा की वायु गुणवत्ता में निरन्तर सुधार किये जाने हेतु गठित सिटी इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी उद्योग से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक के दौरान ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान एवं सिटी एक्शन प्लान पर चर्चा की गयी, इस दौरान जिलाधिकारी ने शीत ऋतु में धूल कड़ों के उत्सर्जन से जनित स्मॉगिंग की स्थिति के नियंत्रण हेतु बनाये गये ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान के अन्तर्गत तैयार डेली एक्शन टेकेन रिपोर्ट पर सूचनायें प्रेषित किये जाने हेतु समस्त स्टेक होल्डर्स एवं सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योगों से जुड़ी इकाईयां एवं विभाग रोड डस्ट के समुचित निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें, इस मौके पर जिलाधिकारी ने तापीय परियोजनाओं

द्वारा कोल एवं ऐश का परिवहन मानकों के अनुरूप करने हेतु निर्देशित करते हुए कहा कि सभी परियोजनाएं नियमानुसार कोल एवं ऐश का परिवहन सुनिश्चित करें, ओवर लोड एवं मानक के विपरीत कोल एवं ऐश का परिवहन करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, उद्योगों एवं ऐश परिवहन करने वाले स्टेक होल्डरों को निर्देशित किया गया कि परिवहन के दौरान खराब हुये ट्रकों को शीघ्र रोड साइड से हटाकर उचित जगह पर रखा जाये, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न न हो एवं समस्त वाहनों को पी0यू0सी0 सर्टीफिक्रेट एवं फ्टिनेस सर्टीफिक्रेट लेने के उपरान्त ही संचालित किया जाये। उद्योगों में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का निरन्तर संचालन करने एवं उसकी नियमित मॉनीटरिंग करने हेतु जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया, जिससे वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। जिलाधिकारी ने नगर पंचायत अनपरा के अधिशासी अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि रोड से उड़ती डस्ट के नियंत्रण हेतु स्वीपिं जल छिड़काव एन्टी स्मॉग गन का प्रयोग निरन्तर किया जाये, बैठक में जिला विकास अधिकारी शेषनाथ चौहान उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग ओबरा एस0डी0ओ0 रेनुकूट क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र सहायक पर्यावरण अभियन्ता उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र एवं अनपरा क्षेत्र के उद्योगों के प्रमुख आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहें।

जिलाधिकारी ने श्रवण क्षेत्र धाम के पर्यटन विकास कार्यों का किया गहन निरीक्षण

अंबेडकरनगर । जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने श्रवण क्षेत्र धाम के पर्यटन विकास कार्यों का भौतिक निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने वहां पर स्थापित की जा रही भगवान श्री राम जी की मूर्ति एवं पार्क से संबंधित कार्यों में अधिक से अधिक मानव संसाधन एवं मशीनरी लगाकर तेजी से कराने तथा समस्त कार्यों को 14 दिसंबर तक पूर्ण करने हेतु कार्यदाई संस्था को निर्देशित किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने श्रवण क्षेत्र धाम के पौराणिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर पर्यटन सुविधाएं प्रदान करने हेतु वहां पर किए जा रहे पार्क एवं पर्यटन विकास के अन्य कार्यों का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मूर्ति के फिनिशिंग कार्य को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने मूर्ति के पास विकसित किया जा रहे पार्क के कार्यों

को भी तेजी से कराने तथा पार्क में आगंतुकों के बैठने हेतु आकर्षक बेंच एवं प्रकाश हेतु आकर्षक स्ट्रीट लाइट आदि लगाने के कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने कार्यों में आगणन की विशिष्टियों एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रवण क्षेत्र धाम को उसकी पौराणिक मान्यताओं के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के विजन के अनुसार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए एवं स्थानीय रोजगार का सृजन करते हुए वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के सपने को साकार रूप दिया जा रहा है। इस दौरान जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी कटेहरी अनुपम सिंह तथा कार्यदाई संस्था के पदाधिकारी मौके पर उपस्थित रहे।

सीडीओ ने ई-ऑफिस प्रणाली के संबंध में समीक्षा बैठक की:अंबेडकरनगर। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों एवम् पटल प्रभारियों को ई-ऑफिस से संबंधित समस्त कार्यवाहियों को आगामी चार दिवसों में पूरा करते हुए अपने-अपने विभाग,पटल से समस्त पत्रावलियों का परिचालन ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली का संचालन शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में सम्मिलित है।

आस-पास मे हो बाल विवाह तो तुरन्त करे काल

सोनभद्र। थाना राबर्ट्सगंज अंतर्गत धार्मिक स्थल दंडईत बाबा मंदिर व राम जानकी मन्दिर पर उपस्थित पंडित एवं पुजारीयो को बाल विवाह रोकथाम के प्रति जागरूक किया गया साथ ही उन्हें टीम द्वारा

बताया गया की अधिकांश धार्मिक स्थलों पर तमाम दर्शनार्थियों के समक्ष बाल विवाह होता है जब की बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत सीधे-सीधे अनुसंशा है की बाल विवाह में किसी भी तरह की भागीदारी दंडनीय अपराध है जिसके तहत किसी भी मंदिर धार्मिक स्थलों पर विवाह होने से पूर्व यह अवश्य जानकारी करे की बालक की उम्र 21 वर्ष व बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जिसके लिए उनके विधिक आयु प्रमाण पत्र की जांच के उपरांत ही विवाह की अनुमति प्रदान करे। क्यो की बाल विवाह एक ऐसी सामाजिक कुरीति है, जो कानून बनने एवं विभिन्न प्रावधानों के बाबजूद ज्यों के त्यों बनी हुई है जिसका असर बच्चों के पूरे जीवन चक्र को प्रभावित करता है। ओ आर डब्ल्यू शेषमणि दुबे द्वारा बताया गया कि अपने आस-पास के हो रहे बाल विवाह की जानकारी तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन की टोल फ्री नम्बर 1098 पर दिया जा सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाता है। मौके पर पर कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर से केंद्र प्रशासक दीपिका सिंह जिला बाल संरक्षण इकाई से संरक्षण अधिकारी रोमी पाठक गायत्री ओ आर डब्लू शेषमणि दुबे चाइल्ड हेल्प लाइन से काउंसलर अमन सोनकर सुपरवाइजर सुधा गिरी मंदिर के पंडित पुजारी तथा वहा उपस्थित दर्शनार्थी मौजूद रहे।

वैदिक रीति से 77 जोड़ों का हुआ सामूहिक विवाह

गाजीपुर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आई टी आई मैदान प्रकाशनगर में सम्पन्न हुआ। शादी समारोह का शुभारम्भं मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह एवं उपस्थित मंचाशीन अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। सामुहिक विवाह योजना में कुल 77 जोड़ो का सामुहिक विवाह पूरे विधि विधान के साथ सम्पन्न हुआ। सामुहिक विवाह के अवसर पर उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने नव विवाहित वर-वधुओं को उनके वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करते हुए शुभकामना दी। सामुहिक विवाह में नव दाम्पत्य को विवाह प्रमाण पत्र एवं पौध रोपण हेतु आम वृक्ष का पौधा उनके हाथो में दिया गया। विवाह कार्यक्रम मे मंच से ही मुख्य अतिथि ने बटन दबाकर 35 हजार रूपये की धनराशि वधुओ के खाते मे हस्तान्तरित किया।

मुख्य अतिथि जिला पंचायत

अध्यक्ष सपना सिंह ने नव विवाहित वर-वधुओ को आर्शिवचन देते हुए कहा कि नव विवाहित जोड़ो ने 7 फेरे लेकर एक साथ रहने का जो संकल्प लिया है उसे आजीवन निर्वहन करे। उन्होने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह कार्यक्रम योजना एक कल्याणकारी योजना है। जिसमे हजारो हजार की संख्या में बेटियों के हाथ पीले किये जा चुके है। मा0 मुख्यमंत्री जी ने इस योजना के माध्यम से गरीब, मजदूर एवं असहाय परिवारो को इसका लाभ दिया है और आगे भी इस योजना के माध्यम से बेटियो का विवाह सम्पन्न कराया जायेगा। मा0 मुख्यमंत्री जी ने बेटियो के हाथ पीले करने का जो संकल्प लिया है उसे आगे और भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होने कहा कि इस योजना के माध्यम से जो विवाह कराया जाता है उससे समाज मे फैली दहेज प्रथा जैसी रूढ़िवादी सोच समाप्त होती जा रही है। दहेज लेना और दहेज देना एक दण्डनीय अपराध है। उन्होने कहा कि आज जो भी बेटियां अपने ससुराल विदा हो रही है तो उनके ससुराल पक्ष के लोग उन्हे बहु न बल्कि बेटी बनाकर घर ले जाये। आज यह संकल्प लें कि बेटी से बड़ा कोई दहेज नही है। उन्होने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से बेटियों को बोझ समझने की जो एक मंशा या सोच रहती है, उन सभी कुरीतियों पर एक प्रहार है यह ''सामुहिक विवाह कार्यक्रम''। मिल बाट कर एक सादगी से भरे इस कार्यक्रम में परिणय सुत्र मे बध जाये और दहेज प्रथा तथा बेटियों को बोझ समझने की सोच से उबरकर, हम आगे बढ सके तथा बेटियों को समाज में उनको उचित स्थान दे सके यही मा0 मुख्यमंत्री जी की मंशा है।

मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य ने मा0 मुख्य मंत्री सामुहिक विवाह योजना की जानकारी देते हुए कहा कि आज जनपद के विभिन्न ब्लाको से चयनित 77 जोड़ो का विवाह पूरे विधि विधान के साथ सम्पन्न हुआ है। इसी क्रम से पिछले 05 दिसम्बर को 166 जोड़ो का विवाह कराया गया था। जनपद मे कुल 1575 जोड़ो का लक्ष्य प्राप्त है। शेष लक्ष्य को माह जनवरी 2025 मे सम्पन्न कराया जायेगा ताकि पात्र परिवारो की बेटियो को इस योजना का लाभ मिल सके।

संदिग्ध परिस्थितियों में लगी ठेले में आग से 50 हजार का नुकसान

चंदौली। मुग़लसराय कोतवाली अंतर्गत जीटी रोड स्थित गुरुद्वारा के सामने फुटपाथ पर खड़े ठेले में बुधवार की प्रातःसंदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया।इस बाबत ठेला स्वामी बच्चा मुगलसराय शाहकुटी निवासी ने बताया कि हमारा फास्ट फूड का ठेला है हर दिन की भांति हम अपने ठेले को बंद कर ठेला वहीं खड़ा कर घर चले गए थे।बुधवार की प्रातःहमें फोन आया कि तुम्हारे ठेले में आग लग गई जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया था। ठेले स्वामी ने बताया कि हमारे ठेले में आग किन परिस्थितियों से लगी इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पा रही है भुक्तभोगी की माने तो ठेले में लगी आग से लगभग ?50 हजार की क्षति हुई है।

अज्ञात वाहन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत

चन्दौली । अलीनगर थाना क्षेत्र के गंजख्वाजा गांव के समीप पैदल नेशनल हाईवे पार करते समय अज्ञात वाहन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शिनाख्त करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया।अलीनगर थाना क्षेत्र के बरहुली गांव निवासी सुद्धन बिन्द 45 वर्ष गंजख्वाजा आवश्यक कार्य हेतु जा रहा था। इसी दौरान पैदल नेशनल हाईवे पार करते समय अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई ।सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का शिनाख्त बरहुली गांव निवासी सुद्धन बिन्द के रूप में हुई। इसकी जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

ऊर्जा संरक्षण को लेकर चित्रकला प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

सोनभद्र। ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, एनटीपीसी सिंगरौली, शक्तिनगर के संत जोसेफस्कूल में राष्ट्रिय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के उपलक्ष्य में छात्रछात्राओं के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को ऊर्जा बचत के महत्व पर विचार करने और कला के माध्यम से इस विषय पर अपने रचनात्मक विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना था। यह कार्यक्रम एनटीपीसी सिंगरौली के ईईएमजी विभाग द्वारा शक्तिनगर टाउनशिप में स्कूल समुदाय को ऊर्जा संरक्षण में शिक्षित करने के उनके चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। यह प्रतियोगिता पूरे सप्ताह होने वाली कई गतिविधियों में से एक है। कार्यक्रम का समन्वय करने वाली उप महाप्रबंधक ऊर्जा एवं दक्षता प्रबंधन समूह मोनिका सिंह ने कहाकि हमारा लक्ष्य शिक्षा को रचनात्मकता के साथ जोड़ना है, छात्रों को ऊर्जा संरक्षण के महत्व को समझने में मदद करना और साथ ही उन्हें अपने विचारों को दृश्य रूप से व्यक्त करने का अवसर देना है।

ग्लोबल वार्मिंग

खतरनाक यथार्थ

वर्ष 2024 के रिकार्ड सबसे गरम साल होने की संभावना से ग्लोबल वार्मिंग खतरनाक यथार्थ बन गई है। यह बढ़ते जलवायु संकट के प्रति खतरनाक चेतावनी है। यूरोपीय संघ के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि 2024 के पहले 11 महीनों ने एक नया रिकार्ड कायम किया है जिससे यह साल शुरुआत से ही सबसे गरम साल बना रहा है। यह पहला साल होगा जब वैश्विक औसत तापमान पूर्व-औद्योगिक समय की तुलना में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ेगा। दुनिया भर के नेताओं ने चेतावनी दी है कि इस सीमा से आगे बढ़ने पर जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव सामने आ सकते हैं। इस खतरनाक यथार्थ को देखते हुए दुनिया को तेजी से जलवायु परिवर्तन आपातकाल का सामना करना पड़ सकता है जिसमें तत्काल आत्यन्तिक उपायों की आवश्यकता पड़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव पहले से ही सारी दुनिया में दिख रहे हैं। 2024 में मौसम के भयानक रूप से खराब होने के कारण अनेक समुदायों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है और व्यापक विनाश हुआ है। गंभीर सूखे ने इटली और दक्षिणी अमेरिका को प्रभावित किया, जबकि भयानक बाढ़ से नेपाल, सूडान और यूरोप में हजारों लोग विस्थापित हुए। लू के कारण मैक्सिको, सऊदी अरब और माली में हजारों लोगों की जानें गईं, जबकि समुद्री तूफ़नों ने अमेरिका और फ्लिीपीन्स में तबाही मचाई। ये घटनायें केवल कभी-कभी होने वाली घटनायें नहीं हैं, बल्कि वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि ये मनुष्यों द्वारा पैदा किए जलवायु परिवर्तन के स्पष्ट परिणाम हैं।

ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जन तथा फ़ासिल ईंधनों का जलाया जाना है। ये उत्सर्जन खतरनाक ढंग से वातावरण में गरमी को जकड़ लेते हैं जिससे वैश्विक तापमान खतरनाक गति से बढ़ रहा है। इस वार्मिंग पर लगाम लगाने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका उत्सर्जनों को 'नेट-ज़ीरो' स्तर तक लाना है। विभिन्न देशों ने आने वाले दशकों में यह लक्ष्य प्राप्त करने का इरादा दिखाया है। लेकिन 'हरित प्रतिज्ञाओं' के बावजूद वैश्विक कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जन इस वर्ष रिकार्ड ऊंचाई तक पहुंचने की आशा है। इस विरोधाभासी प्रवृत्ति से राजनीतिक वादों और यथार्थ के बीच की खाई दिखती है तथा जलवायु परिवर्तन घटाने के लिए सटीक कार्रवाई की आवश्यकता उजागर होती है। इस वर्ष संरा. जलवायु वार्ताओं ने वैश्विक जलवायु संकट से निपटने के लिए 300 बिलियन डालर के समझौते का लक्ष्य बनाया। लेकिन गरीब देशों ने इस समझौते की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि यह जलवायु संबंधी विभीषिकाओं से निपटने के लिए नाकाफी है। हालांकि, इस समझौते से थोड़ी प्रगति हो सकती है, पर यह स्पष्ट है कि वैश्विक प्रतिक्रिया अभी और गरमी से बचाने के लिए काफी नहीं है। जलवायु परिवर्तन में खराबी बढ़ने से इनकार करने वालों ने खासकर राजनीतिक क्षेत्र में इस संकट से निपटना और कठिन बना दिया है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खासकर ग्लोबल वार्मिंग की गंभीरता को अनदेखा किया है और उन्होंने अपने पूर्व कार्यकाल में अनेक पर्यावरणीय विनियमनों को समाप्त किया था। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका पेरिस समझौते से पीछे हट गया था, जबकि इस वैश्विक समझौते का उद्देश्य जलवायु संकट की समस्याओं को कम करना था। ऐसी कार्रवाइयों से असंदिग्ध रूप से जलवायु संकट की समस्या गंभीर होगी तथा पूरी दुनिया का तापमान बढ़ेगा। इससे उत्सर्जन में वृद्धि रोकना और कठिन हो जाएगा तथा पूरी धरती को ग्लोबल वार्मिंग के विनाशकारी प्रभावों से बचाना मुश्किल होगा। समय आ गया है कि इस मामले पर फ़ैरन कार्रवाई की जाए नहीं तो सार्थक परिवर्तन के लिए समय लगातार कम होता जा रहा है।

बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न

भारत को बांग्लादेश में उत्पीड़ितों की सुरक्षा हेतु निर्णायक कार्रवाई करते हुए अल्पसंख्यक अधिकारों, सांस्कृतिक पहचान तथा क्षेत्रीय स्थायित्व के रक्षक की अपनी भूमिका पर जोर देना चाहिए।

प्रशांत तिवारी
(लेखक, लोक नीति विशेषज्ञ हैं)

बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तनों तथा सरकार परिवर्तन के बहाने हिंदू अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न एक चिन्ताजनक प्रवृत्ति है जिससे सांप्रदायिक हिंसा उभरने के खतरनाक संकेत मिलते हैं। पिछले महीनों में व्यवस्थित रूप से हिंदुओं पर निशाना लगाने और उन पर अत्याचार की घटनाओं की खबरों में वर्तमान सरकार की भूमिका स्पष्ट होती है जिसके पीछे जमाते इस्लामी तत्वों का प्रभाव दिखाई देता है। ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू बहुसंख्यक देश तथा अल्पसंख्यक अधिकारों का रक्षक भारत निष्क्रिय भूमिका नहीं निभा सकता है।

इसके बजाय उसे निर्णायक व सक्रिय प्रतिक्रिया कर न केवल बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों, बल्कि स्वयं अपनी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी सुरक्षित करनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ व्यापक हिंसा की खबरें एक सुनियोजित आक्रमण का पैटर्न प्रदर्शित करती हैं। मंदिरों को अपवित्र करने तथा संपत्ति के विनाश के साथ ही हिंसा के ये कृत्य अलग-थलग घटनायें न होकर एक व्यापक व व्यवस्थित अभियान का हिस्सा हैं। इस विरोधाभास की जड़ें 1905 में 'बंगाल के विभाजन' में देखी जा सकती हैं जब उग्रवादी तत्वों ने इस क्षेत्र में इस्लामी सरकार बनाने का प्रयास किया था। हालांकि, 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति से इसमें अस्थाई बाधा आई, पर इस्लामी कानून द्वारा संचालित अवधारणा 'दारुल इस्लाम' का दृष्टिकोण अब पुन: पैदा हो गया है। वर्तमान सरकार के अंतर्गत उन ऐतिहासिक समस्याओं को हवा दी जा रही है जिनका प्रयोग हिंदू संस्कृति और जनसंख्या को समाप्त करने के लिए हथियार की तरह किया जा रहा है।

बांग्लादेश की सरकार, पाकिस्तानी आईएसआई, उग्र जिहादी समूहों तथा जमाते इस्लामी जैसे प्रभावशाली वैचारिक तत्वों के बीच कथित गठजोड़ के कारण स्थिति और खतरनाक होती जा रही है। ये शक्तियां बांग्लादेश की जनसंख्या संरचना बदलने तथा सांस्कृतिक परिदृश्य को अतिवादी विचारों से जोड़ने के व्यापक लक्ष्य के अंतर्गत काम कर रही हैं। इस संकट में नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस की विवादास्पद भूमिका केन्द्रीय भूमिका निभा रही है जिन्होंने सरकार के वैचारिक ध्रुवीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई है। हालांकि, उनको माइक्रोफाइनेंस में अग्रणी भूमिका निभाने के कारण वैश्विक स्तर पर सम्मान प्राप्त हुआ और विश्वसनीयता बढ़ी, पर हिंदू-विरोधी नीतियों से उनका जुड़ाव तथा बाहरी शक्तियों से उनका संबंध चिंता का कारण है जिसमें चीन तथा अमेरिका के कुछ समूह शामिल हैं। इन जुड़ावों से न केवल सरकार का साहस बढ़ा है, बल्कि वह लोकतंत्र व मानवाधिकार उल्लंघनों के नाम पर भारत की आलोचना भी कर रही है। इस भू-राजनीतिक षडयंत्रकारी राजनीति में कट्टरवादी गठबंधनों के साथ साफ्ट पावर भी शामिल है जो भारत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय स्तर पर स्थायित्व बनाए रखने वाली शक्ति के रूप में उसे चुनौती दे रही है।

भारत को सत्य तथा अल्पसंख्यक मानवाधिकार क रक्षक के रूप में अपनी स्थिति पर जोर देते हुए इस विमर्श का मुकाबला करना चाहिए। वर्तमान संकट वैसी ही चुनौतियां पेश कर रहा है जिनका सामना भारत ने 1971 में किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश की मुक्ति मानवतावादी व रणनीतिक उद्देश्यों से संचालित थी। इसके माध्यम से लाखों शरणार्थियों की रक्षा करते हुए उस सरकार को उलटा गया था जो नरसंहार कर रही थी। आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर निशाना लगाना वैसी ही मानवीय विभीषिका तथा रणनीतिक खतरा है। दुनिया में सबसे बड़ी हिंदू जनसंख्या के घर भारत पर खास जिम्मेदारी है कि वह विदेशों में रहने वाले अपने भाइयों और बंधुओं की रक्षा करे। नरेन्द्र मोदी सरकार के पास ऐतिहासिक अवसर है कि वह 1971 में हुए साहसी कृत्यों का अनुसरण करते हुए न्याय व क्षेत्रीय स्थायित्व के संरक्षक के रूप में भारत की भूमिका पुन: स्थापित करें।

संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया बहुआयामी होनी चाहिए जिसमें आक्रमण, राजनय व रणनीतिक समायोजन शामिल हो। भारत की सुरक्षा संरचना को प्रतिक्रियात्मक उपायों के दायरे से बाहर निकलना चाहिए। उसे दुष्ट तत्वों की पहचान कर उनका सफ़ाया करना चाहिए जिसमें बांग्लादेश के भीतर रहने वाले ऐसे तत्व शामिल हैं जो अल्पसंख्यकों पर हमले करते हैं। इससे भारत एक कठोर संदेश दे सकता है। इज़राइल की सटीक कार्रवाइयों की तरह लक्षित हमले एक प्रतिरोधक शक्ति के रूप में काम करते हुए भारत एक प्रतिरोधक की भूमिका निभाते हुए विदेशों में रहने वाले हिंदुओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दे सकता है। बांग्लादेश की भारत पर निर्भरता भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। रणनीतिक व्यापार प्रतिबंध तथा अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण को दिशा दे कर भारत बांग्लादेश की वर्तमान सरकार को अलग-थलग कर उसे अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर कर सकता है। इन प्रयासों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार उल्लंघनों को केन्द्रीय स्थान दे कर इस मामले में सारी दुनिया का समर्थन प्राप्त करना चाहिए। बांग्लादेश में दीर्घकालीन स्थायित्व ऐसी सरकार पर निर्भर है जो अल्पसंख्यक अधिकारों का सम्मान करे तथा लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के मूल्यों का आदर करे।

भारत को ऐसी उपयुक्त व समावेशी सरकार के उभरने में सहायता देनी चाहिए जो अतिवादी विचारधाराओं का मुकाबला कर सके। भले ही यह दृष्टिकोण विवादास्पद हो, पर यह भारत के रणनीतिक व मानवतावादी हितों के अनुकूल है। एक अधिक साहसी दृष्टिकोण में 1971 की जनसंख्या संरचना के यथार्थ पर गौर करने की आवश्यकता है जब बांग्लादेश की जनसंख्या में 21 प्रतिशत हिंदू थे। इस जनसंख्या के लिए सुरक्षित क्षेत्र प्रदान करने से अल्पसंख्यकों को सुरक्षित स्वर्ग मिलेगा तथा उनके प्रति हुए ऐतिहासिक अन्यायों का मुकाबला होगा। ऐसे समाधान से 1947 व 1971 जैसी क्षेत्रीय पुन: व्यवस्था हो सकती है जिससे समकालीन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। दुनिया भर के सभी हिंदुओं को इन अत्याचारों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। एक बिलियन से अधिक हिंदू जनसंख्या वाला भारत अपने उदाहरण से इस दिशा में नेतृत्व प्रदान कर सकता है। वह उत्पीड़न का मुकाबला करने की जीवन्त व्यवस्था बना सकता है। एकजुटता मजबूत करने के साथ ही सरकार की निर्णायक कार्रवाई दुनिया भर में अल्पसंख्यक अधिकार संरक्षण का उदाहरण बन सकती है। इस संकट ने भारत-बांग्लादेश संबंधों में परिवर्तन की आवश्यकता उजागर की है।

बांग्लादेश की मुक्ति में केन्द्रीय भूमिका निभाने के बावजूद बांग्लादेश की अनेक सरकारों ने शत्रुता और निष्क्रियता प्रदर्शित की है। इसे देखते हुए पड़ोसियों के प्रति भारतीय विदेश नीति में परिवर्तन की आवश्यकता स्पष्ट होती है। आर्थिक, सामाजिक, राजनयिक व मौद्रिक रणनीतियों के माध्यम से भारत इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। भारत को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि हिदुओं के खिलाफ हिंसा या शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपनी संप्रभुता तथा जनता के प्रति अडिग प्रतिबद्धता से इज़राइल भारत के लिए मूल्यवान सबक देता है। एक छोटा देश होने के बावजूद इज़राइल ने लगातार नागरिकों की रक्षा में अपने निर्णायक कार्यों की प्रभावशीलता स्पष्ट की है। विशाल संसाधनों तथा भू-राजनीतिक प्रभाव वाले भारत को ऐसी ही रणनीतियां अपना कर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे कर अपना क्षेत्रीय नेतृत्व स्थापित करना चाहिए। बांग्लादेश संकट एक क्षेत्रीय मुद्दे के बजाय भारत की विदेश नीति तथा एक राष्ट्र के रूप में उसकी पहचान का निर्णायक क्षण है।

साहसी और सक्रिय कदम उठा कर नरेन्द्र मोदी सरकार न्याय एवं मानवता के रक्षक के रूप में भारत की भूमिका मजबूत कर सकती है। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा केवल मानवता पर संकट को संबोधित करना नहीं है। इसका संबंध भारत की संप्रभुता पर जोर देने, अपनी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने तथा क्षेत्रीय स्थायित्व सुनिश्चित करने से भी है।

यूएनएचआरसी से हस्तक्षेप की उम्मीद किए बिना भारत सरकार को अवसर के अनुकूल उठ खड़े होना चाहिए। संकट को एक अवसर के रूप में संबोधित करने से दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका पुन: परिभाषित हो सकती है। निर्णायक कार्रवाई से भारत इतिहास को दुहराने से रोक सकता है, न्याय सुनिश्चित कर सकता है तथा अल्पसंख्यक अधिकार सुरक्षित करने की अपनी विरासत मजबूत कर सकता है।

संगठनों में परिवर्तन की आवश्यकता

"तकनीक दुनिया को बहुत तेजी से बदल रही है, ऐसे में संगठनों को प्रासांगिक बने रहने के लिए अपने भीतर परिवर्तन करने चाहिए।

रवि वलूरी
(लेखक, रेलवे से संबद्ध हैं)

यह देखना महत्वपूर्ण है कि संगठनों का ढांचा क्या है और वे कैसे काम करते हैं। लंबे समय से संगठनों ने अपनी रचना ऐसे लोगों के आधार पर की है जो प्रयोग करने, खोजने तथा तकनीक को गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं। इससे संगठन जीवन्त बने रहते हैं। तकनीक और उसके विभिन्न स्वरूप बदलने के साथ ही उसके अनेक प्रयोग समाने आते हैं।

इससे संक्षिप्त और लगभग अनजान स्तर पर उपकरणों का प्रयोग बहुत उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। ऐसे परिदृश्य में मनुष्य और संगठन विभिन्न प्रकार के उत्पादों और उनके स्वरूपों से प्रभावित होंगे। अब मानव मस्तिष्क केवल टाइपराइटर की तरह काम नहीं करता है। ऐसे में संगठनात्मक सिद्धान्त और व्यवहार के क्षेत्र में अनेक विद्वान लोग अपना योगदान देते हैं। इन प्रमुख लोगों में आडम स्मिथ, चार्ल्स बाबेज और राबर्ट ओवेन ने अत्यन्त उल्लेखनीय जमीनी कार्य किया है। आडम स्मिथ ने यह तर्क दिया कि देश और संगठन श्रम विभाजन से पैदा परिणामों का लाभ उठाएंगे और उसके अनुसार स्वयं को बदलेंगे। इसे 'विशेषज्ञताकरण' का नाम दिया गया। चार्ल्स बाबेज ने अपने महत्वपूर्ण कार्य से यह अवधारणा सामने रखी कि श्रम विभाजन के कारण काम या कौशल सीखने में लगने वाले समय में भारी कमी आएगी।

इससे शुरुआती चरण में ही सामग्री की बरबादी बहुत कम हो जाती है। इससे दिमाग ऐसे काम करने के लिए तैयार हो जाता है जिनमें बेहतर कौशलों की आवश्यकता होती है। 1789 में 18 वर्ष की आयु में राबर्ट ओवेन एक फैक्ट्री के मालिक बन गए थे। वे अपने समय से बहुत आगे एक कल्पनावादी थे। 1825 में

उन्होंने काम के नियमित घंटे, बाल श्रम कानूनों, सार्वजनिक शिक्षा तथा अनेक सामुदायिक परियोजनाओं में बिजनेस की सहभागिता की अवधारणायें सामने रखी थीं, जो सीएसआर का पूर्व रूप था। वर्तमान समय की परस्पर जुड़ी दुनिया में अनेक लोग अपने घरों से काम करते हैं। ये स्थान नवीनतम तकनीकों से लैस होते हैं तथा वे नवीनतम 'जिग्मों' का लाभ उठाते हैं। पिछले दशक में संगठनात्मक व्यवहार की पूरी अवधारणा में व्यापक बदलाव आए हैं। तकनीक का संगठनों के कामकाज पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है तथा ढांचों की जटिलता और गतिशीलता में परिवर्तन आया है। यदि हम भारतीय रेलवे के कामकाज पर गौर करें तो स्पष्ट होगा कि पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया में आपरेटिंग और विनिर्माण विभाग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। आज तकनीकी विभाग गेमचेंजर बन गए हैं और निश्चित कार्यकाल की अवधारणा इतिहास बन गई है।

कामगारों को चौबीसों घंटे व सातों दिन सतर्क रहना होता है। इस प्रकार कर्मचारियों को अपने कौशल इस स्तर तक बढ़ाने होते हैं कि वे वर्चुअल दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सकें। हमें प्रत्यक्ष शिक्षण माडलों का परीक्षण करना होगा जो आनलाइन कक्षाओं, वन-आन-वन, शिक्षक और छात्र के बीच काम करते हैं। इस अवधारणा से स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षण प्रभावित हो सकता है। इसी प्रकार योग्य डाक्टर स्काइप या अन्य तरीकों से अपने साथियों को जटिल सर्जरी के समय निर्देश दे सकते हैं।

चाहे युद्ध में सर्जिकल स्ट्राइक करना हो या नवीनतम तकनीक से पैदल सिपाहियों को निर्देश देने हों, जीपीएस कोआर्डिनेट्स तथा रियल-टाइम इमेजिरी जैसी तकनीकों का महत्व बढ़ जाता है। संगठनात्मक ढांचों के ऐसे परिदृश्य में सरकार या निजी क्षेत्र को जीवित बचे रहने के लिए आमूल परिवर्तन करने होंगे। कार्यबल को अपने कौशल का उच्चीकरण करना होगा नहीं तो वह समाप्त हो जाएगा। संभवत: तकनीकी प्रगति के संजाल में भावनायें नष्ट हो जाएंगी। किसी संगठन का भविष्य, उसके लक्ष्य तथा व्यवहार उसके ढांचे तथा कार्यबल के बीच एक ट्रैफ़िक जाम की तरह है जिसका सामना भारत के गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों को करना पड़ता है।

स्टीफेन हाकिंग ने अपने एक संभवत: निराशाजनक पूर्वानुमान में अनुमान लगाया था कि इस ग्रह पर जीवन चार कारणों-नाभिकीय बमों, ग्लोबल वार्मिंग, मानव निर्मित वाइरसों या रोबोटों से समाप्त हो सकता है।

इसलिए मानव मस्तिष्क को स्वयं अपनी खोज करते हुए वर्तमान ढांचागत व्यवहार और सिद्धान्तों को अपना कर एक ऐसी रूपरेखा बनानी चाहिए जहां वह रहने के लिए एक और ग्रह को तैयार कर सके। अरस्तू ने लिखा था, 'हम वह होते हैं जो काम बार-बार करते हैं।' इस अवधारणा को बदलना संगठनों के लिए आवश्यक हो गया है।

आप की बात

डिब्बाबंद भोजन

इटली के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी के शोध के अनुसार, डिब्बाबंद भोजन का अधिक सेवन करने से शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन बढ़ सकती है, जिससे शरीर की कोशिकाएं समय से पहले बूढ़ी हो सकती हैं। यह शोध डिब्बाबंद भोजन में पाए जाने वाले बीपीए (बिसफेनॉल ए) नामक रसायन के प्रभावों पर केंद्रित था। बीपीए एक प्रकार का प्लास्टिकाइज़र है जो डिब्बाबंद भोजन के पैकेजिंग में उपयोग किया जाता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि बीपीए के संपर्क में आने से शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन बढ़ सकती है, जिससे कोशिकाओं की उम्र बढ़ सकती है। इसके अलावा, बीपीए के संपर्क में आने से हृदय रोग, मधुमेह और कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह शोध अभी भी प्रारंभिक चरण में है और इसके परिणामों को और अधिक शोध की आवश्यकता है। हालांकि, यह शोध हमें डिब्बाबंद भोजन के सेवन के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है और स्वस्थ आहार विकल्पों का चयन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आजकल की भागती दौड़ती जीवनशैली में आदमी अपने खान-पान और भोजन के प्रति बेहद लापरवाह हो गया है। जुबान के चटोरे पन और शीघ्र उपलब्धता के चलते घरोंसे बाहर पढ़ाई एवं नौकरी करने वाले अधिकांश व्यक्ति डब्बा बंद भोजन पर निर्भर होते जा रहे हैं।

– **सुभाष बुड़ावनवाला,** रतलाम

विपक्ष को क्या हो गया है?

देश के विपक्ष को पता नहीं क्या हो गया है कारण पता नहीं क्यों उससे एक इमानदार, समझदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई नहीं जा रही हैं कारण इन दिनों केंद्र सरकार के हर कार्य का विरोध करना उसका शगल एक बन गया है फिर विशेष करके प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते रहना जैसे विपक्ष ने एक धंधा बना लिया है। जब से यह मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में सत्ता में आई है लगभग हर दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उद्योगपति अडानी के साथ जोड़कर उन्हें बदनाम करना विपक्ष का एक धंधा बन गया है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री को बदनाम करने की यह साजिश आजसे नहीं बल्कि मोदी सरकार के पहले कार्य काल से हि लगातार चल रही है अत: तब बार-बार हमारे मन में यही विचार आता है कि देश के विपक्ष को आखिर हो क्या गया है फिर जबकि संसद में पिछले दो कार्यकालों को देखे तो विपक्ष मात्र नाममात्र का रह गया था। परंतु इस बार विपक्षी सांसदों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है मगर इतनी भी नहीं की सरकार का सामना ताकत के साथ कर सके। मगर फिर भी विपक्ष जब रचनात्मक काम ना करके केवल सरकार का विरोध- विरोध ही करता रहे तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं रहती है आज संसद के दोनों सदनों में लगातार सरकार का विरोध करते हुए संसद की कार्यवाही नहीं चलने देना ही विपक्ष का आज सबसे बड़ा काम हो गया है।

– **मनमोहन राजावत,** शाजापुर

संसद का सत्र

संसद का शीतकालीन सत्र एक महत्वपूर्ण अवसर है जब सरकार और विपक्षी दल अपने विचारों और नीतियों पर चर्चा कर सकते हैं। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, संसद के सत्रों में हंगामा और व्यवधान एक आम बात हो गई है, जिससे संसद का समय बर्बाद होता है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए, सरकार को कई कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले, सरकार को संसद के नियमों और प्रक्रियाओं को मजबूत बनाना चाहिए, ताकि हंगामा और व्यवधान को रोका जा सके। इसके अलावा, सरकार को विपक्षी दलों के साथ बातचीत करनी चाहिए और उनकी चिंताओं को सुनना चाहिए, ताकि संसद में एक स्वस्थ और रचनात्मक वातावरण बनाया जा सके। एक और महत्वपूर्ण कदम यह है कि सरकार को संसद के सदस्यों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के अवसर प्रदान करने चाहिए, ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम हों। इसके अलावा, सरकार को संसद की कार्यवाही को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए, ताकि जनता को पता चले कि उनके प्रतिनिधि क्या कर रहे ? सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संसद का समय बर्बाद न हो और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो। इसके लिए, सरकार को संसद के नियमों और प्रक्रियाओं को मजबूत बनाना होगा।

– **विभुक्ति बुपक्या,** खाचरोद

ईवीएम पर विपक्ष की खीझ

विपक्ष हमेशा हार के लिए ईवीएम को दोष देता है जबकि जनता के बीच उनकी हार का कारण उनकी नकारात्मक छबि है। ईवीएम पर खीझ निकालने की बीमारी, भारतीय चुनाव प्रक्रिया में एक दुर्भाग्यपूर्ण परिघटना बन गई है। जब भी चुनाव परिणाम उम्मीदों के खिलाफ आते हैं, कुछ लोग ईवीएम को दोष देने लगते हैं, बिना इसके वास्तविक कार्यप्रणाली को समझे। यह मानसिकता चुनावी नतीजों को मान्यता न देने का कारण बनती है। सच्चाई यह है कि ईवीएम विश्वसनीय और सुरक्षित हैं, और बार-बार इसके खिलाफ आरोप लगाना लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास बढ़ाता है। चुनाव आयोग ने कई बार ईवीएम की पारदर्शिता पर सफाई दी है, लेकिन फिर भी कई लोग इसे राजनीति का हिस्सा मानते हैं। इस खीझ को सुलझाने के लिए राजनीतिक और नागरिकों को तथ्य आधारित विचारधारा अपनानी होगी। बिना साक्ष्यों के आरोप लगाना लोकतंत्र की मजबूती के लिए हानिकारक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम के विरोध वाली याचिकाओं को स्वीकार न कर समय बचा कर उलटे याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाना चाहिए।

– **भगवानदास छारिया,** इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

जनपद स्तरीय कैरियर मेले में बच्चों को जिलाधिकारी ने दी जानकारी

संवाददाता। संतकबीरनगर

समग्र शिक्षा माध्यमिक, संत कबीर नगर के अन्तर्गत विकास भवन परिसर में स्थित डी0पी0आर0सी0 हॉल में जनपद स्तरीय कैरियर मेले का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, विशिष्ट अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता एवं मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी ने प्रतिभाग करते हुए उपस्थित छात्र-छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी एवं उनके उत्साह एवं मनोबल ऊंचा बनाए रखने के संबंध में उन्हें प्रेरित किया।

सर्वप्रथम मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि द्वारा जनपद स्तरीय मेले का फीता काटकर शुभारम्भ किया गया तत्पश्चात माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक हरिश्चंद्र नाथ द्वारा मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को बुके, अंग वस्त्र तथा स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। धर्मेन्द्र कुमार मिश्र, जिला समन्वयक, समग्र शिक्षा द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अतिथियों का स्वागत, वंदन एवं अभिनन्दन किया गया। डीएम ने अपने संबोधन में उपस्थित छात्र-छात्राओं को अपने बेसिक छात्र जीवन से यूपीएससी परीक्षा में चयनित होने तक घटित घटनाओं के बारे में बताया तथा छात्र-छात्राओं को अपने कैरियर को कैसे चुने इसके बारे मे भी सुझाव दिया गया। छात्र-छात्राओं से उनको कैरियर से सम्बन्धित जिज्ञासाओं के बारे मे अवसर दिया गया तथा उनके जिज्ञासाओं का उत्तर देते हुए उनको मागदर्शन किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को कैरियर से सम्बन्धित मोटीवेशनल स्पीच देते हुए अपने जीवन से सम्बन्धित घटनाओं के बारे मे बताते हुए यूपीएससी परीक्षा के तैयारियों से सम्बन्धित अनुभव को बताया गया। तत्पश्चात आमंत्रित जनपद स्तरीय अधिकारी गण, प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों/उच्च शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधिगणों द्वारा करियर मेले से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

विधायक ने लेखपालों का धरना कराया समाप्त, दिया आश्वासन

संतकबीरनगर। बखिरा क्षेत्र के बढ़या बाबू में पैमाइश करने गई राजस्व टीम के साथ अभ्रद व्यवहार किए जाने से नाराज लेखपालों ने तहसील परिसर में धरना शुरू कर दिया था। दसवें दिन बुधवार को मेंहदावल विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी धरना स्थल पर पहुंचे और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद लेखपालों ने धरना स्थगित कर दिया है और काम पर लौट आए हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष विवेक रंजन के नेतृत्व में लेखपाल तहसील परिसर में धरनारत रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्व टीम पर हुए हमले के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई, लेकिन दोषियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। ऐसे में धरना पर बैठना मजबूरी बन गई। इस बीच बुधवार को मेंहदावल विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी धरना स्थल पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। उनके आश्वासन पर लेखपालों ने धरना स्थगित कर दिया। इस दौरान राजेंद्र प्रसाद, अमित सिंह, सुनील कुमार श्रीवास्तव, सुनील कुमार, कहकशा परवीन आदि मौजूद रहे। मेंहदावल प्रतिनिधि के अनुसार उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की तहसील इकाई से जुड़े लेखपाल भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग लेकर धरना दे रहे थे।

शांति व सौहार्द का संदेश देती है कबीर स्थली: दुर्गा शंकर मिश्र

संवाददाता। संतकबीरनगर

सद्गुरु कबीर की निर्वाण स्थली मगहर के कबीर चौरा परिसर स्थित कबीर की समाधि व मजार का बुधवार को दर्शन करने के लिये उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रमुख सचिव दुर्गा शंकर मिश्र अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। जहां कबीर की समाधि व मजार पर आस्था की चादर चढ़ाने के साथ ही आशीर्वाद लिया। इससे पूर्व कबीर स्थली पहुंचने पर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, एसपी सत्यजीत गुप्ता, महंत विचार दास व नगर पंचायत मगहर अध्यक्ष प्रतिनिधि नूरुज्जमा अंसारी ने उनका भव्य स्वागत किया।

पूर्व प्रमुख सचिव ने कबीर चौर परिसर स्थित कबीर अकादमी सहित अन्य विकास कार्यों को देखा। पूर्व प्रमुख सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने पत्रकारों से वार्ता करते हुये कहा कि कबीर स्थली पहुँचने के बाद कबीर की समाधि व मजार का दर्शनकर अभिभूत हूं। यह उस सन्त की धरती है जब इस क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था जनता त्राहि त्राहि कर रही थी। ऐसे में कबीर साहेब को काशी से मगहर लाने के बाद इस धरती पर उनके कदम पड़ते ही खूब वर्षा हुई और पूरा इलाका हरा भरा होगया। इनकी एक एक वाणी हमें जिंदगी देती नजर आती हैं।

उनके कहे गये एक एक दोहे पूरी दुनिया के लिये एक सीख है। दो लाइनों में उन्होंने बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है। आगे कहा कि कबीर ने अपने दोहे पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय कहकर प्रेम को परिभाषित किया है। कबीर ने यह भी कहा कि अति का भला न बोलना अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना अति की भली न धूप, कहकर हमें ज्ञान से सृजित करने का कार्य किया है। आगे बताया कि जब सूबे की मुख्यमंत्री मायावती थीं तब वे उनके प्रमुख सचिव रहे तब पहली बार सदुरु कबीर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। फिर दोबारा यहां आकर स्पर प्रसन्नता मिली। यहां की साफसफाई को देखकर खुशी का इजहार किया।

बैसवारा महाविद्यालय में महिला स्वास्थ्य पर संगोष्ठी आयोजित

लालगंज, रायबरेली। बैसवारा डिग्री कॉलेज में महिला स्वास्थ्य पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें विशेषज्ञो ने महिलाओं की समस्याओं व उनके निराकरण पर प्रकाश डाला। कॉलेज की छात्राओं को उड़ान टीम की स्टेट कॉर्डिनेटर शिवानी वर्मा, कॉर्डिनेटर प्रियंका वर्मा, श्वेता वर्मा द्वारा स्वास्थ्य समस्याओं, पीरियड संबधी समस्या, भ्रांतियां, और जागरूकता पर चर्चा की गयी। महाविद्यालय के मीडिया प्रभारी, डॉ. रमेश चंद्र यादव ने बताया कि कार्यक्रम का संयोजन प्रोफेसर पुष्पा बरनवाल द्वारा किया गया। प्रोफेसर बरनवाल ने छात्राओं को बताया कि मासिक धर्म से संबंधित सभी वर्जनाओं और कलंकों के बीच दक्षिण भारत के कई राज्यों में कुछ स्वस्थ परंपरायें प्रचलित हैं जिनके अंतर्गत बालिकाओं के प्रथम बार रजस्वला होने पर उसे एक धार्मिक अनुष्ठान एवं उत्सव की तरह मनाया जाता है। भारत के ओडिशा में रज परब, कर्नाटक में ऋतु शुद्धि या ऋतु कला, तमिलनाडु में मंजल निरातु वीजा, असम में तुलोनिया बिया इस तरह की स्वस्थ परम्परायें हैं। डॉ.दीक्षा मिश्रा ने बताया कि छात्राओं को कई बार एनीमिया की समस्या होती है, क्योंकि उनका खानपान गुणवत्तापूर्ण नही होता। कार्यालय प्रमुख अंजू सिंह ने बताया कि छात्राओं को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। डॉ. नीलम शुक्ला ने बताया कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को आराम मिले, इसलिए धार्मिक ग्रंथों में स्त्रियों को इस अवधि में बहुत सारे कार्यों से दूर रखा गया। कार्यक्रम में डॉ. कांची बाजपेयी, पूजा श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। कॉर्डिनेटर प्रियंका वर्मा ने छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान हाईजीन का ध्यान कैसे रखें, इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रियंका वर्मा ने छात्राओं से अनियमित पीरियड, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस), पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजिज आदि से जुड़ी समस्याओं और चुनौतियों पर बात की।

निरीक्षण एवं जनसुनवाई के लिए रायबरेली पहुंचीं राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष

संवाददाता। रायबरेली

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने जनपद भ्रमण के दौरान जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया तथा महिला वार्डों के निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी वार्ड, लेबर रूम तथा अन्य इकाईयों में महिलाओं से सम्पर्क कर चिकित्सा संबंधित सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। व महिलाओं को 40 बेबी किट व मिष्ठान वितरित कर संबंधित अधिकारियों को कन्या सुमंगला योजना का लाभ दिलाए जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

तत्पश्चात जिला कारागार में पाकशाला, महिला बंदीगृह का निरीक्षण किया गया तथा महिला बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना एवं माता से साथ आवासित बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट, टॉफी एवं महिला बंदियों को कम्बल का वितरण किया। इसके पश्चात वन स्टाप सेंटर का निरीक्षण किया गया जहां पर सभी कार्मिक रोस्टर के अनुसार उपस्थित मिले तथा वहां पर केन्द्र प्रबन्धक से कार्यालय के समस्त अभिलेखों महिलाओं से संबंधित प्राप्त प्रकरणों का अवलोकन तथा महिलाओं से संबंधित प्रकरणों की जानकारी ली तथा केन्द्र प्रबंधक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। वन स्टाप सेंटर भवन में ही संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया।

कार्यालय में उपस्थित कार्मिकों से बच्चों से संबंधित प्रकरणों के बारे में जानकारी ली गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। उपाध्यक्ष द्वारा ग्राम पंचायत हरिदासपुर के आंगनवाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया गया जहां पर 0 से 06 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी तथा आंगनवाड़ी केन्द्र पर धात्री महिलाओं की गोदभराई की तथा सभी बच्चों को फ्रूट वितरण किया गया तथा केन्द्र पर उपस्थिति आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

सरकारी सुरक्षित जमीन पर निर्माण का आरोप

महराजगंज, रायबरेली। सरकार की लाख सख्ती के बाद भी सरकारी जमीनों पर कब्जा और निर्माण किए जाने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहें हैं। ताजा मामला महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव पूरे रानी मजरे चंदापुर का है, जहां सरकारी सुरक्षित जमीन पर हल्का लेखपाल की शह पर निर्माण किए जाने का आरोप लगाते हुए गांव की ही एक महिला ने एसडीएम सचिन यादव को एक शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कोतवाली क्षेत्र के गांव पूरे रानी मजरे चंदापुर गांव की रहने वाली सूरज कली ने एसडीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि गांव स्थित सरकारी सुरक्षित जमीन पर गांव के ही अनिल कुमार सुनील कुमार पुत्रगण मोती लाल व उदयराज पुत्र लल्लू द्वारा लेखपाल की मिली भगत से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसे रोकवाया जाए और निर्माण कार्य करने वालों पर कार्रवाई की जाए। एसडीएम सचिन यादव ने बताया कि निर्माण कार्य पुराने कच्चे घर को जमींदोज कर किया जा रहा है।

एनटीपीसी परियोजना की बाउंड्रीवाल के किनारे ग्रामीणों को अतिक्रमण हटाने की दी गई नोटिस

ऊंचाहार। एनटीपीसी परियोजना की बाउंड्रीवाल के किनारे मकान व दुकान बनाकर जीवन यापन करने वाले ग्रामीणों को प्रबंधन द्वारा अतिक्रमण हटाने की नोटिस दी गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर नुकसान की भरपाई किये जाने की गुहार लगाई है। एनटीपीसी परियोजना की बाउंड्रीवाल के किनारे खुर्रमपुर ग्राम पंचायत के दर्जनों लोग पिछले तीस चालीस सालों से मकान व दुकान बनाकर रोजमर्रा की जीवन व्यतीत कर रहे हैं।एनटीपीसी परियोजना द्वारा वहां स्थायी रूप से रह रहे लोगों को कब्जा हटाने के सम्बंध में दो बार नोटिस दी गई है।बुधवार को प्रधान प्रतिनिधि विनय शुक्ल बाबा की अगुवाई में ग्रामीण रज्जन लाल, प्रमोद कुमार, आशा देवी आदि ने एसडीएम को ज्ञापन देकर मकान व दुकान हटाने के दौरान होने का नुकसान की भरपाई के सम्बंध में गुहार लगाई है।प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा नोटिस देकर ग्रामीणों को कब्जा हटाने को कहा गया है जबकि पिछले चालीस वर्षों से लोग वहां पर काबिज है।उनकी मांग है कि एनटीपीसी प्रबंधन ग्रामीणों के नुकसान की भरपाई करे और ग्राम पंचायत के विकास का कार्य करे अन्यथा ऐसा न करने पर एनटीपीसी प्रबंधन के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया जायेगा। एसडीएम सिदार्थ चौधरी ने बताया कि प्रबंधन से बातचीत कर मसले का हल निकाला जायेगा।

बुंदेलखंड का हक अब और ज्यादा समय तक छीना नहीं जा सकता: पांडेय

- 18 दिसंबर से गांव-गांव पांव-पांव यात्रा का द्वितीय चरण

संवाददाता। उरई, जालौन

बुंदेलखंड राष्ट्र समिति की ओर से हरकौती गांव में एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के विकास, किसानों की समस्याओं और अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण पांडेय की मुख्य आतिथ्य में हुई इस बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीण और कार्यकर्ता शामिल हुए।

राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजी. प्रवीण पांडेय ने अपने वक्तव्य में कहा कि बुंदेलखंड का हक अब और नहीं छीना जा सकता। यूपी और एमपी की उपेक्षा ने इस क्षेत्र को पिछड़ा बना दिया है। यूपी-एमपी तोड़ दो, बुंदेलखंड को जोड़ दो का यह आंदोलन अब और मजबूत होगा। नीरज ने जैविक खेती के महत्व पर बात करते हुए कहा कि यह न केवल पर्यावरण को सुरक्षित रखती है, बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनाती है। उन्होंने जैविक कृषि को क्षेत्र में बढ़ावा देने की योजना साझा की। जिलाध्यक्ष प्रशांत अवस्थी रूरा ने कहा समिति गांव-गांव जाकर बुंदेलखंड राज्य निर्माण की अलख जगा रही है। हर बुंदेली को इस आंदोलन का हिस्सा बनना होगा।

ब्लॉक अध्यक्ष शशांक नायक ने बैठक के अंत में सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। हरकौती के ग्रामीणों ने बैठक में बढ़-चढ़कर भाग लिया और समिति के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने राज्य निर्माण के आंदोलन को पूरा समर्थन देने का वायदा किया। समिति द्वारा क्षेत्र में जनजागरण अभियान को तेज किया जाएगा। गांव-गांव में जागरूकता बैठकें, रैलियां और आंदोलन किए जाएंगे। जालौन ब्लॉक अध्यक्ष शशांक नायक, कमलेश दूरबार, नीरज दूरबार, पवन गोस्वामी, रमेश कटारे, सूर्यकांत नायक, प्रशांत पांडेय, प्रांयाशु खेमरिया, आदर्श नायक, सत्यम यज्ञिक, राजकुमार नायक, नीलेश नायक, राधेश्याम मुखिया, अंकित गुर्जर, सौरभ दुबे, कन्हैया मिश्रा, रामू मास्टर आदि लोग शामिल रहे।

गल्ला मंडी में एसडीएम ने गंदगी देख दी हिदायत

कालपी, जालौन। बुधवार को प्रशासक, उप जिलाधिकारी सुशील कुमार सिंह ने कृषि उत्पादन मंडी समिति कालपी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान परिसर में गंदे जानवर का विचरण तथा गंदगी देखकर नाराजगी जताई जताते हुए मातहतों को जरूरी हिदायत दी। उल्लेखनीय हो कि गल्ला मंडी कालपी में सफाई की समुचित व्यवस्था के मामले को उप जिलाधिकारी ने संज्ञान में लिया तथा बुधवार की दोपहर को अचानक पर मंडी में पहुंच गये। उन्होंने घूम घूम कर परिसर का बारीक से निरीक्षण किया। कई स्थानों में गंदे जानवरों के विचरण करने तथा कूड़े के ढेर लगे होने पर नाराजगी जताते हुए कर्मचारियों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए निर्देश दिये।

एमएसबी कालेज में कम छात्र मिलने पर एसडीएम ने जतायी नाराजगी

कालपी, जालौन। बुधवार को स्थानीय नगर की प्रमुख शिक्षण संस्था एमएसबी इंटर कॉलेज में शिक्षा की हकीकत को परखने के लिये उप जिलाधिकारी सुशील ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की संख्या कम होने पर नाराजगी जताते हुए शिक्षकों को आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय के निर्देशन के अनुरूप उप जिलाधिकारी ने एमएसबी इंटर कालेज कालपी का निरीक्षण किया। एसडीएम सुशील कुमार सिंह ने विद्यार्थियों से कई विषयों से संबंधित प्रश्न पूछें, बच्चों के सही जबाब देने पर अधिकारियों ने संतोष व्यक्त किया। इसी क्रम में उन्होंने विद्यालय में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 9 सौ है। जबकि में करीब 50 प्रतिशत विद्यार्थी उपस्थित पाये गए। एसडीएम सुशील कुमार सिंह ने शिक्षकों से विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षकों को निर्देश दिए कि शिक्षा की गुणवत्ता ठीक रखी जाए तथा छात्र-छात्राओं की उपस्थिति बढाई जाए। इस दौरान प्रधानाचार्य सुशील कुमार शाक्य संतोष द्विवेदी अमित मिश्रा अतुल दीक्षित आदि शिक्षक प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान तत्काल पूर्ण करायें: जिलाधिकारी

उरई, जालौन। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय व पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी अवशेष सड़क मार्गों को भी तत्काल गड्ढामुक्त करने की कार्यवाही पूर्ण की जाए, इसमे किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा एनएचएआई सड़क पर गड्ढामुक्त के कार्य मे रुचि न लेने पर कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि प्राईवेट एवं सरकारी वाहन चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु सतत कैम्प आयोजित किये जायें। उन्होंने निर्देशित किया कि जनजागरूकता कार्यक्रम कराये, जनजागरूकता कराना है और जीवन की रक्षा कराना है।

उन्होंने निर्देशित किया कि अभियान चलाकर ट्रैक्टरों अन्य वाहनों पर रेडियम लगाए। उन्होंने निर्देशित किया कि किसी भी सड़क पर वाहन खड़े नही होना चाहिए, इसके लिए अभियान चलाकर वाहनों को हटाया जाए, इस कार्य में रुचि न लेने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही होगी। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि कालपी बस स्टैण्ड के सामने खड़े अवैध वाहनों एवं अतिक्रमण पर यातायात विभाग द्वारा जो विधिक कार्यवाही की जा रही है उसे निरंतर जारी रखा जाए।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि ट्रैक्टर ट्राली कृषि कार्य के लिए पंजीकृत एवं निर्मित है व डम्पर ट्राला एवं मालयान माल ढोने के लिए है इसमें सवारी बैठाना या ढोना एक दण्डनीय अपराध है इसके लिए सघन अभियान चलाकर दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु तेजी लाना सुनिश्चित करे। जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग को फैक्ट्री एरिया उरई में स्थित चौकी के सामने खड़े सीज वाहनों को तत्काल हटाये जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद जालौन के अंतर्गत एक राष्ट्रीय मार्ग एवं एक राज्यमार्ग जिसमें पिछले तीन वर्षों में सर्वाधिक दुर्घटनायें हुई है उन मार्गो के स्थलों का सर्वे कर उन मार्गो को जीरो फैटेलिटी मार्ग के तहत मॉडल मार्ग बनाने के संबंध में रोड सेफ्टी ऑडिट कराकर रोड सेफ्टी के अंतर्गत समस्त प्रावधान किए जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि ऐसे वाहन जो ओवरलोड, बिना नम्बर, बैक लाइट न होने पर कार्यवाही की जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि शहर के बीच बन रही सीसी रोड पर पानी का छिड़काव करें, इस कार्य में लापरवाही बरतने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी नेहा ब्याडवाल, एआरटीओ सुरेश कुमार, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग सुनील कुमार आदि सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

विधायक ने सुरक्षा में प्रांतीय रक्षक दल के जवानों की भूमिका को सराहा

संवाददाता। उरई, जालौन

बुधवार को सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा, जिलाधकारी राजेश कुमार पाण्डेय व पुलिस अधीक्षक डॉ दुर्गेश कुमार ने युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के तत्वाधान में इंदिरा स्टेडियम में आयोजित प्रांतीय रक्षक दल का 76वां स्थापना दिवस मनाया।

सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने अपने सम्बोधन में पीआरडी जवानों की सुरक्षा में भूमिका की भूरि-भूरि प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने इंदिरा स्टेडियम में लाइट व्यवस्था व कबड्डी मैड देने की घोषणा की। राजेश कुमार पांडेय जिलाधिकारी ने अपने सम्बोधन में सबसे पहले जवानों को स्थापना दिवस की बधाई दी, आपने अपने कर्मकौशक से बहुत अच्छी परेड का एक अच्छा तालमेल प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि विधायक सदर विकास के पथ पर तत्पर रहते हैं, अभी इंदिरा स्टेडियम में लाइट व कबड्डी मेट की व्यवस्था की घोषणा की। जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक से कहा कि धनराशि अवमुक्त करके अतिशीघ्र काम शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि सदर विधायक हमेशा ही विकास के क्षेत्र में गौशाला हो या कोई भी काम हो उसमे आप बढ़-चढ़ कर जनहित में कार्य करते हैं, जनपद के विकास में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उन्होने कहा है कि यहां पर जवानों द्वारा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, इसके लिए पूरी टीम और टीआई को बधाई दी और उम्मीद है कि आप आने वाले समय मे जो आपकी कुशलता, कौशल है वह और अच्छा निखर के आएगा।

उन्होंने कहा कि आज की तारीख में कानून व्यवस्था, ड्यूटी संभालने में पीआरडी के जवान बहुत महत्वपूर्ण कड़ी का निर्वहन कर रहे है, बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर जिम्मेदारी से निर्वहन कर रहे है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पीआरडी जवानों द्वारा अनुशासन का परिचय देते हुए बेहतर परेड की गई। उन्होंने कहा कि पीआरडी जवान की एक टुकड़ी तैयार करके आगामी 26 जनवरी 2025 के लिए परेड में सम्मिलित हो। इससे जुड़े अधिकारी अर्चना प्रजापति व टीआई को जिम्मेदारी दी गई है।

उद्योग बंधुओं की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर करें समाधान: जिलाधिकारी

उरई, जालौन। जनपद की उद्यमियों की समस्याओं को त्वरित निस्तारण करने के उद्देश्य जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं ओडीओपी वित्त पोषण सहायता योजना में प्रगति बढ़ाने के लिये उपायुक्त उद्योग एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक को कड़े निर्देश दिये गये हैं। इन योजनाओं में लक्ष्य की पूर्ति न हो पाने की दशा में कार्यवाही की जायेगी। कालपी औद्योगिक आस्थान में पृथक फीडर हेतु बिजली विभाग को निर्देशित किया कि कार्यवाही जल्द से जल्द पूर्ण करें साथ ही उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिये गये कि उनके हस्ताक्षर से प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण खण्ड को पत्र प्रेषित किया जाये। एक मामला औद्योगिक आस्थान कालपी में सोलर लाईटों के संबंध में कार्य पूर्ण होने पर मामला निपेक्षित किये जाने के निर्देश दिये गये।

पावर लूम सब्सिडी हेतु बुनकरों की विद्युत बिल में सब्सिडी आने लगी है और जो बकाया सब्सिडी है, उसको भी एडजेस्ट करने के निर्देश दिये गये। श्रीकृष्णा कोल्ड स्टोरेज से जो सड़क हाईवे को जोड़ती है वहां 15 फीट का पेच है, का कार्य न होने की स्थिति में संबंधित अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध वेतन रोके जाने के निर्देश दिये गये है।

प्रभाकर बिजनेसेस एल एल पी ने एक प्लाट बैंक आक्शन में खरीदा जिसमें 4.50 करोड़ की बिजली विभाग की देनदारी है। इस संबंध में निर्देश दिये गये कि विद्युत कनेक्शन जोड़ कर कार्यवाही करें। एमओयू के संदर्भ में उपायुक्त उद्योग को बैठक कराने के लिये और जो उद्यमी एमओयू हस्ताक्षरित किये है, यदि वह कार्य शुरू नहीं करते है, तो उनके एमओयू निरस्त करने के भी आदेश दिये गये हैं।

सेफ्टी जाली से विहीन ट्रांसफार्मर कभी भी बन सकते हैं दुर्घटना के सबब

जालौन, उरई। नगर के प्राचीन चौपाला कुंआ के चबूतरे पर ट्रांसफार्मर रखे हैं। ट्रांसफार्मर के पास बिजली के तार लंबे समय से खुले पड़े हैं। चबूतरे पर खुले तार व सेफ्टी जाली विहीन ट्रांसफार्मर कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। मोहल्ले के लोगों ने समस्या का समाधान कराने की मांग बिजली विभाग के अधिकारियों से की है। सरकार बिजली से होनी वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास कर रही है। इसके लिए खुले तार हटाने के साथ ट्रांसफार्मर के आसपास सेफ्टी जाली लगाई जा रही है।

इसके अलावा बिजली तारों के नीचे जाल भी लगाया जा रहा है। व्यवस्था को लेकर बिजली विभाग के नोडल अधिकारी मनीष द्विवेदी कुछ माह पूर्व तीन दिवसीय जनपद भ्रमण पर आए थे। भ्रमण के दौरान उन्होंने मीटर रीडर के साथ नगर में भ्रमण कर बिजली चोरी को लेकर चेकिंग की थी। साथ ही व्यस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए थे।

संगठनात्मक मंडल चुनाव प्रक्रिया को लेकर भाजपा ने किया मंथन

उरई ,जालौन। भारतीय जनता पार्टी ने सर्किट हाउस उरई में आगामी संगठनात्मक मण्डल चुनाव प्रक्रिया को लेकर बैठक संपन्न की बैठक में मुख्य अतिथि जिला चुनाव अधिकारी सुभाष त्रिपाठी विधायक प्रयागपुर रहे उन्होंने सभी मंडल चुनाव अधिकारी एवं सह चुनाव अधिकारी को बैठक में मंडल अध्यक्ष बनाने के लिए नियम बताए जिलाध्यक्ष उर्विजा दीक्षित ने बताया कि मंडल से जो नाम पैनल में आयेगे उन्हीं नामों को क्षेत्रीय कार्यालय भेज दिए जाएंगे क्षेत्र अपनी रिपोर्ट प्रदेश को देगा। इसके बाद प्रदेश स्तर से मंडल अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे।

इस दौरान मुख्य रूप से उपस्थित जिला चुनाव सह अधिकारी जगदीश तिवारी, विवेक कुशवाहा, पूर्व जिलाध्यक्ष रामेंद्र सेंगर, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा उदयन पालीवाल, नरेंद्र जादौन पूर्व विधायक संतराम सेंगर, अरविंद चौहान, संजीव उपाध्याय मनोज राजपूत रामलखन औदीच्य, दिलीप दुबे, बाबा बालकदास पाल एवं मंडल चुनाव अधिकारी उपस्थित रहे।

एक दिवसीय मेला सह प्रदर्शनी का शुभारंभ

- विधायक और डीएम ने किया उद्घाटन
- किसानों को दी योजनाओं की जानकारी
- कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु किसान को दिया 24 लाख रुपये का अनुदान

संवाददाता। फतेहपुर

जनपद स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी/श्री अन्न मिलेट्स एक दिवसीय मिलेट्स मेला सह प्रदर्शनी व नेशनल मिशन ऑन एडिबिल ऑयल योजना अंतर्गत तिलहन मेले का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेक्षागृह में किया गया। मेला सह प्रदर्शनी में कृषि, ग्राम्य विकास अभिकरण, अग्रणी जिला प्रबन्धक, उद्यान, पशुपालन, रेशम, इफ्को, सामाजिक वानिकी एवं वन्य जीव प्रभाग, भृगु आर्गेनिक जैविक उत्पाद, आत्म शक्ति फार्मर प्रो0कं0लि0, प्रज्ञा ग्रामोत्थान सेवा समिति, बायर कं0लि0, वी0एन0आर0 सीड्स, प्रभात फर्टिलाइजर्स, पायनियर सीड्स, नलकूप एवं सिंचाई खण्ड आदि विभाग एवं अन्य सहायोगी प्रतिष्ठानों के लगाए गए स्टालों का विधायक अयाह शाह विकास गुप्ता, जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीना ने फीता काटकर उद्घाटन किया और लगाई गई प्रदर्शनी का घूम-घूम कर निरीक्षण किया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अयाह शाह विकास गुप्ता ने कृषकों के हित मिलेट्स फसलों के प्रयोग को बढ़ाने, आच्छादन विस्तार के साथ कहा कि किसान अन्नदाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश एवं प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में लगातार कार्य किया जा रहा है। कृषकों को कृषि क्षेत्र में विविधता लाते हुए अधिक आय प्राप्त किये जाने की अपील की गयी।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह ने कृषकों को केन्द्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी। उप कृषि निदेशक राममिलन सिंह परिहार ने विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फार इन सी-टू मैनेजमेन्ट ऑफ क्राप रेजीड्यू योजना अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेन्टर हेतु अर्जुन सिंह निवासी बेरागढीवा ब्लाक भिटौरा को 30 लाख परियोजना लागत का 80 प्रतिशत (24 लाख) अनुदान दिये जाने एवं कृषि यंत्र क्रय करने के उपरान्त चाभी देकर मुख्य अतिथि विधायक अयाह शाह विकास गुप्ता व जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया।

इस मौके पर जिला कृषि अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी, ईईसी, भूमि संरक्षण अधिकारी, रा0जला0, जिला उद्यान अधिकारी, अग्रणी जिला प्रबन्धक, ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक, डा0 जितेन्द्र सिंह, कृषि वैज्ञानिक, डा0 साधना वैश्य, कृषि वैज्ञानिक, डा0 जगदीश किशोर, कृषि वैज्ञानिक, डा0 एसके पाण्डेय, कृषि वैज्ञानिक सहित विभागीय अधिकारी एवं कृषक उपस्थित हुए।

झाऊपुर की निष्क्रांत संपत्ति पर भूमाफ़ियाओं की नजर

फतेहपुर। शहर के झाऊपुर वार्ड की निष्क्रांत (शत्रु) संपत्ति गाटा संख्या 203/74 पर पुनः भू-माफ़ियाओं की नज़र टिक गई है। पूर्व में तत्कालीन लेखपाल द्वारा ऐसी कुत्सित मानसिकता वाले 27 लोगों के खिलाफ़ एफआई.आर. दर्ज़ कराई थी, बावजूद इसके फ़िर से भू- माफिया सक्रिय हो गए हैं, विभागीय साठगांठ से सम्पत्ति का न सिर्फ़ वंशज घोषित कर दिया गया, बल्कि इस कीमती भूमि का नामांतरण भी करा लिया गया है और विगत दिवस बलात कब्ज़ा कर लिया गया है। झाऊपुर (मोहल्ले) वार्ड के सुरेश, अनिल, राजेंद्र पाल, सुनील पाल, सुरेन्द्र पाल, नरेन्द्र पाल आदि ने जिला अधिकारी को एक शिकायतीपत्र सौंपकर आरोप लगाया कि मो. आमिल व मो. शाह हुसैन ने उपरोक्त ज़मीन पर कब्जे का ताना- बाना बुना जा रहा है, और कब्ज़ा करके बेचने की तैयारी है। शिकायतकर्ताओ ने डीएम से उपरोक्त प्रकरण पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

आचार्य डॉ रामकृपाल मिश्रा को अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंटकर किया सम्मानित

संवाददाता। फतेहपुर

साहित्य भारती भदबा के तत्वावधान में गीता जयंती के अवसर एवं डॉक्टर हरि प्रसाद शुक्ल अकिंचन की 7वीं पुण्यतिथि पर स्वामी अकर्माचार्य की तपोभूमि में श्रीमद्भगवत गीता के श्लोकों में हवन पूजन के बाद सामुदायिक मिलन केंद्र में सारस्वत अभिनंदन एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आचार्य डॉ. रामकृपाल मिश्रा उज्ज्वल को साहित्य भारती के अध्यक्ष ओमप्रकाश शुक्ल प्रणव, डॉ. अवनीश शुक्ल, सनत कुमार शुक्ल ने अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता सत्यानंद शुक्ल ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में कवि राम सजीवन मिश्र निर्मल मौजूद रहे। बाद में उपस्थित कवियों ने काव्य पाठ कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में आए कवियों के सम्मान के बाद काव्य पाठ का सिलसिला शुरू करते हुए कवि डॉ. गया प्रसाद सनेही ने पढ़ा हमने चाहा फंसाना मगर फंस गए, चांदनी रात में तस्करों की तरह। मधुसूदन दीक्षित ने पढ़ा हो गया पथभ्रष्ट चला जा रहा हूं, मिल रहा जो भी निगलता जा रहा हूं।

अभिनंदित आचार्य डॉ. राम कृपाल मिश्र उज्ज्वल ने पढ़ा गीता के उपदेश में, है वेदों का सार श्रवण, मनन जिसने किया उसका बेड़ा पार। प्रोफेसर डॉ. अश्वनी कुमार शुक्ल ने पढ़ा सदियों रहे वाट जोहते हुआ पूर्ण वह काम, सूर्य विराजे उत्तरायण में राम बिराजे अपने धाम। शिवशरण सिंह चौहान अंशुमाली ने पढ़ा ओ अकिंचन हृदय आओ रूप रखना चाहता हूं, सर्जनाएं आपकी मैं पुनः पढ़ना चाहता हूं। ओमप्रकाश शुक्ल प्रणव ने पढ़ा सफलता सिर चढ़ने लगे तो पातन तय है, बहुत इतरा के चले तो दफ्न तय है। यश मिले तो संभाल कर रखना, आतंक फैलाया तो कफ्न तय है। डॉ. गया प्रसाद सनेही व्याकरणाचार्य सत्यानंद शुक्ल, राम औतार गुप्त, के.पी. सिंह कछवाह, दीपचंद्र गुप्त दीप, रामकुमार गुप्त नलिन ने भी अपनी कविताएं पढ़ मौजूद श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।

सहायक अभियंता की लापरवाही उजागर काम किसी का भुगतान दूसरे ठेकेदार को

- मामला गंभीर है कराएंगे जांचः अधीक्षण अभियंता

संवाददाता। हमीरपुर

लघु डाला नहर (लिफ्ट कैनाल) की भ्रष्टाचार की परत दर परत खुलती जा रही है, ठेकेदार से काम कराने के बाद सहायक अभियंता ने दूसरे ठेकेदार को भुगतान कर दिया है। डीएम के आदेश से हुई जांच में सहायक अभियंता को दोषी बताया गया है यही नही जांच अधिकारी कहना है कि सहायक अभियंता से कई मर्तवा जांच के लिये अभिलेख मांगे मगर अभिलेख नही दिये गये है।

जानकारी के मुताबिक उजनेडी गांव निवासी ठेकेदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सहुरापुर पंप कैनाल में सहायक अभियंता सृष्टि चौहान ने उससे स्टोर रुम व अन्य काम करा लिया था,जिसमे उसका करीब बारह लाख रुपये खर्च हुआ था,इसके बाद सहायक अभियंता ने बिड दूसरे ठेकेदार के नाम एग्रीमेंट कर दिया जब इस मामले में उसने एतराज किया तो पूरा स्टाफ सहायक अभियंता का साथ देने लगा यही नही जांच में जेई ने लिखित रिपोर्ट दी थी कि काम ठेकेदार धीरेंद्र ने कराया है मगर इस बात को न तो एई मानने को तैयार है न ही एक्शियन। प्रताप की शिकायत से बौखलाये एक्शियन व एई ने दूसरे ठेकेदार के नाम एग्रीमेंट कर कई लोगो के नाम भुगतान कर दिया जो गैरकानूनी था।

ठेकेदार ने इस मामले की शिकायत शासन के उच्चाधिकारियों के अलावा डीएम घनश्याम मीना से की। डीएम ने मामले की जांच मौदहा बांध के एक्शियन करनपाल सिंह व डीसी मनरेगा राघवेंद्र सिंह को सौपी,दोनो अधिकारियों ने मौके पर जांच की व मजदूरों से पूछताछ की तो सभी ने ठेकेदार धीरेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष में बयान दिये,जिससे साबित हो गया है कि काम ठेकेदार धीरेंद्र ने ही कराया है,जांच अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में सहायक अभियंता सृष्टि चौहान से कई मर्तवा अभिलेख मागे है मगर उन्होने कोई ध्यान नही दिया है, जांच कमेटी ने डीएम को भेजी गयी रिपोर्ट में कहा है कि ठेकेदार धीरेंद्र द्वारा काम कराने के बाद भुगतान दूसरे ठेकेदार को दिया गया है यह सत्य है।

जांच रिपोर्ट के बाद क्या होता है यह समय ही बतायेगा। इधर दफ्तर में एक्शियन व कोई भी अभियंता के न बैठने से किसानों को तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पडता है। जब कि जिलाधिकारी इस मामले में एक्शियन शरद चौहान को हिदायत भी दे चुके है मगर उनकी चेतावनी का कोई असर नही हुआ है।

बिजली विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ पूर्व सैनिकों ने की कार्रवाई की मांग

राठ, हमीरपुर। कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली विभाग में व्याप्त दलाली घूसखोरी भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के विरोध में पूर्व सैनिकों सहित हिंदू युवा संगठन ने लामबंद होते हुए मोर्चा खोल दिया। दर्जनों पूर्व सैनिकों और हिंदू युवा संगठन के पदाधिकारियों ने बुधवार को विधायक मनीषा अनुरागी व एसडीएम अभिमन्यु कुमार को ज्ञापन सौंपा है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सदानंद खरे महेश यादव सुनील तोमर उदेश फौजी दृगपाल सिंह जानकी प्रसाद हबीब खानएहरी सिंह संतोष सिंह इंद्रजीत सिंह उदय प्रताप सिंह बृजेश कुमार द्विवेदी जोगिंदर सिंहए अखिलेश कुमार अर्जुन सिंह सहित हिंदू युवा संगठन के अध्यक्ष बृजेश खरे ने बताया कि राठ बिजली विभाग कार्यालय में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार घूसखोरी दलाली और अनियमितताएं फैली हुई हैं। बिजली विभाग की चेकिंग के दौरान प्राइवेट व्यक्ति और दलाल टीम के साथ जाकर चेकिंग करते हैं।

ढोल-नगाड़े के साथ कराई बिजली के बिल में ब्याज छूट की मुनादी

गुरसहायगंज, कन्नौज। विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए उनके बकाया बिलों पर ब्याज में छूट की योजना का प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया है। इसी क्रम में विद्युत उपखंड अधिकारी बृजेश कुमार सरोज एवं अवर अभियंता विकास कुमार ने विभागीय कर्मियों के साथ नगर में भ्रमण कर ढोल-नगाड़ों के माध्यम से मुनादी कराई। बुधवार को नगर में प्रचार-प्रसार दौरान विद्युत उपखंड अधिकारी बृजेश कुमार सरोज एवं अवर अभियंता विकास कुमार नें टीम ने नगर के प्रमुख स्थानों और मोहल्लों में घूमकर उपभोक्ताओं को सूचित किया कि उनके बकाया विद्युत बिलों पर शासन से दी गई ब्याज की छूट का लाभ उठाने का यह सुनहरा अवसर है। ढोल-नगाड़ों की आवाज से लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया और लाउडस्पीकर के माध्यम से योजना की जानकारी दी गई। बताया कि इस योजना के तहत उपभोक्ता अपने बकाया बिजली बिलों पर ब्याज की छूट का लाभ उठा सकते हैं। विभाग द्वारा तय समय सीमा के भीतर भुगतान करने पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी। उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाया हैं। वे शीघ्र अपने नजदीकी विद्युत कार्यालय से संपर्क करें।

प्रशिक्षण में दिए मतदान के टिप्स, डीएम ने निरीक्षण कर समझाईं बारीकियां

लखीमपुर खीरी। नगर पालिका परिषद पलियाकला के अध्यक्ष पद के उपनिर्वाचन को लेकर धर्मसभा कॉलेज में मतदान कार्मिकों की प्रशिक्षण कार्यशाला का डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने एडीएम संजय कुमार सिंह के साथ जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्मिकों को मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी। साथ ही मतदान संबंधी अपने अनुभव सांझा किया।

बुधवार को डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने धर्म सभा इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। डीएम ने मतदान कर्मियों को मतदान से जुड़े टिप्स देते हुए वोटिंग की बारीकियां समझाई। मतदान कर्मियों से सवाल पूछने के साथ ही उन्हें पूरी प्रक्रिया भी समझाई। डीएम ने अलग-अलग मतदान कार्मिकों से मतदान दिवस के दिन उनके कार्यों व दायित्वों के संबंध में जानकारी लेते हुए जाना कि प्रशिक्षण के दौरान मतदान कार्मिक कितने संजीदा हैं। मतदान संबंधी कई प्रश्न पूछते हुए प्रशिक्षण की गुणवत्ता को भी परखा।

डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने प्रशिक्षण रूम में कर्मियों को जानकारी देते हुए प्रशिक्षक के भूमिका में नजर आई। डीएम में कार्मिकों को कहा कि उनकी सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। चुनाव के दिन कार्मिकों के ठहरने, भोजन, पेयजल और सुरक्षा आदि की भी अच्छी व्यवस्था रहेगी, ताकि उन्हें कोई परेशानी नहीं हो।

प्रशिक्षण कार्यशाला में मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण जिला प्रशिक्षण अधिकारी डॉ मनीष चंद्रा, प्रवक्ता धर्म सभा इंटर कॉलेज बृजेश वर्मा, अनुदेशक आईटीआई भारत भूषण मिश्रा द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया। प्रशिक्षकों ने कार्मिकों को मतदान प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी।

जिला जज के नेतृत्व में बेहतर स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए साइकिल रैली का आयोजन

संवाददाता। कन्नौज

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में एक विशेष साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण, और राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व के प्रति जागरूक करना था। रैली का नेतृत्व जिला जज चन्द्रोदय कुमार ने किया, जिसमें जिले के सभी न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और डिफेंस काउंसिल ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

बुधवार को लाला श्याम लाल इंटर कॉलेज के छात्रों की सक्रिय भागीदारी ने इस आयोजन में और अधिक ऊर्जा भर दी। यह साइकिल रैली जिला न्यायालय से शुरू होकर बोर्डिंग ग्राउंड तक निकाली गई। जिला जज चन्द्रोदय कुमार ने इस अवसर पर जनता को संदेश देते हुए कहा, साइकिल चलाना न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी सहायक है। हमें अधिक से अधिक साइकिल का उपयोग करना चाहिए।

उन्होंने यह भी अपील की कि 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में लोग अपने विवादों का निस्तारण सुलह-समझौते के माध्यम से करें। इससे न केवल न्याय व्यवस्था में तेजी आएगी, बल्कि लोगों को समय और धन की बचत भी होगी। इस आयोजन ने न केवल कन्नौज में स्वास्थ्य और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा दिया, बल्कि न्यायपालिका के जागरूकता अभियानों को भी मजबूती प्रदान की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की यह पहल सामाजिक सुधार और सामूहिक जिम्मेदारी की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित हुई। साइकिल रैली में अपर जिला जज प्रथम लोकेश वरुण, अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लवली जायसवाल, अपर जिला जज नंद कुमार, अपर जिला जज इंद्रजीत सिंह, अपर जिला जज अलका यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिलिंद कुमार, चीफ डिफेंस काउंसिल श्वेतांक अरुण तिवारी, आदि रहे।

ब्लाक प्रमुख ने जन्म दिन पर सफाई कर्मियों को किया सम्मानित

फतेहपुर। भिटौरा ब्लाक प्रमुख अमित तिवारी ने अपने जन्मदिन पर हवन-पूजन व भण्डारे का आयोजन किया। जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। तत्पश्चात उन्होने पच्चीस सफाई कर्मियों को शील्ड व शाल देकर सम्मानित किया। बुधवार को भिटौरा ब्लाक प्रमुख अमित तिवारी का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर सुंदरकाण्ड का पाठ किया इसके पश्चात हवन-पूजन किया। हवन में आहूतियां डालने के बाद भण्डारे का आयोजन किया। जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता निभाई। ब्लाक प्रमुख ने ठण्ड के मौसम के मद्देनजर बुजुर्ग महिलाओं को कंबल व शाल वितरण किया। शाल व कंबल पाकर सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे।

चेयरमैन ने रेलवे स्टेशन पर रैन बसेरा का किया उद्घाटन

फतेहपुर। नगर पालिका परिषद ने सर्दी के मौसम के दृष्टिगत तैयारियां तेज कर दी हैं। पालिका की ओर से अस्थाई रैन बसेरा का निर्माण सार्वजनिक स्थानों में कराया जा रहा है। बुधवार को रेलवे स्टेशन परिसर में बने अस्थाई रैन बसेरा का चेयरमैन राजकुमार मौर्य ने फीता काटकर शुभारंभ किया। अस्थाई रैन बसेरा का शुभारंभ करते हुए नगर पालिका परिषद राजकुमार मौर्य व अधिशाषी अधिकारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि इस रैन बसेरा के बन जाने से अब रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों के साथ-साथ निर्धनों को रात्रि में भीषण ठण्ड में इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अस्थाई रैन बसेरा में वह रात गुजार सकते हैं। रैन बसेरा में सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई है। जिसमें रजाई, गद्दा व पीने का पानी भी उपलब्ध रहेगा। रैन बसेरा कर्मचारी को हिदायत दिया कि किसी भी तरह की दिक्कत यहां रूकने वाले लोगों को नही होनी चाहिए। इस मौके पर सभासद शहजाद अनवर, अतीश पासवान, रितिक पाल, विनय तिवारी, संजय श्रीवास्तव, शादाब अहमद, भिक्खू मामा, विवेक यादव, हिमांशु सिंह, धीरेन्द्र मौर्य के अलावा मो. हबीब मौजूद रहे।

सीडीओ का विकास भवन के दफ्तरों में छापा नदारद मिले 15 कार्मिक, रोका गया वेतन

लखीमपुर खीरी। बुधवार की सुबह करीब 10.05 बजे सीडीओ अभिषेक कुमार ने विकास भवन के ऑफिसों में छापा मार दिया। कर्मचारी बगैर सूचना के गायब मिले। सीडीओ ने निरीक्षण में गायब मिले सभी 15 कार्मिकों का वेतन रोका दिया।

बुधवार को सुबह 10.05 बजे सीडीओ ने डीडीओ ऑफिस से जांच की शुरूआत की। सीडीओ ने हाजिरी रजिस्टर मंगा लिए। मौके पर अधिकारी-कर्मचारियों को बुलाकर मिलान किया। निरीक्षण के दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी दफ्तर के कार्मिक भूपराम राना, सैय्यद साद, शिवनन्दन भारती, अजय कुमार, सुशील कुमार, श्रीमती एकता सिंह गायब मिली। वही जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी कार्यालय के कार्मिक डा. मंजू दीक्षित, श्रीमती नीति शर्मा, प्रवीन कुमार, सीवीओ दफ्तर के कनिष्क सहायक रजत प्रताप सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) से वसूली सहायक अजय शुक्ला अधिशाषी अभियन्ता, ग्रा.अ.वि. दफ्तर के पत्रवाहक राम सुफल, डीडीओ दफ्तर से प्रधान सहायक उस्मान खाँ, पत्रवाहक कृष्ण प्रताप सिंह और परियोजना अधिकारी एकीकृत जनजाति विकास दफ्तर की पत्रवाहक श्रीमती गौरी अनुपस्थित पाई गई। बगैर सूचना के गायब सभी 15 कार्मिकों को वेतन रोक दिया।

सीडीओ अभिषेक कुमार ने उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया कि सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप काम किया जाए। लेटलतीफ आने वाले अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तय समय पर अधिकारी-कर्मचारी कार्यालयों में उपस्थित होना शुरू करें। निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने विभिन्न पटलों पर जाकर कर्मचारियों से उनके कार्यों को भी देखा। औचक निरीक्षण से विकास भवन में हड़कंप मच गया।

देश को शिक्षा के जगत में विश्वगुरु बनाने के अभियान का प्रयास है सर्वोदय विद्यालय

संवाददाता। कानपुर देहात

गुरुवार, 12 दिसंबर का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है, जब पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के पैतृक गांव परौंख, कानपुर देहात में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति के सर्वोदय विद्यालय बालिका का शिलान्यास होगा। यह पहल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और ग्रामीण भारत में आधुनिक शिक्षा के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। सर्वोदय विद्यालय शिक्षा की प्राचीन गुरुकुल परंपरा और आधुनिक तकनीकी शिक्षा के केंद्र हैं। सर्वोदय विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत मा. प्रधानमंत्री जी के देश को शिक्षा के जगत में विश्वगुरु बनाने के अभियान का एक सफल प्रयास हैं।

परौंख में बनने जा रहे सर्वोदय विद्यालय बालिका में न केवल बेटियों को शिक्षा दी जाएगी बल्कि इस विद्यालय को सेंटर आफ एक्सीलेंस फार डिफेंस, पुलिस, फोर्स के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे बेटियों को डिफेंस और विभिन्न फोर्सेज में आगे बढ़ने का बेहतरीन अवसर मिलेगा। विद्यालय में एनसीसी का केंद्र भी बनेगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग के द्वारा बेटियों को विभिन्न फोर्सेज में जाने के लिये प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की शिक्षा के प्रति गहरी निष्ठा और ग्रामीण विकास की सोच का यह परिणाम है कि उनके पैतृक गांव में बालिका विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार शिक्षा और युवाओं के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। पूरे प्रदेश में 75 जनपदों में सर्वोदय विद्यालयों को मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह विद्यालय परंपरागत और आधुनिक शिक्षा के मिश्रण का अनूठा उदाहरण हैं, जो बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। परौंख में बालिका विद्यालय का निर्माण बालिका शिक्षा को नई दिशा देने का प्रतीक है। यह न केवल कानपुर देहात बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इस शिलान्यास से शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होगी, जो बच्चों को उनके सपने साकार करने का मंच प्रदान करेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सर्वोदय विद्यालयों का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, तकनीकी और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। इन विद्यालयों में छात्रों को कक्षा 6 से 12 तक मुफ्त शिक्षा के साथ छात्रावास, पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म, मेस, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, और आधुनिक तकनीकी सुविधाएं जैसे टैब-लैब और ई-लैब उपलब्ध कराई जाती हैं।

पूर्व राष्ट्रपति के आगमन दृष्टिगत व्यवस्थाओं का लिया गया जायजा

कानपुर देहात। निदेशक समाज कल्याण, कुमार प्रशांत, प्रबंध निदेशक, प्रकाश बिंद व संयुक्त निदेशक निदेशालय समाज कल्याण जे राम जी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन व अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार के साथ कानपुर देहात में कल 12 दिसम्बर 2024 को मा0 पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के पैतृक गांव परौंख, कानपुर देहात में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति के सर्वोदय विद्यालय बालिका का शिलान्यास कार्यक्रम के प्रबंध हेतु आज संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने मा0 पूर्व राष्ट्रपति महोदय द्वारा किये जाने वाले शिलान्यास कार्यक्रम में व्यवस्थाओं का जायजा लिया व सुरक्षात्मक प्रबंध हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उपजिलाधिकारी डेरापुर, क्षेत्राधिकारी डेरापुर सहित अन्य संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

अंत्येष्टि स्थल के निर्माण पर आपत्ति के बावजूद बाउंड्री वाल व गेट पर बनी सहमति

रूरा, कानपुर देहात। कस्बे में जन सामान्य की सुविधा के लिये बनाये जा रहे अन्त्येष्टि स्थल पर एक पक्ष द्वारा की जा रही आपत्ति के बावजूद नायब तहसीलदार अरविन्द मिश्रा, एसएसआई लक्ष्मण सिंह व लेखपाल वरूण कटियार की उपस्थित में दीवार के निर्माण के साथ गेट लगवाये जाने पर आम सहमति बन गयी। इस नगर पँचायत के लिपिक सैनूर अहमद, नगरपँचायकर्मी लकी सक्सेना सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवेदनशील चैयरमैन रामजी गुप्ता द्वारा कस्बे के जनका देवी महाविद्यालय से सटी जमीन पर आम लोगों के लिये अन्त्येष्टि स्थल निर्माण का प्रस्ताव किया था, निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व नगर पँचायत ने अखबार में गजट भी करवाया था, शुरू में किसी ने भी अन्त्येष्टि स्थल निर्माण का विरोध नहीं किया लेकिन जब निर्माण शुरू होने का समय आया तो अपने आपको कबीरपँथी कहने वाले एक पक्ष ने अन्त्येष्टि स्थल निर्माण का विरोध कर शिकायत की।

शिकायत पर वुधवार की शाम को नायब तहसीलदार, लेखपाल वरूण कटियार मौके पर जॉच करने पहुँचे और दूसरे पक्ष को ध्यान से सुना, करीब एक घण्टे से भी अधिक समय तक वार्तालाप व सँवाद के बाद तथाकथित कबीर पँथी पक्ष ने वहॉ बाउण्ड्रीवाल व गेट लगाये जाने पर सहमति प्रदान की।

शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू

फतेहपुर। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए जाने के साथ-साथ जाम की समस्या से आमजन को निजात दिलाए जाने के उद्देश्य से बुधवार को शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरूआत हो गई। पहले दिन चौक पीलू तले चौराहा, चौक चौराहा से लाठी मोहाल तक अतिक्रमण हटाया गया। बुल्डोजर देख व्यापारियों में हड़कंप मचा रहा। अतिक्रमण हटाओ अभियान की अगुवई नायब तहसीलदार सदर अंबरेश कुमार सिंह ने की। अभियान के दौरान नगर पालिका परिषद के ईओ रवीन्द्र कुमार, अतिक्रमण प्रभारी दिलशाद अली, शहर कोतवाल तारकेश्वर राय के अलावा अन्य अधिकारियों ने भी सहभागिता निभाई।

पायनियर
लखनऊ, बृहस्पतिवार, 12 दिसम्बर 2024

उच्चतम न्यायालय ने बौद्धिक दिव्यांगता वाली महिला को मिलने वाली मुआवजा राशि बढ़ाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को यह कहते हुए सड़क दुर्घटना के कारण 75 प्रतिशत बौद्धिक दिव्यांगता वाली महिला को मिलने वाली मुआवजा राशि बढ़ा दी कि विवाह या साथी का होना व्यक्ति के स्वाभाविक जीवन का अभिन्न अंग है। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि जून, 2009 में दुर्घटना के समय लड़की सात वर्ष की थी और चिकित्सा प्रमाण पत्र के अनुसार वह बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त है। उच्चतम न्यायालय ने कहा, अपीलकर्ता (महिला) ने न केवल अपना बचपन खो दिया है, बल्कि अपना वयस्क जीवन भी खो दिया है। विवाह या जीवनसाथी का होना मनुष्य के स्वाभाविक जीवन का अभिन्न अंग है। पीठ ने कहा कि हालांकि महिला के बच्चों को जन्म देने में सक्षम है, लेकिन उनके लिए बच्चों का पालन-पोषण करना और वैवाहिक जीवन का आनंद लेना लगभग असंभव है।

पीठ ने इसलिए मुआवजे की राशि बढ़ाकर 50.87 लाख रुपए कर दी। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के नवंबर, 2017 के उस आदेश को चुनौती देने वाली उनकी अपील पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें उन्हें 11.51 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। पीठ ने कहा कि महिला जीवनभर किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहेगी और उम्र बढ़ने के बावजूद वह मानसिक रूप से अभी भी कक्षा दो में पढ़ने वाली बच्ची की तरह ही रहेगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जून, 2009 में अपीलकर्ता अपने परिवार के सदस्यों के साथ पैदल घर जा रही थी और वे सड़क पार कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी।

न्यायालय ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधान के तहत मुआवजे के लिए एक दावा याचिका मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की गई थी, जिसने 5.90 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके बाद अपीलकर्ता ने दुर्घटना में लगी चोटों के लिए दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने मुआवजा राशि बढ़ाकर 11.51 लाख रुपए कर दी, लेकिन मामूली वृद्धि के मद्देनजर अपीलकर्ता ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

महिला के वकील ने पीठ को बताया कि चिकित्सा के साक्ष्य के अनुसार, महिला को 75 प्रतिशत बौद्धिक दिव्यांगता है। वकील ने दलील दी कि मध्यम बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चे आमतौर पर कक्षा दो के बच्चे के स्तर तक कौशल सीखने में सक्षम होते हैं और केवल करीबी देखरेख के तहत काम कर सकते हैं। पीठ ने उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण को भी गलत करार दिया कि महिला को केवल अंशकालिक परिचारिका की आवश्यकता होगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा, इसके विपरीत, हमारा मानना है कि अपीलकर्ता को जीवनभर पूर्णकालिक आधार पर एक परिचारिका पर निर्भर रहना पड़ेगा।

उपासना स्थल अधि. 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई आज

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय उपासना स्थल अधिनियम, 1991 के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। संबंधित कानून कहता है कि 15 अगस्त, 1947 को विद्यमान उपासना स्थलों का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा, जैसा वह उस दिन था। यह किसी धार्मिक स्थल पर फिर से दावा करने या उसके स्वरूप में बदलाव के लिए वाद दायर करने पर रोक लगाता है। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ इस मामले की संभवतः सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें से एक याचिका अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है। उपाध्याय ने उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधि., 1991 की धाराओं दो, तीन और चार को रद्द किए जाने का अनुरोध किया है। याचिका में दिए गए तर्कों में से एक तर्क यह है कि ए प्रावधान किसी व्यक्ति या धार्मिक समूह के पूजा स्थल पर पुनः दावा करने के न्यायिक समाधान के अधिकार को छीन लेते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और महाराष्ट्र के विधायक जितेंद्र सतीश अव्हाड ने भी उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई लंबित याचिकाओं के खिलाफ याचिका दायर करके कहा है कि यह कानून देश की सार्वजनिक व्यवस्था, बंधुत्व, एकता और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करता है।

केवल महिलाओं ही नहीं, पुरुषों की भी गरिमा होती है: केरल उच्च न्यायालय

भाषा। कोच्चि

केरल उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अभिनेता एवं निर्देशक बालचंद्र मेनन को 2007 में एक फिल्म के शूट के दौरान एक महिला कलाकार के कथित शीलभंग के मामले में बुधवार को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि सिर्फ महिलाओं की नहीं, बल्कि पुरुषों का भी गौरव और उनकी भी गरिमा होती है। न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन ने अभिनेता की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट जारी होने के बाद इस वर्ष सितंबर में अभिनेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

मेनन ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि शिकायत 2007 में कथित घटना की तारीख से 17 साल बाद की गई और इसका उद्देश्य उनकी छवि खराब करना है। अदालत ने कहा कि उनकी दलीलों में दम है क्योंकि यह स्वीकार्य तथ्य है कि कथित घटना 2007 में हुई थी। उसने कहा, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि पीड़िता ने कथित घटना के 17 साल बाद शिकायत दर्ज कराई। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता (मेनन) एक प्रसिद्ध सिने कलाकार हैं। उन्होंने लगभग 40 फिल्मों का निर्देशन किया और उन्हें दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। उन्हें राष्ट्र द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया।

न्यायमूर्ति कुन्हीकृष्णन ने कहा, मौजूदा मामला एक महिला के बयान के आधार पर और वह भी 17 साल बाद दर्ज किया गया है। यह सच है कि जांच जारी है लेकिन सभी को यह याद रखना चाहिए कि गौरव और गरिमा केवल महिलाओं की ही नहीं, बल्कि पुरुषों की भी होती है। अदालत ने कहा कि यह न्याय के हित में याचिकाकर्ता को जमानत देने का उपयुक्त मामला है। न्यायालय ने मेनन को पूछताछ के लिए बुधवार से दो सप्ताह के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा, पूछताछ के बाद यदि जांच अधिकारी याचिकाकर्ता (मेनन) को गिरफ्तार करने का प्रस्ताव रखता है, तो उन्हें गिरफ्तार करने वाले संबंधित अधिकारी की संतुष्टि के लिए अभिनेता को 50,000 रुपए के मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों पर जमानत पर रिहा किया जाएगा। उसने निर्देश दिया कि मेनन आवश्यक पड़ने पर पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे, जांच में सहयोग करेंगे और मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देंगे...।

वकीलो की हड़ताल रहने पर भी कामकाज जरूर करें न्यायिक अधिकारी

प्रयागराज। उप्र की विभिन्न अदालतों में निरंतर हड़ताल से लोगों को हो रही मुश्किलों पर चिंता व्यक्त करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि भले ही वकील हड़ताल पर रहें, लेकिन न्यायिक अधिकारी अपना कामकाज जरूर करें। न्यायमूर्ति अजित कुमार ने आशुतोष कुमार पाठक नाम के व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यदि वादी अपने मामले में सुनवाई चाहते हैं तो जिला न्यायाधीश के परामर्श से जिला प्रशासन को उन्हें पुलिस सुरक्षा अवश्य उपलब्ध करानी चाहिए। वकीलों के हड़ताल पर रहने की वजह से किसी को भी असहाय नहीं रखा जा सकता। कोई भी वकील न्यायिक अधिकारी को काम करने से नहीं रोक सकता और ना ही वह किसी वादी को अदालत में जाने से रोक सकता। वकील ने अदालत को बताया कि जिला गाजियाबाद में वकील हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से उसके मुवक्किल को परेशानी हो रही है।

अदालत ने कहा, वैधानिक विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद वादकारियों को अदालतों से न्याय नहीं मिल रहा और वे केवल इसलिए उच्च न्यायालय का रुख करने को बाध्य हैं क्योंकि संबंधित जिले में वकीलों की हड़ताल है। अधिवक्ता एक नेक पेशे से जुड़े होते हैं और उनसे इस बात की अपेक्षा की जाती है कि वे कभी किसी वादी को न्याय के लिए जनपद न्यायालय में जाने से नहीं रोकेंगे। इस रिट याचिका को निस्तारित करते हुए अदालत ने छह दिसंबर के अपने आदेश में कहा कि यदि याचिकाकर्ता दो सप्ताह में दायर करना चाहे तो अधिकरण के न्यायिक अधिकारी/ पीठासीन अधिकारी आदेश पारित करेंगे, भले ही वकीलों की हड़ताल जारी रहे।

बरेली में टीवी अभिनेत्री सपना सिंह के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, दो दोस्त गिरफ्तार

बरेली (उप्र)। टीवी धारावाहिकों की अभिनेत्री सपना सिंह के 14 साल के बेटे को उसके दो दोस्तों ने कथित तौर पर नशीला पदार्थ खिलाया, जिससे उसकी मौत हो गई। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। बेटे की मौत के विरोध में अभिनेत्री ने बरेली में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, आठवीं कक्षा का छात्र सागर (14) अपने मामा ओम प्रकाश के साथ आनंद विहार कॉलोनी, बरेली में रहता था, रविवार सुबह उसका शव इज्जतनगर थाना क्षेत्र के अदलखिया गांव के पास मिला जबकि एक दिन पहले ओम प्रकाश ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस के अनुसार परिजनों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार सागर गंगवार शनिवार को स्कूल गया था लेकिन वह वापस नहीं लौटा, जिसके बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

पुलिस ने बताया कि रविवार को उसका शव बरामद हुआ लेकिन पहचान नहीं हो पाई, हालांकि सोमवार को सागर के परिजनों ने शव की पहचान की। मंगलवार को 90 मिनट से अधिक समय तक चला अभिनेत्री का विरोध प्रदर्शन स्थानीय पुलिस द्वारा कार्वाई का आश्वासन दिए जाने के बाद समाप्त हुआ। पुलिस के मुताबिक, गंगवार के दो दोस्तों अनुज और सनी (दोनों वयस्क) को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।

क्षेत्राधिकारी पुलिस (फरीदपुर) आशुतोष शिवम ने बताया, पोस्टमार्टम से मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी। हालांकि जहर या नशीले पदार्थ के अत्यधिक सेवन से मौत होने के संकेत मिले हैं। जांच के लिए शव का विसरा सुरक्षित कर लिया गया है। भुता थाना के प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया, अनुज और सनी ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि उन्होंने सागर के साथ मादक पदार्थ और शराब का सेवन किया था। ज्यादा सेवन के कारण सागर बेहोश हो गया। घबराकर वे सागर को घसीटकर एक खेत में ले गए और उसे वहीं छोड़ दिया।

बारादरी पुलिस ने सात दिसंबर को ओम प्रकाश द्वारा गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर की थी, शव की पहचान के बाद घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में अनुज और सनी बेहोश सागर को घसीटते हुए दिख रहे थे। दोनों को हिरासत में लिया गया, घटना के बाद सागर के गांव में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और लोगों ने सड़क जाम कर दी तथा दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की। टीवी कार्यक्रम क्राइम पेट्रोल और माटी की बन्नो में अपनी भूमिकाओं के लिए मशहूर सपना सिंह मंगलवार को मुंबई से लौटीं तो उन्होंने अपने बेटे को मृत पाया। बेटे के शव को देखकर वह रो पड़ीं और न्याय की मांग की। विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने हत्या का मामला जोड़ा और भुता थाने में नई प्राथमिकी दर्ज की।

संभल में पुलिस ने की धर्म गुरुओं के साथ बैठक, धार्मिक स्थलों के बाहर लगे लाउडस्पीकर हटाने पर सहमति

संभल (उप्र)। संभल जिले में पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें धार्मिक स्थलों के बाहर लगे लाउडस्पीकर सर्वसम्मति से हटाने का निर्णय लिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र ने पत्रकारों से कहा, हमने सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार रखने का निर्णय लिया गया। सभी ने सहमति जताई कि बाहर लगे लाउडस्पीकर हटाकर धार्मिक स्थलों के परिसर के अंदर रखे जाएंगे। बैठक में मौजूद रहे मुफ्ती आलम रजा खान नूरी ने कहा, बैठक में सभी धर्मों के लोग मौजूद थे और लाउडस्पीकर को लेकर हुई चर्चा पर सभी ने सहमति जताई। चामुंडा मंदिर के महंत मुरली सिंह ने बताया कि लाउडस्पीकर की आवाज बहुत तेज न हो, इस पर सभी ने सहमति जताई।

इंजीनियर आत्महत्या मामले में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली: पुलिस

जौनपुर (उत्तर प्रदेश)। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की पुलिस ने बुधवार को कहा कि उसे बेंगलुरु पुलिस की ओर से इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के संबंध में अब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में काम करने वाले 34 वर्षीय तकनीकी विशेषज्ञ सुभाष का 24 पन्नों का कथित सुसाइड नोट और 80 मिनट से अधिक लंबा वीडियो मिला है, जिसमें उन्होंने वैवाहिक मुद्दों, अपने खिलाफ दर्ज कई मामलों और पत्नी, रिश्तेदारों व उत्तर प्रदेश के एक न्यायाधीश द्वारा कथित उत्पीड़न के कारण वर्षों से चली आ रही मानसिक प्रताड़ना के बारे में विस्तार से बताया है। सुभाष की मौत के बाद उनकी पत्नी और ससुराल के सदस्यों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है।

सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया जौनपुर की रहने वाली हैं, जहां उन्होंने पहली बार अतुल, उनके भाई और माता-पिता के खिलाफ साल 2022 में दहेज उत्पीड़न के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जौनपुर के पुलिस अधीक्षक अजयपाल शर्मा ने पीटीआई-भाषा को बताया, इस मामले में बेंगलुरू पुलिस ने अब तक हमसे संपर्क नहीं किया है। जौनपुर पुलिस के मुताबिक 24 अप्रैल 2022 को निकिता ने सुभाष के खिलाफ स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था और तत्कालीन महिला उपनिरीक्षक प्रियंका ने मामले की जांच कर 30 अगस्त 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दायर कर दिया था।

इस बीच, बुधवार को जब मीडियाकर्मी निकिता के खोया मंडी स्थित घर पहुंचे तो निकिता के भाई अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया और मां निशा सिंघानिया ने उनसे बात करने से साफ मना कर दिया। मकान की दूसरी मंजिल से मां और बेटे ने मीडिया से कैमरे बंद करने को कहा। निकिता के भाई अनुराग ने यह भी कहा कि हमें जो भी कहना है सबके सामने कहेंगे और अपने वकील के सामने बात करेंगे। जो भी आरोप लगाए जाएंगे, समय आने पर उनका जवाब दिया जाएगा। अनुराग ने कहा, जो भी जानना है अदालत से जाकर पता करो।

निकिता के रिश्तेदार सुरेंद्र सिंघानिया ने बताया कि निकिता और अतुल की शादी करीब पांच साल पहले हुई थी और शादी के बाद दोनों बेंगलुरु में काम करते थे और वहीं रहते थे, उनका एक बेटा भी हुआ। सुरेंद्र ने कहा कि पिछले दो साल से निकिता अतुल से तलाक लेना चाहती थी और इसी के मद्देनजर उसने अपने पैतृक जिले जौनपुर की अदालत में तीन-चार मामले भी दायर किए थे। उन्होंने कहा कि फिलहाल निकिता अपने बेटे के साथ दिल्ली में रहती है और वहीं काम करती है। सुरेंद्र ने कहा कि दोनों के बीच विवाद के चलते निकिता गुजारा भत्ता चाहती थी और अतुल इसे देने के पक्ष में नहीं था जबकि जौनपुर की अदालत में लगातार मामले की तारीखें दी जा रही थीं।

अतुल के खिलाफ निकिता द्वारा दायर मामलों में पैरवी कर रहे अधिवक्ता दिनेश मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया कि निकिता ने अतुल के खिलाफ कई मामले दर्ज कराए थे, जिनमें से एक महत्वपूर्ण मामला पारिवारिक न्यायालय में लंबित है। उन्होंने कहा कि इस मामले में निकिता ने अपने और बच्चे के भरण-पोषण के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी, लेकिन न्यायालय ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने का निर्देश देने से इनकार कर दिया, हालांकि बच्चे के भरण-पोषण के लिए हर महीने 40,000 रुपए देने का आदेश दिया था।

मिश्रा ने कहा कि जुलाई महीने के बाद से उनकी अतुल से कोई मुलाकात या बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा, ऐसा कभी नहीं लगा कि अतुल अवसादग्रस्त या मानसिक तनाव का शिकार है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक निकिता ने 24 अप्रैल 2022 को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए जौनपुर में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें पति, सास, ससुर और देवर को आरोपी बनाया था। यह प्राथमिकी जौनपुर के कोतवाली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए (पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता), 323 (हमला), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना), 506 (आपराधिक धमकी) और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत दर्ज की गई थी।

गाजियाबाद में सड़क पार कर रहे व्यक्तियों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, तीन लोगों की मौत

गाजियाबाद (उप्र)। गाजियाबाद जिले के क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में सड़क पार कर रहे कुछ लोगों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत हो गई। स्थित विजय नगर कॉलोनी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नौ पर सड़क पार कर रहे चार लोगों को किसी वाहन ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। क्रॉसिंग रिपब्लिक की थानाध्यक्ष प्रीति गर्ग ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर के दादरी के निवासी पवन कुमार (45) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तीन अन्य घायलों को अस्पताल भेजा गया, दो महिलाओं सुनीता (38) और नीलम (45) की बुधवार को मौत हो गई। श्वेता (35) का दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। हादसे के शिकार लोग बस से उतरकर विजय नगर में बागू कॉलोनी अंडरपास से सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया।

सरिस्का अभयारण्य में बने मंदिरों के श्रद्धालुओं की भावनाओं का भी ख्याल रखा जाना चाहिए

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि सरिस्का बाघ अभयारण्य के संरक्षण के दौरान वहां स्थित प्रसिद्ध पांडुपोल हनुमान मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाओं का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने मंदिर न्यास और श्रद्धालुओं की इस चिंता पर संज्ञान लिया कि निजी वाहनों पर तत्काल रोक लगाने से मंगलवार और शनिवार को मंदिर जाने वाले हजारों श्रद्धालुओं को दर्शन से वंचित होना पड़ेगा। शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने अपनी रिपोर्ट में सरिस्का बाघ अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध पांडुपोल हनुमान मंदिर तक निजी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही के कारण वन्यजीवों को होने वाले नुकसान पर चिंता जताई है।

पीठ ने सरिस्का के जिलाधिकारी, बाघ परियोजना के क्षेत्र में कार्यरत निदेशक और सीईसी के एक सदस्य की सदस्यता वाली एक समिति गठित करते हुए कहा, बाघ अभयारण्य की सुरक्षा करते समय मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने इससे पहले राजस्थान सरकार से सीईसी की रिपोर्ट पर जवाब तलब किया था। इस मामले में कानूनी मित्र के रूप में न्यायालय की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने कहा था कि सीईसी ने बाघ अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र स्थित प्राचीन मंदिर तक निजी वाहनों के जाने पर पूरी तरह रोक लगाने की सिफारिश की है और सुझाव दिया है कि श्रद्धालुओं को लाने-ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक शटल बसें एक व्यावहारिक विकल्प हो सकती हैं। उन्होंने अदालत से कहा कि सीईसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अभयारण्य के अंदर भारी वाहनों के आवागमन से बाघों के प्रजनन और अन्य वन्यजीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अरावली पर्वत शृंखला में स्थित सरिस्का बाघ अभयारण्य राजस्थान के अलवर और जयपुर जिलों में फैला हुआ है।

हास्य कलाकार सुनील पाल के कथित अपहरण मामले में दो लोग हिरासत में, पत्नी थाने पहुंचीं

भाषा। मेरठ (उत्तर प्रदेश)

हास्य कलाकार सुनील पाल के कथित अपहरण और जबरन वसूली के मामले में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। इस बीच, पाल की पत्नी सरिता बुधवार सुबह तीन वकीलों के साथ मेरठ के लाल कुर्ती थाने पहुंचीं और दावा किया कि उनके पति की वायरल ऑडियो क्लिप से छेड़छाड़ हुई है। पाल ने पिछले सप्ताह दावा किया था कि वह एक कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड गए थे तभी उनका अपहरण कर लिया गया था। उन्होंने कहा था कि अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के तौर पर 20 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन उन्हें आठ लाख रुपए लेकर छोड़ दिया गया।

पाल ने दावा किया था कि उन्हें मेरठ में एक सड़क के किनारे छोड़ा गया, जहां से वह दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचे और मुंबई के लिए रवाना हुए। मुंबई के सांताक्रूज थाने की पुलिस ने उनकी शिकायत के आधार पर अपहरण और जबरन वसूली का मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में इसे उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थानांतरित कर दिया गया।

पुलिस अधीक्षक (नगर) आयुष विक्रम सिंह ने बुधवार को पीटीआई-भाषा को बताया, हास्य कलाकार सुनील पाल के अपहरण का मामला मुंबई से मेरठ स्थानांतरित कर दिया गया है। मामला शुरू में मुंबई में दर्ज किया गया था, लेकिन अब मेरठ पुलिस भी मामले की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि दो संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस आनलाइन मिली एक कथित ऑडियो क्लिप की भी जांच कर रही है जिसमें कथित तौर पर पाल एक अज्ञात व्यक्ति से अपने अपहरण की योजना और मीडिया में इस प्रकरण की चर्चा के बारे में बात कर रहे हैं।

इस बीच, पाल की पत्नी सरिता बुधवार सुबह तीन वकीलों के साथ मेरठ के लाल कुर्ती थाने पहुंचीं और दावा किया कि उनके पति की वायरल ऑडियो क्लिप से छेड़छाड़ हुई है।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ऑडियो अधूरा है, इसकी काट-छांट की गई है। ऑडियो रिकॉर्ड करने से पहले सुनील को धमकाया गया था। आरोपियों के पकड़े जाने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिरौती के बारे में सरिता ने कहा, शुरू में 20 लाख रुपए मांगे गए थे, लेकिन हमने उन्हें आठ लाख रुपए दे दिए। बाद में सुनील ने मदद के लिए कुछ दोस्तों को फोन किया था। उन्होंने कहा कि पाल फिलहाल घर पर हैं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह खुद पुलिस अधिकारियों से मिलने मेरठ आई हैं। बॉलीवुड अभिनेता मुश्ताक खान के अपहरण मामले से जुड़े सवाल पर सरिता ने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है।

पेज 1 का शेष

नोकझोंक...

जो लोग इस पद पर थे, उन्होंने कभी राजनीति नहीं की और निष्पक्ष रहे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को धनखड़ से कोई शिकायत नहीं है, 'लेकिन उन्होंने हमें उन्हें हटाने के लिए नोटिस जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा।' द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के नेता तिरुचि शिवा ने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा संसद में देश के लोकतंत्र पर एक ज़बरदस्त हमला किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता सहित विपक्षी सदस्यों को मुद्दे उठाने की अनुमति नहीं है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता नदीमुल हक ने कहा कि वह कांग्रेस के रुख से सहमत हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद में बार-बार स्थगन के लिए सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस दोनों की आलोचना की और उन्हें व्यवधानों के लिए जिम्मेदार ठहराया। समाजवादी पार्टी (एसपी) के जावेद अली खान ने कहा कि विपक्ष को राज्यसभा में पूरी तरह से अदृश्य कर दिया गया है।राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल (डेमोक्रेटिक) के सांसद मनोज झा ने भी कहा कि संसद में विपक्ष को 'अदृश्य' कर दिया गया है। शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने कहा, ऐसा लगता है कि अध्यक्ष संसद नहीं बल्कि एक सर्कस चला रहे हैं। वह खुद बोलकर समय बर्बाद करते हैं। आम आदमी पार्टी (आप) का कोई भी नेता मौजूद नहीं था। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की राहुल गांधी के खिलाफ 'अपमानजनक टिप्पणी' के खिलाफ पार्टी की शिकायत की जांच करने और उसे रिकॉर्ड से हटाने का आग्रह किया। दुबे की टिप्पणी जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को निशाना बनाया और उन्हें अमेरिका में रहने वाले एक अरबपति से जोड़ने की कोशिश की, ने लोकसभा में हंगामा मचा दिया, जिसके कारण कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। भाजपा ने आरोप लगाया कि अमेरिका स्थित निवेशक, खोजी मीडिया प्लेटफॉर्म ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) और कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सफलता की कहानी को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ अपना आक्रामक रुख जारी रखते हुए सत्तारूढ़ पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका स्थित अरबपति सोरोस और नेहरू-गांधी परिवार के बीच संबंध बहुत गहरे हैं, जो फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स - एशिया पैसिफिक (एफडीएल-एपी) के सह-अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी की 'भूमिका' से कहीं आगे तक फैले हुए हैं।

4.9 डिग्री ...

1.2 डिग्री कम है। दिल्ली के कई हिस्सों में कोहरे की एक पतली परत छाई रही और सुबह की ठंड करीब 9 बजे तक बनी रही। आईएमडी के अनुसार, धुंध और धुंध की स्थिति के साथ-साथ उत्तर-पश्चिम से 8-10 किमी प्रति घंटे की गति से सतही हवाएँ चलने से तापमान में गिरावट आई। आईएमडी ने कहा कि दिल्ली में अब न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया है, जिससे शीत लहर की स्थिति बन गई है। आईएमडी मैदानी इलाकों के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से कम या उसके बराबर न्यूनतम तापमान को 'शीत लहर' के रूप में परिभाषित करता है, जब तापमान विचलन 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे वास्तविक न्यूनतम तापमान के आधार पर भी शीत लहर घोषित किया जा सकता है, जब पारा 4 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो जाता है। इस मौसम का आखिरी सबसे ठंडा दिन 7 दिसंबर को दर्ज किया गया था, जब न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, जो औसत से तीन डिग्री कम था। ऐतिहासिक रूप से, 27 दिसंबर, 1930 को सफदरजंग वेधशाला में 0.0 डिग्री का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि हिमालय से ठंडी हवा लाने वाली उत्तरी हवाओं के कारण अचानक तापमान में गिरावट आई है, जिससे राजधानी में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। रात के तापमान में लगातार गिरावट चिंता का विषय है और आईएमडी के मानदंडों के अनुसार शीत लहर की सलाह अभी भी प्रभावी है, जिससे सावधानी बरतने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। चूंकि राष्ट्रीय राजधानी में तापमान एकल अंकों में बना हुआ है, इसलिए बेघर लोगों ने रैन बसेरों में शरण ली है। इन आश्रयों में उन्हें बिस्तर, कंबल, भोजन और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जाती है। पारे में गिरावट के बावजूद, दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराबश्रेणी में रही, शहर में धुंध की एक पतली परत छाई रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, शाम 4 बजे तक समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 199 था।आनंद विहार (218), अशोक विहार (227), द्वारका (250) और आईजीआई एयरपोर्ट (218) में एक्यूआई खराब श्रेणी में था, जबकि आया नगर (148), बुराड़ी क्रॉसिंग (187) और चांदनी चौक (181) जैसे इलाकों में मध्यम स्तर देखा गया। छ्क्क्क के अनुसार, गाजियाबाद में 98, नोएडा में 110, गुरुग्राम में 159 और ग्रेटर नोएडा में 146 दर्ज किया गया।अपने बुलेटिन में आईएमडी ने अगले कुछ दिनों में उत्तर-पश्चिम और आसपास के मध्य भारत में अलग-अलग इलाकों में शीत लहर की स्थिति की भविष्यवाणी की।

महाराष्ट्र...

दी। कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक यशवंत काले ने कहा, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और दंगाई भीड़ को तितर-बितर किया। नांदेड़ रेंज के प्रमुख पुलिस उप महानिरीक्षक शाहजी उमाप परभणी शहर में स्थिति की समीक्षा और नियंत्रण के लिए परभणी पहुंचे। परभणी जिले के कुछ प्रभावित इलाकों में निषेधाज्ञा जारी की गई है, जबकि स्थानीय पुलिस की सहायता के लिए दंगा प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त बल भेजा गया है। प्रदर्शनकारी भारतीय संविधान की प्रतिकृति को नुकसान पहुंचाने वाले एक बदमाश की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इस बीच, भारतीय संविधान की प्रतिकृति को नुकसान पहुंचाने के मामले में सोपान दत्ताराव पवार (45) नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। भारतीय संविधान की प्रतिकृति के अपमान के तुरंत बाद, परभणी में मंगलवार को हिंसा हुई थी। बुधवार को परभणी में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी, जबकि पड़ोसी हिंगोली जिले के वासमत कस्बे में बंद का आयोजन किया गया।प्रदर्शनकारियों द्वारा परभणी रेलवे स्टेशन पर 'रेल रोको' का सहारा लेने और नंदीग्राम एक्सप्रेस के लोको-पायलट पर हमला करने के बाद हिंसा बढ़ गई। वंचित बहुजन अघाड़ी के संस्थापक-अध्यक्ष और दिवंगत अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा, परभणी में जातिवादी मराठा बदमाशों द्वारा बाबासाहेब की प्रतिमा पर भारत के संविधान की तोड़फोड़ बेहद शर्मनाक है। यह पहली बार नहीं है जब बाबासाहेब की प्रतिमा या दलित पहचान के प्रतीक के साथ इस तरह की बर्बरता हुई हो। अंबेडकर ने कहा, वीबीए परभणी जिले के कार्यकर्ता सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे और उनके विरोध प्रदर्शन के कारण पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और एक बदमाश को गिरफ्तार किया। मैं सभी से कानून और व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध करता हूं। अगर अगले 24 घंटों के भीतर सभी बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो परिणाम भुगतने होंगे। राज्य विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा- परभणी में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई क्योंकि पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई नहीं की गई।

दिल्ली में ...

अधिसूचना में कहा गया है, नशीले पदार्थों के खतरे को रोकने के लिए, एक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें सभी मौजूदा लाइसेंसधारियों से अनुरोध किया गया है कि वे 222.pledge.mygov.in/fight-againstdrugabuse/ वेबसाइट पर ई-शपथ लें और प्रमाण पत्र बनाएं और उसी प्रमाण पत्र को रेस्तरां में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करें, ताकि होटल/क्लब/रेस्तरां में आने वाले लोग/ग्राहक इसे आसानी से देख सकें। इसके अलावा, सभी लाइसेंसधारियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी कर्मचारियों और ग्राहकों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए नशीली दवाओं से दूर रहने के लिए सचेत रूप से सहयोग करने के लिए जागरूक करें।

एफआरएस के...

हो गया। कई वर्षों तक पकड़े जाने से बचने के बाद, दिल्ली पुलिस ने मामले को सुलझाने के लिए स्त्रक्र तकनीक का इस्तेमाल किया। जांच के दौरान, धोखाधड़ी वाले ऋष्ठ से जुड़े बैंक खाता खोलने के फॉर्म की एक तस्वीर को एफआरएस प्रणाली के माध्यम से संसाधित किया गया। मौजूदा राज्य डोजियर से 72 प्रतिशत मिलान पाया गया, जिससे पता चला कि संदिग्ध की असली पहचान टैगोर गार्डन इलाके के निवासी पंकज सचदेवा के रूप में है। डीसीपी ने कहा, सचदेवा रोशन मनचंदा के रूप में एक फर्जी नाम का इस्तेमाल कर रहा था और अपनी धोखाधड़ी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए पैन कार्ड और वोटर आईडी सहित कई पहचान दस्तावेज तैयार किए थे। वह जालसाजी और धोखाधड़ी से जुड़े तीन अन्य आपराधिक मामलों से भी जुड़ा था। एफआरएस परिणामों के आधार पर, सचदेवा को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई गई थी। टैगोर गार्डन में उसके आवास पर छापा मारा गया, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ करने पर, उसने अपने साथियों सुहैल चौहान और नितिन वर्मा की संलिप्तता का खुलासा किया, जिन्होंने ऋष्ठ प्रक्रिया को सुगम बनाया था और लाभार्थियों के रूप में 18.4 लाख रुपये प्राप्त किए थे। बाद में दोनों को उत्तर प्रदेश के मेरठ और हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया।

पायनियर
लखनऊ, बृहस्पतिवार, 12 दिसंबर, 2024

अरबपति जॉर्ज सोरोस और नेहरू गांधी परिवार के बीच गहरे संबंध

भाजपा ने कांग्रेस पर अपना हमला तेज करते हुए लगाया आरोप

नई दिल्ली। (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को कांग्रेस पर अपना हमला तेज करते हुए आरोप लगाया कि अमेरिका में रह रहे अरबपति जॉर्ज सोरोस और नेहरू-गांधी परिवार के बीच संबंध गहरे हैं जो फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स - एशिया पैसिफिक (एफडीएल-एपी) के सह-अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी की भूमिका से कहीं अधिक आगे तक फैले हैं।सत्तारूढ़ पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट में मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा, सोरोस की तरह हंगरी की फोरी नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई बी के नेहरू से शादी की थी और इस लिहाज से वह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नजदीकी रिश्तेदार हुईं।

भाजपा ने दावा किया कि जॉर्ज सोरोस ने फोरी नेहरू से मुलाकात की थी और उनके साथ लंबे समय तक पत्राचार बनाए रखा था। पार्टी के कहा कि यह संबंध तब से हैं जब बीके नेहरू ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया था।भाजपा ने आरोप लगाया, यह सवाल उठाता है कि नेहरू-गांधी परिवार ने अपने विस्तारित परिवार के वित्तीय और उद्यमशीलता के हितों को लाभ पहुंचाने के लिए दशकों से भारत के रणनीतिक हितों से किस हद तक समझौता किया है। पार्टी ने आरोप लगाया, जॉर्ज सोरोस और नेहरू-गांधी परिवार के बीच संबंध बहुत गहरे हैं, जो फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स-एशिया पैसिफिक (एफडीएल-एपी) के सह-अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी की भूमिका से कहीं अधिक व्यापक हैं। भाजपा पिछले हफ्ते से इस मुद्दे पर आक्रामक है जब उसने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जॉर्ज सोरोस समर्थित उन संगठनों के साथ संबंध हैं, जो कथित तौर पर भारतविरोधी गतिविधियों में शामिल हैं।कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इस असली साजिश का पर्दाफाश हो रहा है कि उद्योगपति गौतम अदाणी को बचाने के लिए सरकार ने दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों को भी दांव पर लगा दिया है। कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा है कि सोरोस द्वारा वित्तपोषित फंड चलाने वाले कई लोगों के साथ भाजपा नेताओं की सांठगांठ है। कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल किया है कि जॉर्ज सोरोस अगर देश विरोधी गतिविधियां संचालित कर रहा है तो उसका धंधा-पानी हिंदुस्तान में क्यों चल रहा है?

मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की रचनाओं के संग्रह का विमोचन किया

नई दिल्ली। (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की संपूर्ण रचनाओं के संग्रह का विमोचन किया और उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनके जैसा व्यक्तित्व सदियों में एक बार आता है। मोदी ने कहा कि भारती के विचार और बौद्धिक प्रतिभा आज भी लोगों को प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री ने अपने 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर इस संग्रह का विमोचन किया। भारती की संपूर्ण रचनाओं का 23 खंडों का संग्रह सीनी विश्वनाथन द्वारा संकलित और संपादित किया गया है। इसमें सुब्रमण्यम भारती के लेखन के संस्करणों, व्याख्याओं, दस्तावेजों, पृष्ठभूमि की जानकारी और दार्शनिक प्रस्तुति आदि का विवरण शामिल है। इसे अलायंस पब्लिशर्स ने प्रकाशित किया है।

इस अवसर पर अपने संबोधन में मोदी ने कहा, हमारे देश में शब्दों को महज अभिव्यक्ति नहीं माना जाता। हम उस संस्कृति का हिस्सा हैं जो शब्द ब्रह्म की बात करती है, शब्दों की अनंत शक्ति के बारे में बात करती है। उन्होंने कहा कि भारती ऐसे मनीषी थे जो देश की आवश्यकताओं को देखते हुए काम करते थे और उनका दृष्टिकोण इतना व्यापक था कि उन्होंने हर उस दिशा में काम किया जिसकी जरूरत उस कालखंड में देश को थी।

उन्होंने कहा, भारतियार केवल तमिलनाडु और तमिल भाषा की ही धरोहर नहीं है, वो एक ऐसे विचारक थे जिनकी हर सांस मां भारती की सेवा के लिए समर्पित थी। भारत का उत्कर्ष उनका सपना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने कर्तव्य भावना से भारतियार के योगदान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए, जितना हो सके उतना प्रयास किया है।उन्होंने कहा, भारती जैसा व्यक्तित्व सदियों में कभी एक बार मिलता है। उनका चिंतन, उनकी मेधा, उनका बहु-आयामी व्यक्तित्व... ए आज भी हर किसी को हैरान करता है।

मोदी ने कहा कि उनके और भारती के बीच एक जीवंत संबंध है और वह काशी से जुड़ा है।उन्होंने कहा, वह काशी में ज्ञान प्राप्त करने आए थे और आज भी उनके परिवार के सदस्य वहां रहते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में वाराणसी (काशी) का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मोदी सरकार ने सरकारी बैंकों को निजी फाइनेंसर में तब्दील कर दिया: राहुल

नई दिल्ली।(भाषा) लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ताकतवर कारोबारी समूहों के लिए निजी फाइनेंसर के रूप में तब्दील कर दिया है। उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद यह आरोप लगाया। राहुल गांधी ने मुलाकात का वीडियो साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रत्एक भारतीय तक ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। मोदी सरकार ने जनता की इन जीवनरेखाओं को केवल अमीर और शक्तिशाली समूहों के लिए निजी फाइनेंसर में बदल दिया है। उनका कहना था, मैं ऑल इंडिया बैंकिंग ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के एक प्रतिनिधिमंडल से मिला जिन्होंने हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थिति और आम लोगों पर इसके प्रभाव पर अपनी पीड़ा व्यक्त की। राहुल गांधी ने दावा किया, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लोगों के मुकाबले लाभ को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर किया जा रहा है और इस प्रकार वे प्रभावी ढंग से जनता की सेवा करने में असमर्थ हैं। कर्मचारियों की कमी और कामकाज के खराब माहौल के साथ उनसे समान अवसर के बिना असंभव लक्ष्यों को हासिल करने की उम्मीद की जाती है। उनके अनुसार, महिला कर्मचारियों को समान अवसर या पदोन्नति नहीं दी जाती और बैंक कर्मियों को असंतुष्ट जनता के आक्रोश का भी सामना करना पड़ता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, मोदी सरकार को अपने जालसाज दोस्तों के लिए धन के असीमित स्रोत के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का उपयोग बंद करना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वर्ष के अंत में सरकार को लाभांश चेक देने के अलावा और भी बहुत कुछ होता है।

प्रणब बाबू अपनी तरह की अनूठी हस्ती थे: प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और कहा कि वह एक ऐसी अनूठी हस्ती थे जो एक उत्कृष्ट राजनेता होने के साथ ही अद्भुत प्रशासक और ज्ञान का भंडार भी थे।कांग्रेस के वरिष्ठ एवं अनुभवी नेता मुखर्जी ने भारत का 13 वां राष्ट्रपति बनने से पहले कई सरकारों में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। 31 अगस्त, 2020 को 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा,"प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं। प्रणब बाबू एक ऐसी अनूठी हस्ती थे जो एक उत्कृष्ट राजनेता होने के साथ ही अद्भुत प्रशासक और ज्ञान का भंडार भी थे"। उन्होंने कहा,"भारत के विकास में उनका योगदान उल्लेखनीय है। उनके पास विभिन्न क्षेत्रों में आम सहमति बनाने की अद्भुत क्षमता थी और यह शासन में उनके व्यापक अनुभव और भारत की संस्कृति एवं लोकाचार के बारे में उनकी गहरी समझ के कारण संभव हुआ"। मोदी ने कहा,"हम अपने देश के लिए उनके दृष्टिकोण को साकार करने के वास्ते काम करते रहेंगे"।

राजमार्ग पर आईईडी बरामद

श्रीनगर। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बुधवार को हंदवाड़ा-बारामुला राजमार्ग पर एक संदिग्ध इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) का पता लगाकर उसे निष्क्रिय कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और सेना के संयुक्त गश्ती दल को कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा क्षेत्र स्थित लंगेट में राजमार्ग के किनारे एक संदिग्ध बैग मिला।उन्होंने बताया कि बम निरोधक दस्ते को मौके पर भेजा गया और संदिग्ध बैग को एक निर्जन इलाके में ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि बम निरोधक दस्ते ने संदिग्ध आईईडी को नष्ट कर दिया और इससे कोई नुकसान नहीं हुआ।

बीजापुर में नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या

बीजापुर।(भाषा) छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोमनपल्ली गांव में नक्सलियों ने कुड़ियाम माडो (35) की गला घोट कर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार रात नक्सलियों का दल सोमनल्ली गांव पहुंचा और उन्होंने कुड़ियाम माडो को घर से बाहर निकाला। बाद में नक्सलियों ने माडो की गला घोटकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर नक्सली वहां से फरार हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर घटनास्थल के लिए पुलिस दल रवाना किया गया। पुलिस ने घटनास्थल से नक्सलियों के नेशनल पार्क एरिया कमेटी की ओर से जारी पर्चा बरामद किया है जिसमें उन्होंने ग्रामीण पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि फरसेगढ़ थाने की पुलिस ने शव बरामद कर लिया है तथा नक्सलियों की खोज की जा रही है।

झारखंड में एक महिला ने अपनी नवजात बालिका को नदी में फेंका

जमशेदपुर। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में एक महिला ने अपनी नवजात बालिका को एक नदी में कथित रूप से फेंक दिया जिससे उसकी (बच्ची की) मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। उसने बताया कि जादूगोरा के डुरकु गांव में 30 वर्षीय यह महिला अपनी बेटी के साथ नहाने गई थी और उसने उसे नदी में फेंक दिया। पुलिस उपाधीक्षक (मुसाबनी) संदीप भगत ने बताया कि बच्ची का शव सोमवार को मिला। भगत ने बताया कि महिला के पति ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई है लेकिन उसकी (महिला की) इस हरकत की सटीक वजह का तत्काल पता नहीं चल पाया है।उन्होंने बताया कि महिला को गिरफ्तार कर मामले की जांच की जा रही है।

एआई के उपयोग पर कानून लाने को तैयार: वैष्णव

नई दिल्ली। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि अगर सदन और समाज की सहमति होगी तो सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग के संदर्भ में कानून लाने के लिए तैयार है। उन्होंने सदन में कांग्रेस सांसद अदूर प्रकाश के पूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। अदूर प्रकाश ने सवाल किया था कि क्या एआई के उपयोग के विनियमन को लेकर सरकार की कोई कानून बनाने की योजना है? इस के जवाब में वैष्णव ने कहा कि सोशल मीडिया के इस दौर में दुनिया भर का समाज चुनौतियों का सामना कर रहा है तथा फर्जी समाचार और फर्जी विमर्श से जुड़ी चुनौतियां हैं। उनका कहना था कि इसे (कानून को) लेकर व्यापक सहमति की जरूरत है क्योंकि ए मुद्दे ऐसे हैं जिनसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जुड़ी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, इस पर चर्चा की जरूरत है। अगर सदन सहमत हो और समाज में व्यापक सहमति हो तो हम नया कानून ला सकते हैं। हम इसके लिए तैयार हैं। वैष्णव ने यह भी कहा कि मोदी सरकार प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करने में विश्वास रखती है, जो कांग्रेस शासन के दौरान नहीं था।

डीएमआरसी अपने चौथे चरण के विस्तार के तहत 40 किमी भूमिगत गलियारों का कर रहा है निर्माण

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) अपने चौथे चरण के विस्तार के तहत 40 किलोमीटर से अधिक के भूमिगत गलियारों का निर्माण कर रहा है जो पांच विभिन्न गलियारों में विकसित की जा रही कुल लाइनों का करीब आधा हिस्सा है। निगम के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। निगम चौथे चरण में कुल 27 भूमिगत स्टेशनों का निर्माण कर रहा है। अधिकारी ने कहा कि डीएमआरसी पहले ही जनकपुरी पश्चिम से कृष्णापार्क तक दो करीब दो किलोमीटर के भूमिगत खंड के निर्माण का कार्य पूरा कर चुका है जो मैजेंटा लाइन का विस्तार है। दिल्ली मेट्रो अपने चौथे चरण के तहत 40.109 किलोमीटर नए भूमिगत गलियारे का निर्माण कर रही है। इस चरण में पांच अलग-अलग गलियारों में लगभग 86 किलोमीटर नई लाइनें बिछाई जा रही हैं। अधिकारी ने कहा कि यह एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है क्योंकि भूमिगत गलियारे विभिन्न भू-स्तरों से होकर गुजर रहे हैं जैसे कि सदर बाजार, नबी करीम, महरौली बदरपुर रोड, अजमल खान पार्क, नई दिल्ली आदि में भीड़भाड़ वाले आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र। अधिकारी ने बताया कि आम तौर पर डीएमआरसी पारंपरिक कट-एंड-कवर तकनीक का उपयोग करके भूमिगत मेट्रो स्टेशनों का निर्माण करता है, जबकि सुरंगों का निर्माण टनल बोरिंग मशीनों (टीबीएम) की मदद से किया जाता है।

जम्मू में संयुक्त राष्ट्र के दो सदस्यीय दल ने रोहिंग्या मुसलमानों से की मुलाकात

जम्मू। (भाषा) अवैध रूप से बसे प्रवासियों को बिजली और पानी उपलब्ध कराया जाए या नहीं इसे लेकर हो रही बहस के बीच संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) के दो सदस्यीय दल ने यहां एक झुग्गी बस्ती में रोहिंग्या मुसलमानों से मुलाकात की। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि वरिष्ठ संरक्षण अधिकारी तोमोको फुकुमुरा ने संरक्षण सहयोगी रागिनी त्राक्रू जुत्शी के साथ सोमवार को नरवाल के कियानी तालाब क्षेत्र में रोहिंग्या मुसलमानों तथा कुछ स्थानीय लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि टीम के प्रमुख बुधवार शाम को दिल्ली लौट जाएंगे। उन्होंने बताया कि पुलिस के कुछ अधिकारियों से मिलने का उनका प्रयास विफल हो गया है। जम्मू कश्मीर के जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा ने सात दिसंबर को कहा था कि प्रवासियों को वापस भेजने के संबंध में केंद्र सरकार का निर्णय आने तक, उनकी झुग्गियों में पानी की आपूर्ति बंद नहीं की जाएगी। राणा का यह बयान जम्मू के नरवाल क्षेत्र में तीन भूखंडों पर रह रहे रोहिंग्याओं के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि यूएनएचसीआर में पंजीकृत होने के बावजूद हाल ही में उनकी बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दो दिन बाद कहा कि केंद्र को जम्मू में बसे रोहिंग्याओं के बारे में फैसला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें भूख या ठंड से मरने नहीं दिया जा सकता। अब्दुल्ला ने पत्रकारों से कहा था, यह एक मानवीय मुद्दा है और केंद्र सरकार को रोहिंग्याओं के बारे में फैसला करना चाहिए। अगर आप उन्हें वापस भेज सकते हैं, तो उन्हें वापस भेजें और नहीं भेज सकते, तो हम उन्हें भूखा नहीं मरने दे सकते है। उन्हें ठंड से मरने नहीं दिया जा सकता। हालांकि, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रोहिंग्याओं तथा बांग्लादेशी नागरिकों को जम्मू में बसाने को एक बड़ी राजनीतिक साजिश बताया और उन्हें शहर में लाने एवं बसाने में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की मांग की। विस्थापितों को पानी और बिजली कनेक्शन देने को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा ने आरोप लगाया कि ऐसा उन्हें बचाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि वे एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जम्मू समेत जम्मू-कश्मीर के अन्य जिलों में 13,700 से अधिक विदेशी बसे हुए हैं, जिनमें से अधिकतर रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी नागरिक हैं। दक्षिण जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय शर्मा ने 25 नवंबर को कहा कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार पुलिस को सूचना दिए बिना रोहिंग्याओं और अन्य लोगों को अपनी संपत्तियां किराए पर देने वाले मकान मालिकों के खिलाफ एक बड़े अभियान में 18 प्राथमिकियां दर्ज की गईं।

बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो एक मुस्लिम समेत दो उपमुख्यमंत्री बनने चाहिए: कांग्रेस नेता

पटना। (भाषा) बिहार में सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से तकरार के बीच कांग्रेस के नेता शहनवाज आलम ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी चाहेगी कि राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने पर उसके दो उपमुख्यमंत्री बनाए जाएं, जिनमें से एक मुसलमान हो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के सचिव और राज्य के सह पार्टी प्रभारी आलम के इस बयान पर राजद ने आपत्ति जताई जबकि सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल दलों जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चुटकी ली।

फिलहाल राज्य का दौरा कर रहे आलम ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए कहा,"हमारा संकल्प है कि अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगली सरकार बनती है, तो हमारी पार्टी से दो उपमुख्यमंत्री बनने चाहिए, जिसमें से एक मुस्लिम और दूसरा उच्च जातियों (सामान्य वर्ग) से होना चाहिए। आलम के बयान को खोया हुआ पारंपरिक जनाधार वापस पाने की कांग्रेस की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमे दलित, मुसलमान और उच्च जाति वर्ग शामिल हैं। हालांकि, यह बात राजद को पसंद नहीं आई, जिसे कांग्रेस का मुस्लिम जनाधार खिसकने से फायदा हुआ है। पार्टी आलम की हालिया टिप्पणी से विशेष रूप से नाराज है कि विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे के फार्मूले को अंतिम रूप देते समय"लोकसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट पर विचार किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि आम चुनावों में कांग्रेस ने नौ सीटों पर चुनाव लड़कर केवल तीन सीट जीती थीं, जबकि राजद ने 23 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे केवल चार सीट पर जीत मिली। इस हिसाब से कांग्रेस अपने प्रदर्शन को राजद से बेहतर बता रही है। आलम के आक्रामक रुख से तेजस्वी यादव के पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद नाराज दिखाई दिए और उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के दावे को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन किया था। लालू के बयान को कांग्रेस और राजद के बीच खटपट के तौर पर देखा गया।

आलम अपने रुख पर कायम नजर आए जबकि राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रतिक्रिया व्यक्त हुए कहा,"ऐसे बयान गठबंधन धर्म का उल्लंघन करते हैं। कांग्रेस को ऐसे बेलगाम बयानबाजों पर लगाम लगानी चाहिए"। इस बीच, जनता दल (यूनाइटेड) के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) खालिद अनवर ने मुसलमानों तक पहुंच बनाने के आलम के दावों को खारिज करते हुए कहा,"समुदाय यह नहीं भूल सकता कि कांग्रेस के शासन में ही मेरठ, भागलपुर और जबलपुर में दंगे हुए थे। गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ नेताओं को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। बिहार में हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनावों में मुसलमानों का रूझान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राजग की ओर दिखा है।

भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचोल ने भी मुस्लिम उपमुख्यमंत्री की कांग्रेस की मांग की आलोचना करते हुए इसे "तुष्टिकरण की राजनीति का एक और उदाहरणै बताया। भाजपा नेता ने कहा,"2025 और 2029 के बीच बिहार में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के पदों के लिए कोई रिक्ति नहीं है। नीतीश कुमार बने रहेंगे, और हमारी पार्टी तय करेगी कि उपमुख्यमंत्री कौन होंगे।

रेलवे में 58,642 खाली पड़े पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है: रेल मंत्री

नई दिल्ली। केंद्र सरकार को रेलवे में युवाओं को अधिक से अधिक अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध बताते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि रेलवे में 58,642 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। रेल मंत्री ने लोकसभा में रेल (संशोधन) विधेयक, 2024 पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह बात कही। उनके जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। वैष्णव ने कहा, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि संप्रग सरकार के समय 4,11,000 लोगों को रेलवे में नौकरी मिली थी, जबकि मोदी सरकार में 5,02,000 युवाओं की भर्ती रेलवे में की गई है।

चंडीगढ़ : सिख धर्मगुरु ढडरियांवाले पर बलात्कार और हत्या का मामला हुआ दर्ज

चंडीगढ़।(भाषा) पंजाब पुलिस ने पटियाला में 2012 में एक महिला के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मामले में सिख धर्मगुरु रंजीत सिंह ढडरियांवाले के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी गई। पंजाब पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा मंगलवार को उच्च न्यायालय में दायर हलफनामे के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत सात दिसंबर को पटियाला के पासियाना पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह प्राथमिकी पीड़िता के भाई की शिकायत पर दर्ज की गई थी। पटियाला के शेखपुरा गांव में गुरुद्वारा परमेश्वर द्वार के प्रमुख सिख उपदेशक ढडरियांवाले के पंजाब और विदेशों में बड़ी संख्या में अनुयाई हैं। ढडरियांवाले ने एक वीडियो संदेश में कहा कि वह पुलिस जांच में सहयोग करेंगे। सिख उपदेशक ढडरियांवाले ने कहा,"उन्होंने (परिवार ने) उच्च न्यायालय का रुख किया है। उन्हें संदेह है और उन्हें अपना संदेह दूर करना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मामले की जांच करें। इसमें कुछ समय लग सकता है लेकिन सच्चाई सामने आएगी। मुझे उच्च न्यायालय और पंजाब पुलिस पर पूरा भरोसा है"। पुलिस महानिदेशक का हलफनामा पीड़िता के भाई द्वारा लगाए गए आरोप के बाद आया है। पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने (पीड़िता के भाई) यह भी आरोप लगाया कि घटना के समय पुलिस ने कोई कार्वाई नहीं की। महिला के भाई की याचिका पर नवंबर में सुनवाई हुई थी।

तेलुगु अभिनेता मोहन बाबू के बेटे की घर में प्रवेश की कोशिश से तनाव

हैदराबाद। (भाषा) तेलुगु अभिनेता मोहन बाबू के छोटे बेटे मनोज द्वारा जलपल्ली इलाके में उनके घर पर जबरन घुसने के प्रयास किए जाने से मंगलवार को वहां अफरा-तफरी मच गई और घटनाक्रम को कवर कर रहे एक पत्रकार पर भी कथित तौर पर हमला किया गया। मनोज भी एक अभिनेता है। उन्होंने जबरदस्ती घर के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन वहां तैनात निजी सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। टेलीविजन फुटेज में मोहन बाबू को एक पत्रकार को पीटने की कोशिश करते हुए दिखाया गया। वह पत्रकार माइक्रोफोन से इस घटना को कवर कर रहा था और खबरों के अनुसार उसे चोटें आई हैं। मोहन बाबू के परिवार में मतभेद का यह मामला सोमवार को उस समय खुलकर सामने आ गया जब उन्होंने पुलिस में यह शिकायत दर्ज कराई कि मनोज और उनकी पत्नी ने धमकी एवं बलपूर्वक जलपल्ली स्थित उनके घर पर कब्जा करने की योजना बनाई है। मनोज ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि वह संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं। मनोज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अपने पिता द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार और झूठा बताया।

मोहन बाबू के बड़े बेटे विष्णु ने कहा कि पारिवारिक मुद्दे सुलझा लिए जाएंगे। मोहन बाबू की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पहले ही मनोज और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। उन्होंने ने सोमवार को अपनी शिकायत में मनोज और उसके द्वारा किराए पर रखे गए कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आठ दिसंबर को उनके आवास पर उपद्रव किए जाने का आरोप लगाया। मोहन बाबू ने सोमवार को अपनी शिकायत में कहा कि मनोज और उसके द्वारा किराए पर रखे गए कुछ असामाजिक तत्वों ने आठ दिसंबर को उनके आवास पर उपद्रव किया। मोहन बाबू के अनुसार उनके एक कर्मचारी ने सोमवार को उन्हें बताया कि 30 व्यक्ति उनके घर पर जबरन घुस आए, कर्मचारियों को धमकाया और उन्हें परिसर से बाहर निकाल दिया। वरिष्ठ तेलुगू अभिनेता ने आरोप लगाया कि मनोज और उनकी पत्नी के निर्देश पर इन लोगों ने उनके घर पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। मोहन बाबू ने पुलिस से मनोज, उनकी पत्नी और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्वाई करने तथा उन्हें घर से बाहर निकालने का अनुरोध किया। उन्होंने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सुरक्षा का भी अनुरोध किया। पुलिस ने मनोज की शिकायत पर भी मामला दर्ज किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आठ दिसंबर को 10 अज्ञात लोग घर में घुसे और जब उसने उन्हें देखा तो उन लोगों ने भागने की कोशिश की।

अभिनेता मोहन बाबू पर हैदराबाद में पत्रकार पर हमला करने के आरोप में मामला दर्ज

हैदराबाद। (भाषा) तेलंगाना में दिग्गज तेलुगू अभिनेता मोहन बाबू के खिलाफ एक वीडियो पत्रकार पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। शिकायत में पत्रकार ने कहा कि जब वह 10 दिसंबर को मोहन बाबू और उनके छोटे बेटे मनोज के बीच हो रहे विवाद को कवर करने के लिए उनके जलपल्ली स्थित आवास पर गए, तो तेलुगू अभिनेता मोहन बाबू ने उनपर हमला कर दिया। उन्होंने कथित तौर पर माइक छीन लिया और अपमानजनक एवं अभद्र भाषा का प्रयोग किया तथा उससे (माइक) उन पर हमला कर दिया, जिससे उनके (पत्रकारों) सिर में चोट लग गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि 35 वर्षीय पत्रकार की शिकायत के आधार पर पहाड़ीशरीफ पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 118 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मंगलवार की रात मोहन बाबू के आवास पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब अभिनेता मनोज ने घर में घुसने का प्रयास किया लेकिन उन्हे अंदर जाने से रोक दिया गया। हंगामे के दौरान घटना को कवर कर रहे वीडियो पत्रकार पर कथित तौर पर हमला किया गया। टीवी पर दिखाए गए दृश्यों में मोहन बाबू को पत्रकार पर माइक से हमला करने की कोशिश करते हुए दिखाया गया। इस हमले की निंदा करते हुए मीडियाकर्मियों ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया और मोहन बाबू से माफी की मांग की। इस बीच अभिनेता को तबियत खराब होने की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। संबंधित घटनाक्रम में मोहन बाबू और उनके दो बेटों विष्णु एवं मनोज को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126 के तहत संभावित शांति भंग के आरोप में 11 दिसंबर को रचकोंडा पुलिस आयुक्त के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया। मोहन बाबू के परिवार के भीतर मतभेद नौ दिसंबर को सार्वजनिक हो गए, जब उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि मनोज और उनकी पत्नी ने धमकी और बल के माध्यम से उनके जलपल्ली स्थित घर पर कब्जा करने की योजना बनाई है। हालांकि मनोज ने बुधवार को दोहराया कि उनकी लड़ाई संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए नहीं बल्कि आत्मसम्मान और अपनी पत्नी और बच्चों की सुरक्षा के लिए है। उन्होंने पहले ही अपने परिवार के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए विष्णु ने उम्मीद जताई कि पारिवारिक मुद्दे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ जाएंगे।

उत्तरी गाजा में इजराइल के हमले में 29 लोगों की मौत

काहिरा। उत्तरी गाजा पट्टी में इजराइल द्वारा रात भर किए गए हमले में कम से कम 29 लोग मारे गए हैं। इजराइल ने इस दौरान एक मकान को भी निशाना बनाया जहां विस्थापितों ने शरण ले रखी थी। फलस्तीनी चिकित्सा अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मकान को निशाना बनाकर किए गए इजराइल के हमले में 19 लोग मारे गए। इजराइल-हमास युद्ध अब भी जारी है और इसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। हालांकि, इजराइल ने लेबनान के हिज्बुल्ला के साथ संघर्ष विराम समझौता किया है और सभी का ध्यान सत्ता से हटाए गए सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद पर केंद्रित हो गया है।कमाल अदवान अस्पताल ने बताया कि इजराइल की सीमा के पास उत्तरी शहर बेत लहिया में रात भर जारी हमले के बाद बुधवार को हताहतों को अस्पताल लाया गया था। हमले में 19 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल के रिकॉर्ड से पता चलता है कि मारे गए लोगों में आठ लोगों का एक परिवार शामिल था, जिसमें चार बच्चे, उनके माता-पिता और दादा-दादी शामिल थे। अस्पताल ने बताया कि बुधवार को प्रवेश द्वार के पास हुए एक अन्य हमले में एक महिला और उसके दो बच्चों की मौत हो गई।अस्पताल ने बताया कि मध्य गाजा में नुसेरात शरणार्थी शिविर को निशाना बनाकर किए गए एक और हमले में कम से कम सात लोग मारे गए। मृतकों में दो बच्चे, उनके माता-पिता और तीन रिश्तेदार शामिल हैं। इस मामले में इजराइल की सेना ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। सेना का कहना है कि उसकी कोशिश यही रहती है कि नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे और आरोप लगाती है कि आतंकवादी नागरिकों के बीच छुपकर उनकी जान को खतरे में डालते हैं।सेना ने मध्य गाजा में बने माघाजी शरणार्थी शिविर के पांच ब्लॉक क्षेत्र को खाली करने का आदेश दिया था। आदेशों से संकेत मिलता है कि इजराइल जल्द इस क्षेत्र में हमले करेगा। इजराइल अक्टूबर की शुरुआत से ही उत्तरी गाजा में हमास आतंकवादियों के विरुद्ध नए सिरे से हमले कर रहा है। युद्ध की शुरुआत तब हुई जब सात अक्टूबर, 2023 को हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादियों ने इजराइल पर धावा बोल दिया।

ट्रंप ने एंड्रयू फर्गुसन को एफटीसी प्रमुख, किबर्ली गिलफॉयल को ग्रीस के लिए राजदूत नामित किया

वाशिंगटन। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एंड्र्यू फर्गुसन को फेडरल ट्रेड कमिशन (एफटीसी) के अगले प्रमुख के तौर पर नामित किया है। फर्गुसन लीना खान की जगह लेंगे, जो अरबों डॉलर के कॉरपोरेट अधिग्रहणों को अवरुद्ध करके तथा प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार का आरोप लगाते हुए अमेजन और मेटा पर मुकदमा दायर करके चर्चा का केंद्र बन गई थीं। ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच के जरिए किंबर्ली गिलफॉयल को ग्रीस के लिए अमेरिका का राजदूत नामित किया। गिलफॉयल लंबे समय से ट्रंप की समर्थक रही हैं और उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर से उनकी सगाई हुई थी।

ट्रंप ने टॉम बराक को तुर्किए में राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की औरउन्हें एक सम्मानित और अनुभवी आवाज कहा। फर्ग्यूसन पहले से ही एफटीसी के पांच आयुक्तों में से एक हैं, जिसमें वर्तमान में डेमोक्रेटिक पार्टी से तीन सदस्य और रिपब्लिकन पार्टी से दो सदस्य हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, एंड्र्यू के पास बिग टेक सेंसरशिप के खिलाफ खड़े होने और हमारे महान देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने का रिकॉर्ड रहा है। जो बाइडन प्रशासन ने जिन सौदों को रोका था, उन्हें ट्रंप के नेतृत्व में नया जीवन मिलने की संभावना है। गिलफॉयल कैलिफोर्निया की एक पूर्व अभियोजक और टेलीविजन समाचार प्रस्तोता रही हैं। उन्होंने ट्रंप के 2020 अभियान के लिए धन जुटाने के कार्यक्रम का नेतृत्व किया था। ट्रंप ने उन्हें एक करीबी दोस्त और सहयोगी कहा तथा उनकी प्रशंसा की। वह 2020 से डोनाल्ड जूनियर से जुड़ी हैं। वह चुनाव की रात कन्वेंशन सेंटर में एक साथ पहुंचीं और परिवार के साथ मंच पर मौजूद थीं।

बेरूत। लेबनान में भारत के राजदूत नूर रहमान शेख ने सीरिया से निकाले गए 75 भारतीय नागरिकों का स्वागत किया, जिनमें जम्मू.कश्मीर के 44 जायरीन भी शामिल थे जो लेबनान के बेरूत में सईदा ज़ैनब में फंसे हुए थे। वे भारत के लिए उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों से लौटेंगे।

संजय भंडारी ने ब्रिटेन उच्च न्यायालय में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील दायर

लंदन। भारत में कर चोरी और धनशोधन के आरोप में वांछित व्यवसाई एवं रक्षा क्षेत्र में सलाहकार संजय भंडारी ने अपने प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ लंदन के उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। भंडारी (62) ने इस साल की शुरुआत में अपने प्रत्यर्पण को मंजूरी देने वाले नवंबर 2022 के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति हासिल की थी। न्यायाधीश टिमोथी होलरॉयड और न्यायाधीश कैरन स्टेन ने रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वकील जेम्स स्टैंसफेल्ड और एडवर्ड फिट्ज़गेराल्ड की ओर से दायर अपील के तीन मुख्य आधारों पर सुनवाई शुरू की।

भारतीय प्राधिकारियों की ओर से उपस्थित क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) सुनवाई के दौरान दलीलों का जवाब देंगे, जिसका प्रतिनिधित्व बैरिस्टर बेन कीथ और एलेक्स डू सौटॉय करेंगे। उसने मंगलवार को न्यायाधीशों के समक्ष अनुरोध किया कि अगले कुछ दिनों के लिए वीडियो लिंक तैयार करने की अनुमति दी जाए, ताकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत से कार्यवाही पर नजर रख सके। फिट्जगेराल्ड ने दिल्ली की तिहाड़ जेल के संदर्भ में अपनी दलीलों के दौरान दावा किया, कैदियों और जेल अधिकारियों की ओर से हिंसा या जबरन वसूली का खतरा है। भंडारी को प्रत्यर्पित किए जाने की स्थिति में उसे तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने पिछले साल प्रत्यर्पण का आदेश दिया था। भंडारी ने अपनी कंपनी ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस के माध्यम से भारतीय सरकारी अनुबंधों के लिए बोली लगाने वाले रक्षा निर्माताओं को परामर्श सेवाएं प्रदान की थीं। भंडारी ने जिला न्यायाधीश माइकल स्नो के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का अनुरोध किया था।

दक्षिण कोरिया में पूर्व रक्षामंत्री को आत्महत्या की कोशिश करने से रोका

भाषा। सियोल (दक्षिण कोरिया)

दक्षिण कोरिया में पिछले सप्ताह की गई मार्शल लॉ की घोषणा के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए पूर्व रक्षा मंत्री को हिरासत में आत्महत्या का प्रयास करने से रोक दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति यून सूक एओल के कार्यालय ने परिसर की तलाशी लेने के पुलिस के प्रयास का विरोध किया। मुख्य विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी ने तीन दिसंबर की घोषणा के सिलसिले में यून पर महाभियोग चलाने के लिए नया प्रस्ताव पेश करने की योजना बनाई है। इस घोषणा के बाद चार दशकों से अधिक की अवधि में पहली बार दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लग गया।

पिछले शनिवार को महाभियोग का पहला प्रयास विफल हो गया था क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी ने मतदान का बहिष्कार किया था। पार्टी ने कहा कि शनिवार को मत विभाजन के वास्ते बृस्पतिवार को नया प्रस्ताव सौंपने की उसकी योजना है। यून की गलत तरीके से सत्ता हथियाने की कोशिश ने दक्षिण कोरियाई राजनीति को पंगु बना दिया है, उसकी विदेश नीति को अवरुद्ध कर दिया है और वित्तीय बाजारों को हिलाकर रख दिया है। बुधवार को, प्रतिद्वंद्वी उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने पहली बार सीमा पार की उथल-पुथल के बारे में रिपोर्ट की, लेकिन देश ने कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं दिखाई।

कोरिया सुधार सेवा के महा आयुक्त जनरल शिन योंग हे ने सांसदों को बताया कि पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून ने पिछली रात सियोल के एक हिरासत केंद्र में खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि सुधार अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया और उनकी हालत स्थिर है। सियोल की एक अदालत ने विद्रोह में अहम भूमिका निभाने और सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोपों पर उनके खिलाफ वारंट को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद बुधवार को किम को गिरफ्तार कर लिया गया था।

मार्शल लॉ के आदेश के बाद औपचारिक रूप से गिरफ्तार होने वाले किम पहले व्यक्ति हैं। यून के कार्यालय ने राष्ट्रपति परिसर की तलाशी में बाधा डाली। बाद में पुलिस ने राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के आयुक्त जनरल चो जी हो और राजधानी सियोल की महानगरीय पुलिस एजेंसी के प्रमुख किम बोंग-सिक को हिरासत में ले लिया। उन पर सांसदों को मतदान करने से रोकने के लिए संसद में पुलिस बल तैनात करने का आरोप लगाया गया था।

ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो का उपहास उड़ाया, उन्हें कनाडा का गवर्नर कहा

वाशिंगटन। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का उपहास उड़ाते हुए उन्हें कनाडा का गवर्नर कहा। ट्रूडो पिछले सप्ताह ट्रंप के साथ रात्रिभोज के लिए उनके निजी क्लब मार-ए-लागो गए थे, जहां उन्होंने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की इस चेतावनी पर चर्चा की थी कि अगर कनाडा सरकार वहां से अमेरिका आने वाले अवैध प्रवासियों और अवैध मादक पदार्थों के प्रवाह को रोकने में विफल रहती है तो कनाडा पर 25 प्रतिशत शुल्क (कर) लगाया जाएगा। सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कनाडा के प्रधानमंत्री का उपहास उड़ाते हुए ट्रंप ने कहा, महान राज्य कनाडा के गवर्नर जस्टिन ट्रूडो के साथ रात्रिभोज करके खुशी महसूस हुई। रात्रिभोज के दौरान ट्रूडो ने चिंता जताते हुए कहा था कि इस तरह के शुल्क से कनाडा की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी।

क्विक न्यूज

दक्षिण कोरिया के दो शीर्ष पुलिस प्रमुखों को मार्शल लॉ लागू करने के आरोप में हिरासत में लिया गया

सियोल (दक्षिण कोरिया)। दक्षिण कोरिया के दो शीर्ष पुलिस अधिकारियों को पिछले सप्ताह राष्ट्रपति यून सुक एओल के मार्शल लॉ के आदेश को अमल मे लाने मे उनकी भूमिका की जांच के लिए हिरासत मे लिया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह घटनाक्रम विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से यून के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए नया प्रस्ताव पेश करने से कुछ घंटे पहले हुआ है। साथ ही देश की कानून प्रवर्तन संस्थाएं इस बात की जांच कर रही है कि क्या राष्ट्रपति की घोषणा विद्रोह के समान है या नही। पिछले शनिवार को महाभियोग का पहला प्रयास विफल हो गया था क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी ने मतदान का बहिष्कार किया था। डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा है कि उसका लक्ष्य शनिवार को नए प्रस्ताव पर मतदान कराना है। पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के आयुक्त जनरल चो जी हो और राजधानी सियोल की महानगरीय पुलिस एजेंसी के प्रमुख किम बोंग-सिक को सियोल के नामदामुन पुलिस थाने में हिरासत में रखा गया है।
पुलिस ने कहा कि नेशनल असेंबली में पुलिस बल तैनात करने में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि पुलिस बल इसलिए तैनात किया गया था कि सांसदो को राष्ट्रपति के मार्शल लॉ के खिलाफ मतदान करने से रोका जा सके।

सीरिया में असद सरकार का पतन अमेरिका और इजराइल की संयुक्त योजना : अयातुल्ला अली खामनेई

तेहरान। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा है कि सीरिया मे बसर असद सरकार का पतन सहित वहां का हालिया घटनाक्रम अमेरिका और इजराइल की संयुक्त योजना का हिस्सा है। खामनेई द्वारा दिए भाषण को ईरान के सरकारी चैनल पर प्रसारित किया गया। उन्होंने कहा, इसमे कोई संदेह नही होना चाहिए कि सीरिया मे जो कुछ हुआ है वह अमेरिकी और यहूदी (इजराइल के संदर्भ मे) योजना का परिणाम है। खामनेई ने कहा, हमारे पास सबूत है, और यह सबूत संदेह की कोई गुंजाइश नही छोड़ता। ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा, सीरिया के एक पड़ोसी देश ने इस मामले मे स्पष्ट भूमिका निभाई है, और वह ऐसा करना जारी रख रहा है। इसे हर कोई देख सकता है। खामेनेई ने विश्लेषको की उन अटकलो को भी खारिज कर दिया कि सीरिया मे राष्ट्रपति बशर अल-असद की सरकार के पतन से ईरान कमजोर हो जाएगा। उन्होंने कहा, वे अज्ञानी विश्लेषक प्रतिरोध के अर्थ से अनभिज्ञ है। उन्हे लगता है कि अगर प्रतिरोध कमजोर हुआ तो इस्लामिक ईरान भी कमजोर हो जाएगा। लेकिन मै कहना चाहता हूं, सर्वशक्तिमान अल्लाह की इच्छा से ईरान शक्तिशाली है तथा यह और भी अधिक शक्तिशाली बनेगा।

द. कोरिया के पूर्व रक्षा मंत्री ने की आत्महत्या की कोशिश

सियोल। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्युन ने आत्महत्या का प्रयास किया लेकिन उन्हे बचा लिया गया और उनकी हालत स्थिर है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। कोरिया सुधार सेवा के कमिश्नर जनरल शिन योंग हे ने बुधवार को सांसदो को बताया कि किम ने सियोल के एक हिरासत केंद्र मे आत्महत्या करने की कोशिश की हालांकि उन्हें बचा लिया गया और अब उनकी हालत स्थिर है। सियोल की एक अदालत ने विद्रोह मे अहम भूमिका निभाने और सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप मे किम के खिलाफ वारंट जारी किया था जिसके बाद बुधवार को उन्हे गिरफ्तार किया गया था। किम तीन दिसंबर को मार्शल लॉ के आदेश के बाद गिरफ्तार किए गए पहले व्यक्ति है।

काबुल में बम धमाका, शरणार्थी मामलों के मंत्री की मौत

इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल मे बुधवार को एक आत्मघाती बम धमाके मे तालिबान सरकार मे शरणार्थी मामलो के मंत्री की मौत हो गई। विस्फोट मंत्रालय के अंदर हुआ और शरणार्थी मामलों के मंत्री खलील हक्कानी की मौत हो गई। हक्कानी ऐसे शीर्षस्थ पदाधिकारी थे जिनकी अफगानिस्तान की सत्ता पर तीन साल पहले तालिबान द्वारा कब्जा किए जाने के बाद हुए बम धमाको मे मौत हुई है। धमाके की तत्काल किसी ने जिम्मेदारी नही ली है।

गाजा में दो माह से नहीं पहुंच पा रहीं मानवीय सहायता: संरा

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उत्तरी गाजा मे पिछले 66 दिनो से व्यापक पैमाने पर मानवीय सहायता नही पहुंच पा रही है। इजराइल ने छह अक्टूबर को उत्तरी गाजा मे जमीनी कार्वाई प्रांरभ की थी और इसके बाद से 65 हजार से 75 हजार फलस्तीनी नागरिक भोजन, पानी, बिजली तथा स्वास्थ्य सेवा की पहुंच से वंचित हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (ओसीएचओ) ने मंगलवार को कहा कि उत्तरी गाजा मे इजराइल ने बेत लाहिया, बेत हनून और जबालिया पर अपनी घेराबंदी जारी रखी है और वहां रहने वाले फलस्तीनियो को सहायता से वंचित रखा है।

सिंगापुर में भारतीय नागरिक को 16 महीने की जेल कीसजा

सिंगापुर। सिंगापुर में 58 इंडियन स्टार कछुओं को अवैध रूप से लाने के जुर्म में एक भारतीय नागरिक को 16 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई है। द स्ट्रेट्स टाइम्स की खबर के अनुसार, अब्दुल जाफर हाजी अली जब 29 अगस्त को जकार्ता के लिए दूसरी उड़ान में सवार होने के वास्ते भारत से चांगी हवाई अड्डे पहुंचे तो उनके निजी सामान में छिपाकर रखे गए ए कछुए मिले। अली (40) ने सिंगापुर में अवैध रूप से इंडियन स्टार कछुओं को लाने का दोष सोमवार को स्वीकार कर लिया। इन कछुओं को अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) द्वारा लुप्त होने के खतरे वाली श्रेणी में रखा गया है। अली को ए कछुए उसके दोस्त से मिले थे, जिसकी पहचान अदालती दस्तावेजों में भाई के रूप में की गई है। इसी शख्स ने अली की यात्रा की व्यवस्था में मदद की थी, जिसमें उसकी उड़ान का भुगतान और उसके रहने की व्यवस्था करना भी शामिल था।

नेपाल, भारत ने सहयोग बढ़ाने के लिए पहली पर्यटन बैठक आयोजित की

काठमांडू। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को बढ़ावा देने और दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन संबंधों को मजबूत करने के लिए काठमांडू में पहली नेपाल-भारत पर्यटन बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों ने इस क्षेत्र की क्षमता का पूरा लाभ उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम मंगलवार को नेपाल पर्यटन बोर्ड (एनटीबी) और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। भारतीय दूतावास द्वारा उप्र के प्रयागराज में महाकुंभ को बढ़ावा देने और नेपाल एवं भारत के बीच सर्किट पर्यटन (एक ही मार्ग पर कम से कम तीन प्रमुख पर्यटन स्थल हों जो एक ही कस्बे, गांव या शहर में नहीं हों और एक दूसरे से अधिक दूरी पर भी नहीं हों) के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ अगले साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए पर्यटन राज्य मंत्री अरुण कुमार चौधरी ने कहा कि विशेष रूप से स्थल मार्ग के जरिए सीमा पार पर्यटन, नेपाल में पर्यटन में बड़ा योगदान देता है। हालांकि इसे औपचारिक आंकड़ों में दर्ज नहीं किया जाता है। उन्होंने सलाह दी कि दोनों पक्षों को विशेष रूप से सुंदरपश्चिम प्रांत जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सीमा पार संपर्क पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख प्रसन्न श्रीवास्तव ने भारत-नेपाल पर्यटन क्षमता का पूर्ण लाभ उठाने के लिए दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त प्रयास किए जाने पर बल दिया, जिसमें नेपाल एवं निकटवर्ती भारतीय राज्यों को शामिल करते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक सर्किट भी शामिल हैं।

आर्कटिक में कुछ दशकों में ही महत्वपूर्ण बदलाव आया है

कोलोराडो। (द कन्वरसेशन) यदि आप आर्कटिक क्षेत्र में रहने वाले 40 लाख लोगों में से नहीं हैं तो यह आपको दैनिक जीवन से कटा हुआ एक दूरस्थ स्थान जैसा लग सकता है। इसके बावजूद, तापमान में वृद्धि के कारण आर्कटिक में होने वाले बदलाव दुनिया भर में जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। आर्कटिक ग्लेशियर और ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर से पिघला हुआ पानी महासागरों में जाने से तटीय बाढ़ की समस्या का कई समुदायों पर असर पड़ रहा है। आर्कटिक के जंगलों में लगी आग और पिघलते टुंड्रा से निकलने वाली ऊष्मा-अवरोधक गैसें तेजी से हवा में मिल जाती हैं, जिससे पृथ्वी गर्म हो रही है। टुंड्रा का अर्थ है आर्कटिक क्षेत्र में वृक्षविहीन पर्वतीय क्षेत्र का एक विशाल भूभाग।

असामान्य और प्रतिकूल मौसम की घटनाएं, खाद्य आपूर्ति पर दबाव और जंगली आग और उससे संबंधित धुएं से बढ़ते खतरे, ए सभी आर्कटिक को प्रभावित कर सकते हैं। हम 10 दिसंबर को जारी 2024 आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड में आर्कटिक पर्यावरण की स्थिति पर जानकारी देने के लिए 11 देशों के 97 वैज्ञानिकों को एक साथ लेकर आए हैं। इनके पास वन्यजीवों से लेकर जंगल की आग और समुद्री बर्फ से लेकर हिम तक की विशेषज्ञता है। उन्होंने आर्कटिक क्षेत्र में तेजी से हो रहे परिवर्तनों तथा विश्व के प्रत्एक क्षेत्र में लोगों और वन्य जीवन पर पड़ने वाले इसके परिणामों का वर्णन किया। आज का आर्कटिक एक या दो दशक पहले के आर्कटिक से आश्चर्यजनक रूप से भिन्न दिखता है। पिछले 15 वर्षों से आर्कटिक में बर्फबारी का मौसम ऐतिहासिक रूप से एक से दो सप्ताह कम रहा है, जिससे मौसम का समय और चरित्र बदल रहा है।

हिमपात का छोटा होता मौसम उन पौधों और जानवरों के लिए चुनौती बन सकता है जो नियमित मौसमी बदलावों पर निर्भर रहते हैं। लंबे समय तक बर्फ रहित मौसम के कारण वसंत या गर्मियों में बर्फ पिघलने से जल संसाधन भी कम हो सकते हैं और सूखे की आशंका बढ़ सकती है।

कुल मिलाकर, 2024 में आर्कटिक में 1900 में माप शुरू होने के बाद से दूसरा सबसे अधिक तापमान होगा तथा रिकॉर्ड पर सबसे अधिक बारिश वाली गर्मियां होंगी। जंगली आग का आकार और तीव्रता भी बढ़ गई है, जिससे वातावरण में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रही है, और जंगली आग लगने का समय भी लंबा हो गया है। इन परिवर्तनों ने टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र को चरमरा दिया है। सुसान नटाली और उनके सहयोगियों ने पाया कि आर्कटिक टुंड्रा क्षेत्र अब कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत बन गया है - न कि डूब या भंडारण स्थान। पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने के कारण यह पहले से ही मीथेन का स्रोत था। पर्माफ्रॉस्ट वह जमीन है जो कम से कम दो साल तक पूरी तरह से जमी हुई अवस्था में रहती है। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड प्रत्एक वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक का होता है और 2024 आर्कटिक के लिए रिकॉर्ड पर दूसरा सबसे गर्म वर्ष होगा।

पाक सेना के खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने के आरोप में 22 लोग गिरफ्तार

लाहौर। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने के आरोप में 150 संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उनमें से 22 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में से ज्यादातर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी से जुड़े है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अनुसार 26 नवंबर को इस्लामाबाद में प्रदर्शनकारियों पर कानून प्रवर्तकों द्वारा की गई गोलीबारी में कम से कम 12 पार्टी कार्यकर्ता मारे गए थे और सैकड़ों घायल हो गए थे। पार्टी का यह भी दावा है कि तब से लगभग 105 पार्टी कार्यकर्ता लापता हैं।

घटना के बाद, खान के समर्थकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी करने के लिए पाकिस्तानी सेना को दोषी ठहराना शुरू कर दिया था। शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने इस बात से इनकार किया कि कानून प्रवर्तकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। उन्होंने सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्वाई करने की प्रतिबद्धता जताई।

सरकार ने ऐसे तत्वों पर नकेल कसने के लिए संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के प्रमुख की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यबल का गठन किया। एफआईए के एक अधिकारी ने कहा, इसके बाद, एफआईए की साइबर अपराध शाखा ने देशभर में लगभग 150 संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज किया और 22 लोगों को गिरफ्तार किया।

उन्होंने कहा कि एफआईए ने सरकारी संस्थाओं के खिलाफ दुष्प्रचार में शामिल संदिग्धों को गिरफ्तार करने के लिए 117 छापे मारे, जिनमें से अधिकतर पंजाब में मारे गए। उन्होंने कहा कि संदिग्धों (सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं) के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम (पीईसीए) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले, अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस्लामाबाद के डी-चौक से पीटीआई समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए सरकार की घातक कार्वाई की पारदर्शी ढंग से जांच कराए जाने मांग की थी। पीटीआई समर्थक जेल में बंद अपने नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री की रिहाई के लिए एकत्र हुए थे।

वैश्विक पर्यटन से बढ़ते उत्सर्जन के लिए केवल 20 देश जिम्मेदार : नया अध्ययन

मेलबर्न। (द कन्वरसेशन) वैश्विक पर्यटन से बढ़ते उत्सर्जन के लिए लगभग पूरी तरह से जिम्मेदार 20 देश हैं, और इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के प्रयास अनुपयोगी साबित हो रहे हैं। यह हमारे नए अनुसंधान का मुख्य निष्कर्ष है, जो आज नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। यह अब तक पर्यटन उत्सर्जन का सबसे कठोर और व्यापक विश्लेषण है। अध्ययन कई आंकड़ों का एक साथ विश्लेषण करता है, जिसमें 11 वर्षों (2009-2020) में 175 सरकारों द्वारा सीधे प्रकाशित किए गए आंकड़े भी शामिल हैं। यह संयुक्त राष्ट्र-समर्थित स्थाई पर्यटन के माप ढांचे का उपयोग करता है और राष्ट्रीय स्तर पर एकत्र पर्यटन व्यय और उत्सर्जन तीव्रता के आंकड़ों को प्राप्त करता है।

व्यापक संदर्भ को देखते हुए निष्कर्षों से आगे की गंभीर चुनौतियों का पता चलता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक कुल मिलाकर वर्तमान वैश्विक उत्सर्जन के मुकाबले 42 प्रतिशत की कमी (और 2035 तक 57 प्रतिशत) की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित करने का लक्ष्य चूक जाएंगे। लेकिन वैश्विक पर्यटन उत्सर्जन वैश्विक अर्थव्यवस्था की दोगुनी दर से बढ़ रहा है। हमारे अध्ययन के मुताबिक, 2009 और 2019 के बीच, उत्सर्जन में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 2009 में 3.7 गीगाटन (वैश्विक उत्सर्जन का 7.3 प्रतिशत) से बढ़कर 2019 में 5.2 गीगाटन (वैश्विक उत्सर्जन का 8.8 प्रतिशत) हो गया।

कोविड-19 महामारी के कारण 2020-2021 में वैश्विक पर्यटन उत्सर्जन में नाटकीय रूप से कमी आई, लेकिन इसके बाद पूर्व-महामारी के स्तर पर वापसी तेजी से हुई। प्रौद्योगिकी सुधार के बिना पर्यटन-संबंधी उत्सर्जन में भारी वृद्धि हो रही है और 2009 से 2019 तक यह 3.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा। तुलनात्मक रूप से, उस अवधि में सामान्य रूप से वैश्विक आर्थिक विकास 1.5 प्रतिशत प्रति वर्ष था। यदि यह वृद्धि दर जारी रही, तो अगले दो दशकों में वैश्विक पर्यटन से उत्सर्जन दोगुना हो जाएगा। पर्यटन के लिए खर्च प्रत्एक डॉलर के मुकाबले कार्बन उत्सर्जन की दर वैश्विक अर्थव्यवस्था के औसत से 30 प्रतिशत अधिक है, और सेवा क्षेत्र की तुलना में चार गुना अधिक है। बढ़ते उत्सर्जन का प्राथमिक कारक पर्यटन मांग में उच्च वृद्धि है। तेजी से बढ़ने वाला कार्बन फुटप्रिंट मुख्य रूप से विमानन (21 प्रतिशत), पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों का उपयोग (17 प्रतिशत), और बिजली आपूर्ति (16 प्रतिशत) जैसी उपयोगिताओं से है।

प्रौद्योगिकीय दक्षता की धीमी गति की वजह से इसका लाभ मांग में वृद्धि के आगे छोटा पड़ गया है। विमानन क्षेत्र की प्रत्यक्ष पर्यटन उत्सर्जन में हिस्सेदारी करीब 50 प्रतिशत है जिससे यह वैश्विक पर्यटन उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। दशकों के वादों के बावजूद, वैश्विक हवाई परिवहन प्रणाली में नई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में कमी करना असंभव साबित हुआ है। उत्सर्जन में 20 देश सबसे अधिक जिम्मेदार हमारे अनुसंधान के मुताबिक देशों के बीच उत्सर्जन वृद्धि में चिंताजनक असमानताएं सामने आईं। 2009 और 2019 के बीच पर्यटन उत्सर्जन में 60 प्रतिशत वृद्धि के लिए केवल तीन देश अमेरिका, चीन और भारत जिम्मेदार थे। 2019 तक, ए तीन देश अकेले कुल वैश्विक पर्यटन उत्सर्जन के 39 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार थे।

कुल वैश्विक पर्यटन उत्सर्जन का तीन-चौथाई हिस्सा केवल 20 देशों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है जबकि शेष 25 प्रतिशत उत्सर्जन बाकी के 155 देश करते हैं। अब सबसे अधिक यात्रा करने वाले और सबसे कम यात्रा करने वाले देशों के बीच प्रति व्यक्ति पर्यटन कार्बन फुटप्रिंट में सौ गुना का अंतर है। शीर्ष 20 में से, अमेरिका (एक विदेशी गंतव्य के रूप में, साथ ही यात्रा करने वाले इसके नागरिकों) में 2019 में पर्यटन क्षेत्र में सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश था और इसने करीब एक गीगाटन कार्बन उत्सर्जित किया। यह कुल वैश्विक पर्यटन कार्बन उत्सर्जन का 19 प्रतिशत था जो 3.2 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। अमेरिका द्वारा 2019 में पर्यटन से उत्सर्जित कार्बन वहां के प्रति निवासी तीन टन के बराबर था। इसी के साथ वह वैश्विक स्तर पर उच्चतम प्रति व्यक्ति पर्यटन उत्सर्जन के मामले में 12वें स्थान पर है। ब्रिटेन एक गंतव्य के रूप में 128 मेगाटन (कुल का 2.5 प्रतिशत) के साथ विश्व में पर्यटन जनित कार्बन उत्सर्जन में सातवें स्थान पर है। 2019 में, ब्रिटेन के निवासियों ने प्रति व्यक्ति 2.8 टन उत्सर्जन किया। इसी के साथ वैश्विक स्तर पर इस मामले में उसका 15वां स्थान है। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन के मामले में दुनिया में 14वें स्थान पर है और वह 82 मेगाटन कार्बन उत्सर्जित करता है। 2019 में यहां के निवासी पर्यटन मद में प्रति व्यक्ति 3.4 टन (वैश्विक स्तर पर 8वां) कार्बन उत्सर्जित करते थे। यह ऑस्ट्रेलिया आने वाले और यहां से दुनिया के अन्य हिस्सों में जाने वाले के लिए लंबी दूरी की हवाई यात्रा से होने वाले उच्च उत्सर्जन को रेखांकित करता है। न्यूजीलैंड ने 2019 में प्रति व्यक्ति 3.1 टन प्रति की दर से (वैश्विक स्तर पर 10वां स्थान) पर्यटन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जित किया। ऑस्ट्रेलिया की तरह, लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर निर्भरता एक ऐसी समस्या है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर्यटन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने के तरीके पहली बार, इस साल के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी29) में पर्यटन को शामिल किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन ने हमारे अध्ययन का समर्थन किया और स्वीकार किया कि पर्यटन अब कुल वैश्विक उत्सर्जन में 8.8 प्रतिशत का योगदान देता है। इसने बताया कि सीओपी 29 एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जब महत्वाकांक्षा को मूर्त रूप मिलता है, और दृष्टि हमारे ग्रह के बेहतर भविष्य के लिए सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्धता में बदल जाती है।

ब्रिसबेन में बसे भारतीयों के लिए क्रिसमस की रौनक के बीच त्योहार से कम नहीं गाबा टेस्ट

ब्रिसबेन। लाल रंग की सजावट, संगीत की महफिलें, केक की खुशबू, सैंटा की पोशाक में बच्चे और रोशनी में सराबोर ब्रिसबेन। क्रिसमस की तैयारियां यहां जोरों पर हैं लेकिन यहां बसे भारतीयों के लिए गाबा पर उससे पहले 14 दिसंबर से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट भी किसी त्योहार से कम नहीं है। तीन साल पहले पहली बार आस्ट्रेलिया के इस गढ में मिली ऐतिहासिक टेस्ट जीत के बाद तो यहां भारतीय समुदाय इस मुकाबले को लेकर बेहद रोमांचित है। मैच के टिकट खरीदे जा चुके हैं और भारतीय रंग में रंगने के लिए संदूकों से नीली जर्सी बाहर आ चुकी है, तिरंगे मंगवाए जा चुके हैं और विराट कोहली, रोहित शर्मा तथा ऋषभ पंत के पोस्टरों का जुगाड़ किया जा रहा है। घरों में थेपले, मठरी, भाकरवड़ी और लड्डू भी बन रहे हैं जिनका लुत्फ स्टेडियम में उठाया

जाएगा। मराठी, गुजराती, पंजाबी, दक्षिण भारतीय सभी क्रिकेट के रंग में रंगे हैं।

पिछले बारह साल से ब्रिसबेन में रह रहे आईटी पेशेवर सचिन पंवार ने भाषा से कहा , हम अपने सभी भारतीय दोस्तों के साथ गाबा में मैच देखने जाएंगे। मेरे माता पिता भी महाराष्ट्र के कराड़ से आए हैं और वे भी साथ होंगे। भारतीय टीम तीन चार साल में यहां आती है और हम यही एक मैच देखने जाते हैं तो यह हमारे लिए त्योहार से कम नहीं।

उन्होंने कहा , मेरी आई (मां) ने खास तौर पर लड्डू, चकली और भाकरवड़ी बनाई है जिसका मजा हम मैच के साथ लेंगे। कुछ गुजराती दोस्त थेपला और पंजाबी परिवार मठरी लेकर आता है। हमारे लिए यह दावत से कम नहीं होता। एडीलेड में भारतीय टीम को दस विकेट से मिली हार से भी इनका उत्साह कम नहीं हुआ है चूंकि इन्हें विश्वास है कि वूलूंगाबा यानी गाबा के मैदान पर इतिहास दोहराया जाएगा। पिछली बार 2021 में खेले गए मैच की यादें अभी भी भारतीयों के जेहन में ताजा है जब आखिरी दिन 328 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने आस्ट्रेलिया को उसके गढ में 32 साल में पहली बार पराजय का सामना कराया था।

भारतीय टीम में उस समय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली समेत कई प्रमुख खिलाड़ी नहीं थे और एडीलेड में 36 रन पर आउट होने की शर्मिंदगी झेलकर टीम यहां आई थी। जीवट और जुझारूपन की नई परिभाषा लिखते हुए भारत ने यह टेस्ट जीता। पंत, चेतेश्वर पुजारा और मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन याद करके भारतीयों के चेहरे पर अभी भी चमक आ जाती है। गुजरात के पाटण से आकर यहां बसे अल्केश चौधरी ने कहा , मुझे यकीन है कि हमारी टीम एक बार फिर विषमताओं पर जीत दर्ज करेगी। पंत टीम में है और शुभमन गिल भी। सिराज जबर्दस्त आक्रामक गेंदबाज है लिहाजा यह रोमांचक मैच होगा।

अगले साल संसद के बजट सत्र में खेल विधेयक लाने के इच्छुक मांडविया

नई दिल्ली। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि सरकार संसद के बजट सत्र में खेल विधेयक लाने की इच्छुक है और कुछ मानदंडों में बदलाव करने के लिए तैयार है ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय खेल प्रशासक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में बड़ी भूमिकाएं हासिल कर सकें। मैं खेलों को नुकसान नहीं होने देना चाहता। 95 प्रतिशत लोग चाहते हैं कि खेल विधेयक आए। हां, कुछ एनएसएफ (राष्ट्रीय खेल महासंघ) की ओर से कुछ छोटी आपत्तियां हैं, जिनका हम ध्यान रखेंगे। मीडिया से बातचीत में मांडविया ने कहा, 70 वर्ष की आयु के प्रावधान में कुछ अनुच्छेद हैं जिन पर हमें विचार करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर रणधीर सिंह जैसे व्यक्ति को तालमेल बनाने के लिए 50 साल लगे। उन्होंने इतने सालों तक काम किया और अब वे एशियाई ओलंपिक परिषद (ओसीए) के अध्यक्ष बन गए हैं।

कैलिस को उम्मीद, कार्तिक के एसए20 में पदार्पण से और भारतीय लीग से जुड़ेंगे

भाषा। नई दिल्ली

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर जाक कैलिस को उम्मीद है कि एसए20 लीग में दिनेश कार्तिक के होने वाले पदार्पण से संन्यास ले चुके और भी भारतीय खिलाड़ी इस लीग से जुड़ेंगे। कार्तिक 2025 एसए20 में पार्ल रॉयल्स की ओर से खेलने के लिए तैयार हैं। वह लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनेंगे। इस साल की शुरुआत में भारतीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने के बाद वह इस टूर्नामेंट में खेलने के पात्र हैं। कार्तिक जोस बटलर की जगह रॉयल्स में शामिल हुए जिन्होंने आगामी सत्र में नहीं खेलने का फैसला किया है।

एसए20 के एंबेसडर कैलिस ने वर्चुअल बातचीत के दौरान कहा, भारत से स्तरीय खिलाड़ियों का आना शानदार है। उम्मीद करता हूं कि यह कई और भारतीयों के आने की शुरुआत होगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की मौजूदा नीति के अनुसा भारतीय खिलाड़ियों को आईपीएल सहित खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने के बाद ही विदेशी लीग में खेलने की स्वीकृति है। कैलिस ने कहा, हां, निश्चित रूप से उनका होना अच्छा होगा लेकिन स्पष्ट कारण यह है कि बीसीसीआई को अपने खिलाड़ियों का ध्यान रखना होगा इसलिए एक अच्छा संतुलन बनाना होगा। उन्होंने कहा, एसए20 ने जिस तरह से शुरुआत की है, उससे हम भाग्यशाली हैं। आईपीएल में शामिल प्रमुख फ्रेंचाइजी का समर्थन निश्चित रूप से हमारी मौजूदा लीग को पेश करने में बड़ा अंतर पैदा करता है।

कैलिस ने कहा, आईपीएल हमेशा नंबर एक पर रहेगा। लीग, खिलाड़ियों का स्तर, दर्शकों की भागीदारी – यह सब अलग स्तर पर हैं। इस समय किसी भी अन्य चीज से बहुत आगे हैं। हमारा लक्ष्य आईपीएल के जितना संभव हो सके उतना करीब पहुंचना और प्रशंसकों के लिए एक रोमांचक लीग बनाना है। कैलिस ने विवादास्पद इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर कहा कि यह एक ऑलराउंडर के विकास में बाधा डालता है। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे इम्पैक्ट प्लेयर नियम पसंद नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि यह ऑलराउंडर से दूर ले जाता है। हम दक्षिण अफ्रीका में ऑलराउंडर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और यह नियम उस भूमिका को कम करता है। इसलिए मैं इसे एसए20 में नहीं देखना चाहूंगा। दक्षिण अफ्रीका के इस पूर्व कप्तान ने चैंपियंस लीग टी20 को फिर शुरू करने के विचार का भी समर्थन किया जिसमें दुनिया भर की की फ्रेंचाइजी टीम एक साथ खेलती हैं।

गाबा की पिच में पारंपरिक गति और उछाल होगा: क्यूरेटर

ब्रिसबेन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा में होने वाले तीसरे टेस्ट मैच की पिच में पारंपरिक गति और उछाल रहने की उम्मीद है क्योंकि यह मैच क्रिसमस के बाद नहीं बल्कि गर्मियों की शुरुआत में खेला जाएगा। भारत ने अपने पिछले दौरे पर गाबा में शानदार जीत दर्ज की थी जब यहां टेस्ट मैच श्रृंखला के दूसरे हाफ में खेला गया था। ऋषभ पंत की शानदार पारी की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया में लगातार दूसरी श्रृंखला जीती। यह 1988 के बाद से मेजबान टीम की इस मैदान पर यह पहली हार थी। तब से ऑस्ट्रेलिया अपने गढ़ में वेस्टइंडीज से भी हार गया है और कोई आश्चर्य नहीं कि मेजबान टीम के खिलाड़ी गर्मियों की शुरुआत में गाबा में खेलना पसंद करते हैं, ना कि गर्मियों के अंत में। क्रिकेट.कॉम.एयू ने शनिवार से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट से पहले गाबा के क्यूरेटर डेविड सैंडर्सकी के हवाले से कहा, साल के अलग-अलग समय निश्चित रूप से इसे अलग बनाते हैं, यह थोड़ी अलग पिच हो सकती है। उन्होंने कहा, सत्र के आखिर में पिचों में थोड़ी अधिक टूट-फूट हो सकती है सत्र की शुरुआत में पिचें आमतौर पर थोड़ी नई होती हैं और उनमें थोड़ी अधिक गति और उछाल होती है। सैंडर्सकी ने कहा, आम तौर पर हम अब भी पिच को हर बार ठीक उसी तरह से तैयार करते हैं ताकि हम वह अच्छी गति और उछाल प्राप्त कर सकें जिसके लिए गाबा को जाना जाता है। हम बस हर साल की तरह गाबा का पारंपरिक विकेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एडीलेड में गुलाबी गेंद से खेले गए दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की आसान जीत के बाद पांच मैच की श्रृंखला ।-। से बराबर है। पिछले महीने घरेलू गुलाबी गेंद के मैच के पहले दिन गाबा में 15 विकेट गिरे थे और क्यूरेटर ने कहा कि सतह वैसी ही होगी। सैंडर्सकी ने कहा, हमारा लक्ष्य उसी तरह का विकेट बनाना है जहां बल्ले और गेंद के बीच अच्छा संतुलन था।

शमी का फीका प्रदर्शन, बंगाल को क्वार्टर फाइनल में बड़ौदा से मिली हार, मप्र सेमीफाइनल में

बेंगलुरू। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के फीके प्रदर्शन के कारण बंगाल को बुधवार को यहां सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में बड़ौदा से 41 रन से हार का सामना करना पड़ा। सलामी बल्लेबाज शाश्वत रावत 26 गेंद में 40 रन (एक चौका, तीन छक्के) बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे जिससे बड़ौदा ने सात विकेट पर 172 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया। शाहबाज अहमद (36 गेंद में 55 रन, तीन चौके, चार छक्के) की शानदार पारी के बावजूद बंगाल की टीम 131 रन पर सिमट गई। कप्तान हार्दिक पंड्या (27 रन देकर तीन विकेट) ने अपने तेज गेंदबाजों लुकमान मेरीवाला (17 रन देकर तीन विकेट) और अतीत शेठ (41 रन देकर तीन विकेट) के साथ मिलकर बड़ौदा को सेमीफाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। शमी का प्रदर्शन इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यह अनुभवी तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया में चल रही बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के कम से कम आखिरी दो टेस्ट के लिए भारतीय टीम में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।

इस मैच से पहले शमी ने आठ मैच में 7.8 के इकॉनमी रेट से 11 विकेट थे। लेकिन बुधवार का दिन शमी के लिए कुछ खास नहीं रहा। उन्होंने पहले ओवर में दो वाइड से शुरुआत की और अपने स्पैल के बाकी समय में अपनी गेंदबाजी में नियंत्रण में नहीं दिखे। 34 वर्षीय शमी ने दो स्पैल में लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदें फेंकी और कुछ यॉर्कर भी डालीं।

शिवालिक शर्मा (17 गेंद में 24 रन) ने लगातार दो छक्के लगाए। हालांकि एक छक्का थर्ड मैन के पीछे से निकल गया। जब बड़ौदा तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहा था तब शमी ने शिवालिक और अतीत शेठ के रूप में दो सांत्वना विकेट झटके। शमी बल्लेबाजी करने उतरे और दो गेंद खेलने के बाद भारतीय टीम के साथी हार्दिक पांड्या की गेंद पर शून्य पर आउट हो गए।

फिर बड़ौदा के तेज गेंदबाज मेरिवाला ने अपने चौथे ओवर में तीन विकेट लेकर बंगाल की पारी को पटरी से उतार दिया। उन्होंने फॉर्म में चल रहे करण लाल, कप्तान सुदीप कुमार घरामी और रितिक चटर्जी को आउट किया। शाहबाज ने बंगाल की पारी को पटरी पर लाने की कोशिश की लेकिन उन्हें किसी का साथ नहीं मिला। अलूर में दूसरे क्वार्टरफाइनल में मध्य प्रदेश ने वेंकटेश अय्यर के हरफनमौला प्रदर्शन की बदौलत सौराष्ट्र पर छह विकेट की शानदार जीत के साथ अंतिम चार में प्रवेश किया। वेंकटेश ने दो विकेट लेने के साथ 33 गेंद में नाबाद 38 रन बनाए जिससे मध्य प्रदेश ने सौराष्ट्र के सात विकेट पर 173 रन के लक्ष्य को चार गेंद रहते चार विकेट पर 174 रन बनाकर हासिल कर लिया।

मलेशियाई युगल कोच टैन किम हर दूसरे कार्यकाल के लिए भारत लौटे

नई दिल्ली। मलेशिया के युगल विशेषज्ञ कोच टैन किम हर भारत की स्टार जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के साथ फिर से जुड़ गए हैं। यह भारतीय बैडमिंटन में उनका दूसरा कार्यकाल होगा। भारतीय बैडमिंटन संघ ने 53 वर्षीय टैन को 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक तक चार साल के कार्यकाल के लिए अनुबंधित किया है। टैन ने यहां जारी विज्ञप्ति में कहा, मैं भारत वापस आकर तथा सात्विक और चिराग सहित युगल खिलाड़ियों के युवा और प्रतिभाशाली समूह के साथ काम करने का मौका पाकर बहुत खुश हूं। मैं युगल जोड़ियों का बड़ा समूह तैयार करना चाहता हूं जो विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। हैदराबाद पहुंचे टैन इससे पहले 2015 से 2019 तक भारत के युगल कोच थे। उन्होंने 2016 के ओलंपिक खेलों से पहले सात्विक और चिराग को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

क्विक न्यूज

वेस्टइंडीज ने 10 साल में पहली बार बांग्लादेश से वनडे श्रृंखला जीती

बासेटेरे (सेंट किट्स एंड नेविस)। तेज गेंदबाज जेडन सील्स के चार विकेट और सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग के आकर्षक अर्धशतक की मदद से वेस्टइंडीज ने दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बांग्लादेश को 79 गेंद शेष रहते हुए सात विकेट से हराकर तीन मैच की श्रृंखला में 20 से अजेय बढ़त बनाई। वेस्टइंडीज ने पहले बांग्लादेश को 46 ओवर में 227 रन पर आउट कर दिया और फिर 36.5 ओवर में तीन विकेट पर 230 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। यह पिछले 10 वर्षों में पहला अवसर है जबकि वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश से वनडे श्रृंखला जीती है। उसने रविवार को इसी मैदान पर खेला गया पहला मैच पांच विकेट से जीता था। तीसरा और अंतिम वनडे इसी मैदान पर गुरुवार को खेला जाएगा। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद नियमित अंतराल में विकेट गंवाए। एक समय उसका स्कोर सात विकेट पर 115 रन था। महमुदुल्लाह (62) और तंजीम हसन साकिब (45) ने यहां से 92 रन की साझेदारी करके टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। सलामी बल्लेबाज तंजीद हसन ने 46 रन का योगदान दिया। वेस्टइंडीज की तरफ से सील्स ने 22 रन देकर चार विकेट लिए। वेस्टइंडीज के लिए लक्ष्य तक पहुंचना औपचारिकता मात्र रहा। ब्रैंडन किंग और एविन लुईस ने पहले विकेट के लिए 21 ओवर में 109 रन की साझेदारी करके वेस्टइंडीज को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। किंग ने 82 रन बनाए जबकि लुईस (49) और कीसी कार्टी (45) अर्धशतक से चूक गए।

ब्रूक टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे गेंदबाजों में बुमराह नंबर एक पर कायम

दुबई। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक अपने सीनियर साथी जो रूट की बादशाहत खत्म करके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की बुधवार को जारी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए जबकि भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह गेंदबाजों और रविंद्र जडेजा ऑलराउंडरों की सूची में नंबर एक पर बने हुए हैं। पिछले सप्ताह वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने करियर का आठवां शतक बनाने वाले 25 साल के ब्रूक हालांकि अपने सीनियर साथी से केवल एक अंक आगे हैं। ब्रूक के कुल 898 रेटिंग अंक है और वह टेस्ट बल्लेबाजों में सर्वकालिक 34वीं उच्चतम रेटिंग के साथ भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर की बराबरी पर पहुंच गए है। रूट इस साल जुलाई से शीर्ष स्थान पर बने

हुए थे। तब न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन को नंबर एक स्थान से हटाया था। बुमराह ने 890 रेटिंग अंकों के साथ टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर अपना स्थान बरकरार रखा है। उनके बाद दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा (856) और ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड (851) का नंबर आता है। जडेजा ने भी 415 रेटिंग अंकों के साथ ऑलराउंडरों की टेस्ट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज 285 अंकों के साथ इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं।

लिंडे के ऑलराउंड खेल से दक्षिण अफ्रीका की पाक पर जीत

डरबन। जॉर्ज लिंडे के ऑलराउंड खेल की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने यहां खेले गए पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच मे पाकिस्तान पर 11 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 183 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम इसके जवाब में आठ विकेट पर 172 रन ही बना पाई। चुनौती पूर्ण लक्ष्य के सामने पाकिस्तान के केवल तीन बल्लेबाज कप्तान मोहम्मद रिजवान (74), सैम अयूब (31) और तैयब ताहिर (18) ही दोहरे अंक मे पहुंच पाए। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से लिंडे ने 21 रन देकर चार विकेट लिए। लिंडे ने इससे पहले 24 गेंद पर 48 रन की तूफानी पारी खेली थी जिसमे तीन चौके और चार छक्के शामिल है। उनके अलावा डेविड मिलर ने 40 गेंद पर 82 रन बनाए। उन्होने अपनी पारी मे चार चौके और आठ छक्के लगाए।

रियाल मैड्रिड ने अटलांटा को हराया, लिवरपूल का विजय जारी

मैड्रिड। रियाल मैड्रिड ने अपने तीन प्रमुख खिलाड़ियों के गोल की मदद से अटलांटा को 32 से हराकर चैंपियंस लीग फुटबाल टूर्नामेंट मे अपनी उम्मीद जीवंत रखी जबकि शीर्ष पर काबिज लिवरपूल ने अपना विजय अभियान जारी रखा। मौजूदा चैंपियन रियाल मैड्रिड की तरफ से किलियन एम्बाप्पे, विनीसियस जूनियर और जूड बेलिंगहैम ने गोल किए जिससे 15 बार का चैंपियन इस प्रतियोगिता में अपनी तीसरी जीत हासिल करने में सफल रहा। इस बीच छह बार के चैंपियन लिवरपूल ने मोहम्मद सलाह के गोल की मदद से गिरोना को 10 से हराकर शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत की। पेरिस सेंट-जर्मेन ने भी साल्ज़बर्ग को 3-0 से हराकर महत्वपूर्ण जीत हासिल की। बायर लेवरकुसेन ने इंटर मिलान को।-0 से हराया जिससे वह दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। एस्टन विला ने लीपज़िग को 3-2 से हराया और वह तीसरे स्थान पर है।

गाबा के उछाल का फायदा उठाएं, हेडन की भारतीय गेंदबाजों को सलाह

ब्रिसबेन। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने भारतीय गेंदबाजों को सलाह दी है कि वे शनिवार से यहां शुरू हो रहे बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट में चौथी और पांचवीं स्टंप लाइन को लक्ष्य बनाएं और गाबा की पिच से मिलने वाले उछाल का फायदा उठाएं। एडिलेड में गुलाबी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की शानदार जीत के बाद पांच मैचों की श्रृंखला ।-। से बराबर है। भारत ने पर्थ में पहला टेस्ट 295 रनों से जीता था। हेडन ने गाबा में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को आउट करने के तरीके पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, भारत को जब भी गेंदबाजी करने का मौका मिलता है तो उन्हें चौथी और पांचवीं स्टंप लाइन पर थोड़ा और अधिक भरोसा करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें उछाल का उपयोग करने की जरूरत है। हेडन ने कहा, ब्रिसबेन में तेज गेंदबाजी इकाई के लिए यह अहम चीज है।

ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष क्रम के सभी बल्लेबाज दबाव में हैं: वार्नर

ब्रिस्बेन। पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर का मानना है कि केवल उस्मान ख्वाजा ही नहीं बल्कि आस्ट्रेलियाई शीर्ष क्रम के सभी बल्लेबाज भारत के खिलाफ एडिलेड में जीत दर्ज करके श्रृंखला बराबर करने के बावजूद दबाव महसूस कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने के कारण आलोचकों के निशाने पर रहे मार्नस लाबुशेन ने जहां एडिलेड में जोरदार अर्धशतक के साथ फॉर्म में वापसी की वहीं सलामी बल्लेबाज ख्वाजा, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी के मुख्य आधार स्टीव स्मिथ और युवा सलामी बल्लेबाज नाथन मैकस्वीनी मौजूदा बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वार्नर ने फॉक्स क्रिकेट से कहा, मुझे लगता है कि केवल उजी (उस्मान ख्वाजा) पर ही नहीं बल्कि शीर्ष क्रम के सभी बल्लेबाजों पर दबाव है। ट्रैविस हेड ने एडिलेड में अपने घरेलू मैदान पर यादगार शतक जड़ा, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में करारी हार के बाद वापसी करते हुए पांच मैचों की श्रृंखला बराबर की।

वार्नर ने कहा, ट्रैविस ने आकर पलटवार किया और शानदार शतक बनाया और हम जानते हैं कि वह ऐसा करने में सक्षम है। लेकिन अन्य बल्लेबाजों को भी उनका अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा, विशेष रूप से यह केवल एक खिलाड़ी से जुड़ा मामला नहीं है, चोटी के सभी छह बल्लेबाजों को बड़ा स्कोर बनाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने गेंदबाजों को आराम करने का पर्याप्त मौका दे रहे हैं। पिछला मैच मिशेल स्टार्क के नाम रहा जिन्होंने हमेशा की तरह गुलाबी गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया। वार्नर ने शनिवार से ब्रिस्बेन में शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट मैच के संदर्भ में कहा, मुझे उम्मीद है कि ब्रिस्बेन में हमारे चोटी के बल्लेबाज बड़ी पारियां खेलेंगे।

स्मृति मंधाना के शतक के बावजूद हारा भारत ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से सूपड़ा साफ किया

पर्थ। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना के शतक के बावजूद भारत को तीसरे और अंतिम महिला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में बुधवार को यहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 83 रन की हार के साथ 0-3 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। अरुंधति रेड्डी (26 रन पर चार विकेट) के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी से भारत ने वाका पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर चार विकेट पर 78 रन कर दिया था लेकिन अनाबेल सदरलैंड (95 गेंद में 110 रन, नौ चौके, चार छक्के) के शतक से मेजबान टीम छह विकेट पर 298 रन का बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही। सदरलैंड ने एशलेग गार्डनर (50) के साथ पांचवें विकेट के लिए 96 और कप्तान तहलिया मैकग्रा (56) के साथ छठे विकेट के लिए 122 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। इसके जवाब में भारतीय टीम मंधाना की 109 गेंद में 14 चौकों और एक छक्के से 105 रन की पारी के बावजूद 45.1 ओवर में 215 रन

पर सिमट गई।

जब तक स्मृति क्रीज पर थी तब तक भारत की जीत की उम्मीद बंधी हुई थी लेकिन उनके आउट होने के साथ मेहमान टीम की सांत्वना जीत दर्ज करने की उम्मीद भी टूट गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ऑफ स्पिनर एशलेग ने 30 रन देकर पांच विकेट चटकाए। लेग स्पिनर एलेना किंग ने भी 27 रन देकर दो विकेट हासिल किए। मंधाना को दूसरे छोर पर अन्य बल्लेबाजों से समर्थन नहीं मिला। एलेना ने हरलीन देओल (64 गेंद में 39 रन) को अपनी ही गेंद पर लपककर मंधाना के साथ उनकी दूसरे विकेट की 118 रन की साझेदारी का अंत किया जिसके बाद टीम ने लगातार विकेट गंवाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने पांचवें ओवर में ही रिचा घोष (02) का विकेट गंवा दिया जिन्हें मेगान शूट ने बोल्ड किया।

भारत में मुझे मैच फिक्सिंग की दुनिया में धकेल दिया गया था: लू विंसेंट

वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज लू विंसेंट ने खुलासा किया है कि 2000 के दशक के आखिर में अब बंद कर दी गई इंडियन क्रिकेट लीग के दौरान वह मैच फिक्सिंग की दुनिया में कैसे आकर्षित हुए थे तथा वह एक गिरोह का हिस्सा थे जिसमें उन्हें अवसाद के दिनों में अपनेपन का एहसास होता था। न्यूजीलैंड की तरफ से 23 टेस्ट और 108 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले विंसेंट पर 2104 में मैच फिक्सिंग के लिए इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने आजीवन प्रतिबंध लगाया था। पिछले साल प्रतिबंध का दायरा कम करके उन्हें घरेलू क्रिकेट में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। इस 46 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने करियर की शुरुआत 2000 के दशक की सबसे मजबूत टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में शतक जड़कर की थी। इसके बाद हालांकि उन्हें अवसाद से जूझना पड़ा और वह मैच फिक्सिंग की दुनिया में चले गए। इस तरह से उनका अंतरराष्ट्रीय करियर 29 साल की उम्र में समय से पहले खत्म हो गया।

विंसेंट ने द टेलीग्राफ को दिए गए साक्षात्कार में बताया कि कैसे उनकी शुरुआती परवरिश ने उनके व्यक्तित्व और करियर को प्रभावित किया। उन्होंने कहा, मैं पेशेवर खिलाड़ी बनने के लिए मानसिक रूप से मजबूत नहीं था। इसलिए 28 साल की उम्र में मैं गहरे अवसाद में था और फिर भारत चला गया जहां मुझे मैच फिक्सिंग की दुनिया में धकेल दिया गया। विंसेंट ने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक गिरोह का हिस्सा हूं। इससे मुझे लगभग बेहतर महसूस हुआ, क्योंकि मैं सोच रहा था: मैं एक मैच फिक्सिंग गिरोह का हिस्सा हूं, मैं एक ऐसे समूह के साथ हूं जो मेरी पीठ थपथपाएगा और कोई भी हमारे बारे में नहीं जानता।

पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं होने के कारण विंसेंट हमेशा अपने आस-पास भावनात्मक समर्थन की तलाश में रहते थे और आखिरकार उन्हें वह सहारा भ्रष्टाचार की गंदी दुनिया में मिला। वह वर्तमान में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के संगठन की भ्रष्टाचार विरोधी शिक्षा पहल में शामिल हैं। मैंने 12 साल की उम्र से खुद का पालन पोषण किया और इसलिए मैं हमेशा अपने आसपास के लोगों के बहकावे में आ जाता था।

पहलवानों के गांव सर्फाबाद से उभरा रेसिंग का चैंपियन

नोएडा। सर्फाबाद गांव जिसे पहलवानों के गांव के रूप में जाना जाता हैए अब रेसिंग की दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। इस गांव के 13 वर्षीय शौर्य यादव ने अपनी अनोखी प्रतिभा से पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। शौर्य ने पिंक फाल्कन जयपुरए राजस्थान में आयोजित रेड रैबिट रेसर्स चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचकर शानदार प्रदर्शन कर गांव और परिवार का नाम रोशन किया।

'स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं शौर्य यादव'

शौर्य यादव का परिवार ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखता है। उनके परदादा स्वतंत्रता सेनानी थेए जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना योगदान दिया। उनके दादाए स्वर्गीय श्याम सिंह यादवए अपने समय के प्रभावशाली व्यक्तित्व थे और प्रधान तथा जिला पंचायत सदस्य के रूप में जनसेवा करते रहे।

शौर्य की माँए वर्षा यादवए वर्तमान में बदायूं से जिला पंचायत अध्यक्ष हैंए जो अपने नेतृत्व और सेवा के लिए जानी जाती हैं। उनके पिताए जितेंद्र यादवए पूर्व एमएलसी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैंए जिन्होंने राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस गौरवशाली पारिवारिक विरासत के साथए शौर्य यादव ने खेल की दुनिया में कदम रखा और अपनी मेहनत तथा दृढ़ संकल्प से न केवल अपने परिवारए बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया।

'रेड रैबिट रेसर्स चैंपियनशिप में 40 प्रतिभागियों को पछाड़ा'

पिंक फाल्कन रेड रैबिट रेसर्स चैंपियनशिप में कुल 40 प्रतिभागियों ने हिस्सा लियाए जिनमें से अधिकांश की उम्र 20 वर्ष से अधिक थी। शौर्य इस प्रतियोगिता के सबसे युवा ड्राइवर थेए लेकिन उनकी प्रतिभा और साहस ने उन्हें सबसे आगे ला खड़ा किया। चैंपियनशिप चार राउंड में आयोजित की गई थीकृक्वालीफाइंगए हीटए सेमीफाइनल और फाइनल। सेमीफाइनल में शौर्य ने 23ण्8 सेकंड के सर्वश्रेष्ठ लैप समय के साथ सभी को पछाड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया।

13 साल की उम्र में हासिल की बड़ी उपलब्धि'

शौर्य यादव ने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से साबित किया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। फाइनल में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से उन्होंने सभी को चकित कर दिया। हालांकि वे खिताब अपने नाम नहीं कर सकेए लेकिन इतनी कम उम्र में फाइनल तक पहुंचना और चैंपियनों के बीच जगह बनाना किसी जीत से कम नहीं है। शौर्य की इस उपलब्धि ने न केवल उन्हें बल्कि उनके परिवार और सर्फाबाद गांव को भी गर्व का अवसर दिया है। उनका यह प्रदर्शन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैए जो दिखाता है कि मेहनत और आत्मविश्वास से बड़ी से बड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है।

सीएमवाईके प्रिंटेक के लिए तथा उसी की ओर से मुद्रक एवं प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा द इंडियन एक्सप्रेस प्रा.लि. सी-26 अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया, नादरगंज लखनऊ से मुद्रित एवं चौथी मंजिल, सहारा शापिंग सेंटर, फैजाबाद रोड, लखनऊ (फोन: 0522-4036600) से प्रकाशित। प्रधान सम्पादक: शोबोरी गाँगुली, स्थानीय सम्पादक: विजय प्रकाश सिंह। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं।